राष्ट्रीय संस्करण

पासवान बोले, सरकार के पास है पूरे साल के लिए पर्याप्त खाद्यान्न

>> 10

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 303
मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 10 अप्रैल 2020
www.jagran.com
पृष्ठ 14

कोरोनामीटर
(स्रोत : वर्ल्डोमीटर्स डॉट इंफो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

	विश्व	अमेरिका	स्पेन	भारत	3 अप्रैल की स्थिति	दिल्ली
कुल केस	15,36,677	4,35,289	1,52,446	6,624	2,331	720
मौतें	89,907	14,818	15,238	227	73	12
स्वस्थ हुए	3,40,349	22,909	52,165	596	174	25

भारत के प्रमुख राज्य

राज्य	केस	मौतें
तमिलनाडु	834	8
तेलंगाना	453	11
राजस्थान	430	7
मध्य प्रदेश	415	2
उत्तर प्रदेश	410	7
केरल	357	7
आंध्र प्रदेश	348	4
गुजरात	262	4
अन्य	2395	165

रात 11 : 30 बजे तक

अन्य प्रमुख देश

देश	इटली	जर्मनी	फ्रांस
केस	1,39,422	1,13,296	1,12,950
मौतें	17,669	2,349	10,869

नोट : कोरोना से प्रभावित लोगों के संदर्भ में आंकड़े उल्लिखित दो स्रोतों के अतिरिक्त जागरण न्यूज नेटवर्क के रूप में अन्य माध्यमों से भी लिए गए हैं। अतः तालिका तथा दैनिक जागरण के इस अंक में प्रकाशित सामग्री में आंकड़ों का अंतर संभव है।

हेल्पलाइन नंबर

कोरोना से जुड़ी सही जानकारी देने के लिए भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों को मोबाइल में सुरक्षित करके कोई भी प्रामाणिक सूचना पाई जा सकती है। कृपया नंबर दर्ज करके वाट्सएप पर सिर्फ नमस्कार का संदेश भेजें। तुरंत एक मेन्यू आएगा, जिसके अनुसार वांछित जानकारी ली जा सकती है।

who:+41 798931892
mygov : +919013151515

कोरोना को हराना है

मुंबई के स्लम एरिया में सघन जांच अभियान शुरू • पेज 5

समझदार बने, घर में रहें और लक्ष्मण रेखा न लांघें • पेज 6

प्रियंका ने चार कोरोना फाइटर्स को दिए एक लाख डॉलर • पेज 7

महाराष्ट्र में एक दिन में 25 की मौत

संकट गहराया ▶ देशभर में संक्रमितों की संख्या 6,600 के पार, अब तक 227 की गई जान

महाराष्ट्र में 229 मामलों के साथ देश में एक दिन में 778 मरीज सामने आए

जेएनएन, नई दिल्ली

देश में कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। गुरुवार को अलग-अलग राज्यों से बेहद चिंताजनक आंकड़े सामने आए। कोरोना के कारण अकेले महाराष्ट्र में एक दिन में 25 लोगों की मौत हो गई। इससे देशभर में इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 227 पर पहुंच गया है। गुरुवार को महाराष्ट्र में 229 नए संक्रमितों के साथ देशभर में 778 नए मामले सामने आए और कुल मरीजों का आंकड़ा 6,624 पर पहुंच गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, गुरुवार शाम तक पिछले 24 घंटे में 591 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 5,865 रही। मृतकों की संख्या 169 है। आंकड़ों में अंतर को लेकर अधिकारियों का कहना है कि राज्यों की संबंधित इकाइयों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को आंकड़े मिलने में देरी के कारण यह अंतर रहता है। कई निजी एजेंसियां सीधे राज्यों से आंकड़े जुटाती हैं।

कोरोना संक्रमण के लिहाज से गुरुवार का दिन महाराष्ट्र के लिए चिंता बढ़ाने वाला रहा। यहां 24 घंटे में 229 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,364 पर पहुंच गई। अकेले मुंबई में 79 नए मरीज मिले हैं। यहां सबसे बड़ी चिंता घनी झोपड़पट्टियों में नए मामले सामने आने की है, जिससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। मुंबई के झोपड़पट्टी क्षेत्र धारावी एवं वरली कोलीवाड़ा सहित 215 क्षेत्रों को रेड जोन घोषित कर सघन जांच की जा रही है। देश में संक्रमितों के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। 96 नए मामलों के साथ यहां संक्रमितों का आंकड़ा 834 पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में भी 50 से ज्यादा नए मामलों के साथ अब तक कुल 410 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राजस्थान में भी करीब 70 नए मामलों के साथ 430 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। गुजरात में भी 76 नए मामले सामने आए और संक्रमितों का आंकड़ा 262 पर पहुंच गया है। दिल्ली में 51 नए मरीजों के साथ अब तक 720 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मृतकों के मामले में सबसे ज्यादा 97 लोगों ने महाराष्ट्र में कोरोना के कारण जान गंवाई है। अब तक मध्य प्रदेश में 30, गुजरात में 18, दिल्ली में 12, तेलंगाना में 11, पंजाब में 10 और तमिलनाडु में आठ लोगों की कोरोना के कारण मौत की पुष्टि हुई है।

मुंबई में स्थित एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती धरावी में कई कोरोना वायरस संक्रमित मिलने के बाद यहां ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे से पुलिस क्वारंटाइन किए गए लोगों पर नजर रख रही है। एपी

आइसोलेशन में रखे गए लोगों की हो रही 'जियो फेंसिंग'

नई दिल्ली : आइसोलेशन में रखे गए कोरोना संदिग्धों के लिए घर से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। आठ राज्यों में ऐसे संदिग्धों का 'जियो फेंसिंग' कर दिया गया है। जैसे ही कोई आइसोलेशन के स्थान से दूर जाएगा, उसकी निगरानी में लगी एजेंसियां सतर्क हो जाएंगी। (पेज-3)

पीपीई की उपलब्धता को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली : स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा कर्मियों के सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) व अन्य संसाधन पर्याप्त संख्या में होने की बात कही है। मंत्रालय ने कहा है कि पीपीई की उपलब्धता को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 20 घरेलू कंपनियां इसका निर्माण कर रही हैं। आर्डर दिए जा चुके हैं। (पेज-4)

ईएसआइसी के अस्पतालों में भी तैयारियां चाक चौबंद

नई दिल्ली : कोरोना से जंग के प्रयासों की कड़ी में कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआइसी) के अस्पतालों ने भी अपनी तैयारियां चाक-चौबंद कर ली हैं। ईएसआइसी के अस्पतालों ने अब तक 2200 आइसोलेशन बेड और 1200 क्वारंटाइन बेड तैयार कर उपलब्ध करा दिए हैं। (पेज-6)

कोरोना से जंग का पूरा खर्च उठाएगा केंद्र

▶ 15 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का एलान, राज्यों से अपनी-अपनी जरूरतें बताने के लिए कहा गया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज और इससे निपटने की तैयारियों का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इसके लिए केंद्र ने राज्यों के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज का एलान किया है। राज्य सरकारें इस फंड का इस्तेमाल एन-95 मास्क, वेंटिलेटर, पीपीई, एंबुलेंस और दवाइयां खरीदने से लेकर अस्पतालों और टेस्टिंग लैब के साथ अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए कर सकती हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, यह कोरोना के खतरे से निपटने के लिए राज्यों को दिया जाने वाला 100 फीसद केंद्रीय सहायता का पैकेज है। यानी इस फंड के इस्तेमाल के लिए राज्यों को अपनी तरफ से कोई धन नहीं देना पड़ेगा। कई योजनाओं में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी तय होती है, जिसके अनुसार राज्य अपने हिस्से का धन देने के बाद ही केंद्रीय फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अग्रवाल ने कहा, गुरुवार को ही सभी राज्यों को इस पैकेज के बारे में बता दिया गया है और कोरोना से निपटने के लिए उन्हें अपनी-अपनी जरूरतें बताने को कह दिया गया है। तैयारियों में मदद के लिए केंद्र की ओर से विशेषज्ञों की 10 टीमें नौ राज्यों में भेजी गई हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस पैकेज में से लगभग आधे 7,774 करोड़ रुपये का इस्तेमाल राज्य सरकारें तत्काल कोरोना से लड़ने के लिए आपातकालीन सेवाओं पर कर सकती हैं। शेष राशि का इस्तेमाल एक से चार साल के बीच राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर आधारभूत संरचना तैयार करने पर किया जाएगा। पैकेज का उद्देश्य यह है कि धन के अभाव में किसी भी राज्य में कोरोना के मरीजों के इलाज में कोई कमी नहीं रहे और इसके फैलने से रोकने की तैयारियों पर कोई असर नहीं हो। लेकिन इसका दूरगामी उद्देश्य राज्यों में अस्पतालों और लैबोरेटरी समेत स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी आधारभूत संरचना का निर्माण करना है ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से आसानी से निपटा जा सके। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को ही एलान किया था कि केंद्र सरकार कोरोना से लड़ाई के लिए 15 हजार करोड़ रुपये से इसकी टेस्टिंग से लेकर इलाज तक पूरी संरचना का निर्माण करेगी।

लव अग्रवाल के अनुसार इस फंड का उपयोग राज्य सरकारें कोरोना से लड़ने के लिए सभी जरूरी चीजों के लिए कर सकती हैं। राज्य सरकारें इससे पीपीई, एन95 मास्क, वेंटिलेटर या कोई और अन्य सामान खरीद सकती हैं। साथ ही वे सामुदायिक निगरानी के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्पतालों के उन्नयन और एंबुलेंस खरीदने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

मानवता को बचाने के लिए सब कुछ करेगा भारत : मोदी

नई दिल्ली : कोरोना महामारी में संजीवनी समझी जाने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात की मंजूरी देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धन्यवाद के जवाब में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा, भारत कोविड-19 से लड़ाई में मानवता की मदद के लिए हरसंभव मदद करेगा। भारत ने दूसरे देशों को एचसीक्यू की आपूर्ति शुरू कर दी है। (पेज-3)

सरोकार

कोरोना से लड़ने को दान कर दी जीवनभर की पूंजी

चमोली : उत्तराखंड के चमोली जिले के गौचर गांव की निवासी 60 वर्षीय देवकी भंडारी ने कोरोना से लड़ने के लिए जीवनभर की पूंजी दान कर दी। देवकी ने पीएम केयर फंड के लिए दस लाख का चेक जमा कराया है। (पेज-7)

जागरण विशेष

फिर मुस्कुराएगा इंडिया, गुनगुना रहा देश...

पटना : बिहार के एक युवक का लिखा गीत- फिर मुस्कुराएगा इंडिया...। प्रधानमंत्री को बहुत पसंद आया। उन्होंने ट्वीट किया-फिर जीत जाएगा इंडिया...। पीएम की तरह ही लाखों लोगों को यह गीत खूब पसंद आ रहा है। (पेज-7)

न्यूज गैलरी

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

सारे सुधारों को चुनौती दे रही कोरोना महामारी : आरबीआइ

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने गुरुवार को जारी मोनेटरी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना पिछले कई माह से चलाए जा रहे आर्थिक सुधारों को चुनौती देती दिख रही है। कोरोना से पहले अर्थव्यवस्था में सब कुछ बढ़िया था।

अंतराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कोरोना को सियासी मुद्दा बना दिया : ट्रंप

वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) प्रमुख टीए घेब्रेयसस ने चीन का पक्ष लेकर कोरोना को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोकने की भी बात कही।

ओडिशा में 30 तक बढ़ा लॉकडाउन

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए ओडिशा सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस तरह लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा करने वाला ओडिशा पहला राज्य बन गया है। वहीं, कर्नाटक सरकार भी लॉकडाउन की अवधि 15 दिन बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विचार-विमर्श करके इस संबंध में फैसला लेंगे।

ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही केंद्र सरकार से भी इसकी अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है।

मुख्यमंत्री ने ओडिशा के लिए 30 अप्रैल तक ट्रेन एवं हवाई सेवा को भी बंद रखने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। इसके साथ ही 17 जून तक राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का निर्णय भी लिया गया है।

▶ मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लिया फैसला

▶ देशभर में अवधि बढ़ाने के लिए भी की केंद्र से सिफारिश

नवीन पटनायक फाइल फोटो

ममता ने दिए संकेत, बंगाल में भी बढ़ाई जा सकती है अवधि

कोलकाता : बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को संकेत दिए कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक होनी है, इसके बाद ही लॉकडाउन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

कर्नाटक भी 15 दिन बढ़ाने के पक्ष में, सीएम आज करेंगे पीएम से बात

कर्नाटक में कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने बताया कि कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए उनके सभी कैबिनेट सहयोगियों ने सर्वसम्मति से लॉकडाउन की अवधि करीब 15 दिन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। लेकिन हम शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से विचार-विमर्श करने और अन्य राज्यों के हालात देखने के बाद इस पर कोई फैसला करेंगे कि लॉकडाउन में ढील दी जाए अथवा नहीं। बता दें कि कर्नाटक में लॉकडाउन से निकलने की रणनीति बनाने के लिए बनाई गई स्वास्थ्य विशेषज्ञों की समिति ने बुधवार को अपनी सिफारिशें मुख्यमंत्री को सौंप दी थीं। इसमें कुछ छूट के साथ हॉटस्पॉट पर लॉकडाउन को जारी रखने, सभी स्कूल-कॉलेजों को 31 मई तक बंद रखने और सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध जारी रखने की सिफारिश की गई है। निजी वाहनों के लिए इसमें ऑड-ईवन लागू करने का सुझाव दिया गया है।

सांस के गंभीर रोगियों में कोरोना ने बढ़ाई चिंता

आइसीएमआर का अध्ययन : कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में पहुंचने के संकेत

नीलू रंजन, नई दिल्ली

कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में पहुंचने के शुरुआती संकेत मिलने लगे हैं। आइसीएमआर के ताजा अध्ययन में सामने आया है कि सांस से संबंधित बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित हर 100 मरीजों में लगभग दो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। दिल्ली में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है। यहां हर 100 मरीज में पांच से अधिक कोरोना से ग्रसित मिले हैं, जबकि महाराष्ट्र में चार फीसद और उत्तर प्रदेश में डेढ़ फीसद मरीज कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं।

कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंचने का पता लगाने के लिए आइसीएमआर (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रीसर्च) ने सांस से संबंधित बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित ऐसे मरीजों की कोरोना वायरस की जांच शुरू की, जो देश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में आइसीयू में भर्ती हैं।

15 फरवरी से शुरू किए गए इस अध्ययन में 14 मार्च तक 859 मरीजों का कोरोना टेस्ट किया गया, लेकिन इसमें कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। लेकिन 15 मार्च के बाद हुए टेस्ट में कोरोना के मरीज मिलने शुरू हो गए। 15 से 21 मार्च के बीच कुल 109 मरीजों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें दो कोरोना पॉजिटिव निकले। 22 से 28 मार्च के बीच 2877 मरीजों में 48 और 29 मार्च से दो अप्रैल के बीच 2069 मरीजों में 54 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले। सबसे बड़ी बात यह है कि 29 मार्च से दो अप्रैल के बीच प्रति 100 मरीजों में कोरोना के 2.6 फीसद मरीज कोरोना पॉजिटिव थे। इस तरह 15 फरवरी से दो अप्रैल तक कुल 5911 मरीजों में 104 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले।

सांस की बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित हर 100 मरीज में लगभग दो मरीजों का कोरोना पॉजिटिव मिलना इसके कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में पहुंचने का पहला संकेत है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें 40 फीसद मरीजों की ट्रेवल या कोरोना मरीज के संपर्क में आने की कोई हिस्ट्री नहीं है।

अध्ययन में दिल्ली में 277 मरीजों का टेस्ट किया गया, जिनमें 14 कोरोना पॉजिटिव मिले। उत्तर प्रदेश में 295 मरीजों में चार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आइसीएमआर ने सरकार को इस अध्ययन के आधार पर कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को केंद्रित करने को कहा है ताकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में पहुंच चुके स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा सके।

चिंताजनक तस्वीर

तिथि	आइसीयू में टेस्ट	कोरोना+
14 मार्च तक	859	0
21 मार्च तक	109	2
28 मार्च तक	2877	48
दो अप्रैल तक	2069	54

हॉटस्पॉट के इंफ्लुएंजा मरीजों की भी होगी जांच

नई दिल्ली : देश में कोरोना के मामलों में आई तेजी के मद्देनजर आइसीएमआर ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। परिषद ने गुरुवार को कहा, अब हॉटस्पॉट या क्लस्टर इलाकों और विस्थापित केंद्रों पर ऐसे लोगों की भी कोरोना संक्रमण जांच की जाएगी जिनमें बुखार, खांसी, खराश या नाक बहने जैसे एंफ्लुएंजा के लक्षण होंगे। यह जांच बीमारी के सात दिन के भीतर और बीमारी के सात दिन बाद कराई जाएगी। (पेज-5)

जीत की राह

जब दुनिया एक वायरस से जूझ रही है तब राजस्थान के एक जिले ने पेश की मिसाल, एक समय पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या हो गई थी 27, बेहतर मैनेजमेंट और दृढ़ इच्छाशक्ति से हराया महामारी को

देश के लिए सबक है कोरोना मुक्त हुआ भीलवाड़ा

नरेन्द्र शर्मा, जयपुर

जब समूची दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है तब राजस्थान के भीलवाड़ा जिले ने मिसाल पेश की है। बेहतर मैनेजमेंट व दृढ़ इच्छाशक्ति की बदौलत जिला कोरोना मुक्त हो गया है। एक समय था, जब यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 27 तक पहुंच गई थी, मगर गुरुवार को यह आंकड़ा तीन रह गया। अब इनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। जिले में अब कोरोना पीड़ित एक भी व्यक्ति नहीं है। भीलवाड़ा ने जिस तरह कोरोना पर नियंत्रण पाया है, उसके बाद देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी भीलवाड़ा मॉडल की मांग बढ़ी है। उधर, गुरुवार रात एक व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण देखे गए हैं, मगर वह कोरोना ग्रसित है या नहीं, यह रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।

मार्च के तीसरे हफ्ते में भीलवाड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या एक साथ बढ़ी थी। यहां 27 पॉजिटिव केस मिले तो राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक चिंतित हो गई। लेकिन, करीब 20 दिन के बेहतर मैनेजमेंट के बाद जिला कोरोना मुक्त हो गया है। भीलवाड़ा के डीएम राजेंद्र भट्ट ने दैनिक जागरण को बताया कि कोरोना पीड़ित 27 में से दो की मौत हो गई थी। शेष 25 इलाज के बाद ठीक हो गए। इनमें 15 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, बाकी को जल्द घर भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा,, शहर में महाकर्फ्यू और बढ़ाया जाएगा।

महाकर्फ्यू के दौरान सुनसान नजर आ रहा भीलवाड़ा शहर। सौ. जिला जनसंपर्क अधिकारी

दिल्ली और उत्तर प्रदेश ने अपनाया मॉडल : प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि कोरोना पर काबू पाने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों व 225 जिलाधिकारियों को भीलवाड़ा मॉडल का प्रजेंटेंशन भेजा गया था। दिल्ली व उत्तर प्रदेश ने इसे अपनाते हुए कोराना प्रभावित क्षेत्रों को सील कर दिया है। शारीरिक दूरी को लेकर गाइडलाइन जारी की। वहां भी घर-घर स्क्रीनिंग की जा रही है।

कई देशों ने मांगी जानकारी : राज्य में चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह से अमेरिका, दुबई और फ्रांस से कई सरकारी प्रतिनिधियों एवं प्रवासी भारतीयों ने संपर्क कर भीलवाड़ा मॉडल की जानकारी मांगी है। उक्त देशों के कई प्रतिनिधियों ने सिंह से टेलीफोन एवं ईमेल के माध्यम से संपर्क किया है। सिंह का कहना है कि भीलवाड़ा की तरह पूरे प्रदेश को शीघ्र ही कोरोना मुक्त कर देंगे।

ऐसे पाया वायरस पर काबू

- स्थिति पर काबू पाने व तत्काल फैसला लेने को डीएम राजेंद्र भट्ट का मुख्यमंत्री से सीधा संपर्क रहा
- जब हालात बिगड़ने लगे तो शहर में महाकर्फ्यू लगा दिया गया, जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गईं
- मेडिकल टीम के अलावा किसी को शहर में प्रवेश नहीं दिया गया। राशन की आपूर्ति जिला प्रशासन ने की
- घर-घर सर्वे किया गया और लाखों लोगों की स्क्रीनिंग की गई
- करीब 1500 लोगों को होम आइसोलेट किया गया, घरों के बाहर जवान तैनात कर दिए गए
- क्वारंटाइन करने के लिए सभी होटल, गेस्ट हाउस, अस्पताल व हॉस्टल को अधिग्रहित कर लिया गया।
- शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया गया
- कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने के लिए सख्ती की गई, नतीजन शहर में मरीजों का आंकड़ा नहीं बढ़ा

अब 14 अप्रैल तक बदल सकेंगे जेईई मेंस की परीक्षा का केंद्र

▶ परीक्षार्थियों की गुहार पर निशंक ने समय सीमा बढ़ाने के दिए थे निर्देश

▶ जेईई मेंस की परीक्षा पहले ही मई के अंतिम सप्ताह तक बढ़ा दी गई है

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जेईई मेंस की परीक्षा की तैयारी में जुटे परीक्षार्थियों के लिए यह राहत देने वाली खबर है। अब वह 14 अप्रैल तक अपने परीक्षा केंद्र में बदलाव और आवेदन से जुड़ी गलतियों को ठीक कर सकेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने इसके लिए तय समय सीमा अब 14 अप्रैल शाम पांच बजे तक बढ़ा दी है। एजेंसी ने समयसीमा बढ़ाने का फैसला छात्रों की ओर से आ रही मांग के बाद लिया है।

छात्रों की मांग को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एनटीए से जरूरी कदम उठाने को कहा था। इस पर एनटीए ने गुरुवार को जेईई-मेंस के परीक्षा केंद्रों में बदलाव और आवेदन से जुड़ी गलतियां ठीक करने के लिए और समय दे दिया। छात्रों को यह सुविधा 14 अप्रैल शाम पांच बजे तक मिलेगी। जिन छात्रों को परीक्षा केंद्र में बदलाव या आवेदन से जुड़ी गलतियां सुधारनी हैं वे इस समयसीमा में कर सकते हैं। इससे पूर्व एनटीए ने जेईई मेंस की अप्रैल में प्रस्तावित परीक्षा स्थगित कर मई के अंतिम सप्ताह तक बढ़ा दी थी। हालांकि इसके लिए तारीखों का एलान 14 अप्रैल को लाकडाउन खत्म होने के बाद स्थिति की नए सिरे से समीक्षा के बाद ही किया जाएगा।

पीसीएस मेंस 2019, आरओ/एआरओ प्री 2016 की परीक्षा स्थगित पेज>>12

86 एयर इंडेक्स दर्ज किया गया गुरुवार को राजधानी का। फरीदाबाद में यह आंकड़ा 103, गाजियाबाद में 86, ग्रेटर नोएडा में 92, गुरुग्राम में 96 और नोएडा में 80 दर्ज किया गया।

शारीरिक दूरी का रख रहे ध्यान

कोरोना के चलते देशभर में लॉकडाउन के दौरान आसफ अली रोड पर एक साथ शारीरिक दूरी का ध्यान रखकर निजी संस्थाएं कुछ इस तरह भरपेट भोजन प्रतिदिन करा रही है। ध्रुव कुमार

डीएसजीपीसी क्वारंटाइन सेंटर के लिए अस्पताल देने को तैयार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) ने दिल्ली सरकार को गुरु हरकिशन अस्पताल और गुरु हरकिशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में क्वारंटाइन सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सरकार को पत्र भी लिखा है।

उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इससे निपटने के लिए होटल व अन्य स्थानों को आइसोलेशन केंद्र में परिवर्तित किया जा रहा है। इस हालात में कमेटी 50 बिस्तर वाले गुरु हरकिशन अस्पताल को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली सरकार को देने के लिए तैयार है। गुरुद्वारा बाला साहिब परिसर में स्थित आइसीयू सहित अन्य जरूरी सुविधाएं हैं। इसके साथ ही 500 बिस्तरों वाला गुरु हरकिशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस व रिसर्च सेंटर भी लगभग तैयार है। सरकार चाहे तो इसका भी उपयोग क्वारंटाइन सेंटर के रूप में कर सकती है। उन्होंने कहा कि मानव जाति इस समय मुश्किल दौर में है।

राजस्व को लगी कोरोना की काली नजर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

लॉकडाउन का दिल्ली सरकार के राजस्व वसूली पर भी असर पड़ा है। यहां तक कि बढ़त बना रहा आंकड़ा पिछले साल की अपेक्षा भी पिछड़ गया है। हालात को देखते हुए अगले एक-दो महीने में भी सरकार को मिलने वाले राजस्व में भारी कमी की आशंका है। ऐसे में सरकार के निर्धारित विकास कार्यों पर भी इसका असर पड़ सकता है।

दिल्ली सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में अपना बजट 65 हजार करोड़ का रखा है, जो प्रमुख रूप से जीएसटी और आबकारी विभाग से टैक्स के रूप में मिलने वाले राजस्व पर निर्भर है। लॉकडाउन के चलते इस समय सब कुछ ठप पड़ा है। स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मार्च में भी राजस्व वसूली में गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2019-20 में दिल्ली सरकार के जीएसटी कलेक्शन में निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। फरवरी 2020 के मुकाबले मार्च 2020 में कलेक्शन 14 फीसद और मार्च 2019 के मुकाबले 12 फीसद घटा है। इसे कोरोना वायरस के आर्थिक गतिविधियों पर असर के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले महीनों के जीएसटी वसूली के आंकड़ों को और प्रभावित कर सकता है।

दिल्ली सरकार को वित्त वर्ष 2019-20 में जीएसटी के तौर पर लगभग 22,085 करोड़ रुपये मिले हैं, जो 2018-19 में आए 19,920 करोड़ रुपये से लगभग 11 फीसद ज्यादा हैं। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2019-20 के बजट में करीब 23 हजार करोड़ रुपये जीएसटी संग्रह का लक्ष्य रखा था, जो अंतरिम आंकड़ों के आधार पर पूरा नहीं हो सका।

मार्च में मिला 1,630 करोड़ रुपये जीएसटी : आम तौर पर मार्च में टैक्स कलेक्शन अन्य महीनों के मुकाबले ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते विश्वभर की अर्थव्यवस्था में मची हलचल का असर साफ दिखाई देता है। मार्च 2020 में दिल्ली सरकार को लगभग 1,630 करोड़ रुपये जीएसटी मिला है, जो मार्च 2019 में प्राप्त 1,860 करोड़ से 12 फीसद कम है, जबकि फरवरी में आए 1,918 करोड़ से 14 फीसद कम है।

आबकारी को भी कम मिला राजस्व : इसी तरह आबकारी विभाग को भी मार्च में कम टैक्स मिला है। मार्च के लिए जितना टैक्स फिक्स किया गया था, उसमें करीब 5 सौ करोड़ की कमी हुई है। दिल्ली सरकार को फरवरी 2020 तक एक्साइज से कुल 4670 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था और लॉकडाउन से पहले 5028 करोड़ रुपये राजस्व के रूप में मिल चुके थे, जबकि पिछले साल सरकार को 5 हजार करोड़ का राजस्व आबकारी से मिला था। विभाग का मानना है कि मार्च 2020 में आबकारी से मिलने वाला राजस्व 55 सौ करोड़ से ज्यादा होता।

इस महीने भी घट सकता है राजस्व : दिल्ली सरकार ने 2020-21 के लिए आबकारी विभाग से 63 सौ करोड़ के राजस्व का टारगेट रखा है। लेकिन अप्रैल 2020 के राजस्व में और कमी आ सकती है। आप ट्रेड विंग के संयोजक बृजेश गोयल कहते हैं कि कोरोना का असर निश्चित रूप से मार्च से साथ-साथ अप्रैल के जीएसटी कलेक्शन पर भी पड़ेगा।

न्यूज गैलरी

लॉकडाउन के उल्लंघन में 190 एफआइआर

नई दिल्ली : लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने 190 एफआइआर दर्ज कीं। वहीं 3954 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये वे लोग थे, जो बिना कारण घर से बाहर सड़कों पर निकल आए थे। बिना वजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों में से 481 लोगों के वाहनों को भी पुलिस ने जब्त किया। इसके अलावा पुलिस की तरफ से 872 मूवमेंट पास ऑनलाइन जारी किए गए। इन लोगों को मूवमेंट पास आवश्यक कार्य के लिए जारी किए गए। दिल्ली पुलिस द्वारा लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में यह कारवाई गुरुवार शाम पांच बजे तक की गई। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दिल्ली पुलिस विभिन्न माध्यमों से लोगों को इस बात के लिए जागरूक भी कर रही है कि वे घरों से न निकलें। (जासं)

25 गर्भवती महिलाओं को पीसीआर ने पहुंचाया अस्पताल

नई दिल्ली : लॉकडाउन के कारण सार्वजनिक और निजी वाहनों के न चलने के कारण पीसीआर कर्मी गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने का भी कार्य कर रहे हैं। बुधवार को पीसीआर ने विभिन्न हिस्सों से 25 गर्भवती महिलाओं को प्रसव पीड़ा के चलते अस्पताल पहुंचाया। लॉकडाउन से लेकर आठ अप्रैल तक पीसीआर 236 गर्भवती महिलाओं को समय से अस्पताल पहुंचा चुकी है। डीसीपी शरत कुमार सिन्हा ने बताया कि सार्वजनिक परिवहन और ऑटो व टैक्सी बंद होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर लोगों को कुछ दिक्कतें हो रही हैं। ऐसी स्थिति में पीसीआर कर्मी बेहतर कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के मामले में सूचना मिलते ही पीसीआर पहुंच रही है। (जासं)

राशन लेने में परेशानी दूर करे सरकार : भाजपा

नई दिल्ली : भाजपा ने दिल्ली सरकार से उन गरीबों की परेशानी दूर करने की मांग की है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, वे लोग ऑनलाइन आवेदन करके उसकी पर्ची से राशन प्राप्त कर सकते हैं। भाजपा का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन करने में लोगों को परेशानी हो रही है। संबंधित विभाग की वेबसाइट में दिक्कत है। सरकार इस परेशानी को शीघ्र दूर करे जिससे कि संकट के समय में गरीबों को राशन मिल सके। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर समस्या हल करने की मांग की है। उनका कहना है कि लाखों लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि सरकार द्वारा जारी लिंक नहीं खुल रहा है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 768 करोड़ रुपये का राशन उपलब्ध कराया है। (जासं)

ऑपरेशन शील्ड से रोका जाएगा कहर

सख्ती ▶ कोरोना के केस पाए जाने वाले 21 इलाकों में लागू किया कंटेंनमेंट

सीएम बोले, किसी डॉक्टर या नर्स के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं, सख्त सजा मिलेगी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना का कहर थामने के लिए ऑपरेशन शील्ड को बड़े पैमाने पर चलाने का निर्णय लिया है। जिन 21 इलाकों में कंटेनमेंट (सील) लागू किया गया है, वहां इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के अधिक केस मिलने पर दिल्ली के 21 इलाकों में कंटेनमेंट लागू किया गया है। अब उस एरिया में किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। सभी जरूरत की वस्तुएं घर पर पहुंचाई जाएंगी। साथ ही ऑपरेशन शील्ड के तहत कोरोना से निपटा जाएगा।

वहीं सीएम ने अस्पताल से घर लौट रहे दो डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर संतुष्टि जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी दी है कि इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद ने कहा कि डॉक्टर और नर्स अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कड़ी चेतावनी देता हूं कि किसी भी डॉक्टर के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करता है, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। जो इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी इतनी गंदी हरकत करते हैं।

ऑपरेशन शील्ड का ऐसे हो रहा संचालन : मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में 21 ऐसे इलाके चिह्नित किए गए हैं, जिनमें कंटेनमेंट (शील्ड) लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जहां पर कुछ मरीज मिलते हैं, उस एरिया को हम सील कर देते हैं। एक तरह से वहां पर ऑपरेशन शील्ड चला दिया। शील्ड में 6 अक्षर हैं। 'एस' का मतलब सील कर दिया। उस एरिया के लोग बाहर नहीं जाएंगे और न कोई अंदर जाएगा।

'एच' का मतलब होम क्वारंटाइन है। उस एरिया के लोग अपने-अपने घर में ही रहेंगे। 'आई' का मतलब आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग है। जिन लोगों को कोरोना मिला है, उनको कमरे के अंदर आइसोलेट किया जाता है। वे पिछले दिनों में कहां-कहां घूमे, यह सीसीटीवी और मोबाइल फोन के जरिये पता करके उन सभी लोगों को चिह्नित किया जाता है। 'ई' का मतलब एसेंशियल सप्लाई है। उस इलाके के अंदर रहने वाले लोगों को जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति डोर-टू-डोर की जाती है। 'एल' का मतलब लोकल सैनिटाइजेशन है। उस पूरे एरिया को सैनिटाइज कर दिया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'डी' का मतलब डोर-टू- डोर चेकिंग है। एक-एक घर के अंदर जाकर यह पूछा जाता है कि आपके घर में कोई बीमार तो नहीं है। किसी को खांसी, बुखार, सांस लेने में या शरीर में कोई दिक्कत तो नहीं है। एक-एक घर के अंदर जाकर पता करने की कोशिश की जाती है कि किसी को कोरोना के लक्षण तो नहीं हैं।

अरविंद केजरीवाल। (फाइल)

घर से बाहर निकलने के दौरान सभी को मास्क पहनना अनिवार्य : मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि बुधवार को हम लोगों ने आदेश दिए हैं कि जब भी कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा या किसी मीटिंग में जाएगा, तो उसे मास्क पहनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मास्क बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। आप धुला हुआ कपड़ा या रूमाल को भी मास्क में इस्तेमाल कर सकते हैं।

लॉकडाउन के चलते सरकार को टैक्स आना लगभग बंद : मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कल एक और आदेश पारित किया है। लॉकडाउन की वजह से कोई भी गतिविधि नहीं चल रही है। कोरोना से संबंधित जैसे मुफ्त राशन बांट रहे हैं और खाना खिला रहे हैं, इन सब के अलावा कोई और खर्चा नहीं किया जाएगा। आगे हमें और भी कटौती करेंगे, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में हम सभी लोगों को कुर्बानी करनी पड़ेगी।

राशन वितरण में आ रही दिक्कतों को दूर कर देंगे : मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बताया था कि 71 लाख लोगों को राशन दे रहे हैं। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था, अब उन लोगों को भी राशन देना शुरू कर दिया है। इसकी पूरी व्यवस्था अचानक बनानी पड़ी है। इसलिए फील्ड में थोड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि स्कूल में राशन बांट रहे हैं। स्कूल के शिक्षक और प्रधानाचार्य राशन का वितरण कर रहे हैं। मैं सभी स्कूल के शिक्षक और प्रधानाचार्य को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका यह काम नहीं था, लेकिन वे लोग यह काम कर रहे हैं। इसमें अभी कई दिक्कतें आ रही हैं और दो-चार दिन में सभी दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। सभी लोगों को थोड़ा सब्र करना होगा।

जीबी पंत में नहीं होगा कोरोना का इलाज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने जीबी पंत सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को कोविड अस्पतालों की सूची से बाहर कर दिया है। अब यहां पहले की तरह हार्ट, न्यूरो, लिवर व गैस्ट्रोलॉजी की अन्य बीमारियों का इलाज होगा। इस बाबत गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इस अस्पताल में कोरोना के लिए आरक्षित 500 बेड की जगह अब लोकनायक अस्पताल में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जाएगी।

स्वस्थ्य विभाग ने लोकनायक, जीबी पंत व राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को कोविड अस्पताल घोषित किया था। इन अस्पतालों में दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज बंद कर दिया गया था। साथ ही इन अस्पतालों के मरीजों को दूसरे सरकारी और निजी अस्पतालों में स्थानांतरित करने का फैसला हुआ था। लोकनायक अस्पताल से काफी संख्या में मरीज दूसरे अस्पतालों में रेफर किए जा चुके हैं। जीबी पंत सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में हार्ट, न्यूरो व गैस्ट्रोलॉजी से संबंधित बीमारियों के इलाज की बेहतर सुविधा है। इसे कोविड अस्पताल घोषित होने से हार्ट, न्यूरो व लिवर के मरीजों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही थीं। अस्पताल के कई चिकित्साधिकारी भी इसे कोविड अस्पताल बनाने के फैसले से सहमत नहीं थे। इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसे कोविड अस्पतालों की सूची से अलग रखने का फैसला किया है। इससे अब यहां पहले की तरह इमरजेंसी में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं ओपीडी में भी सिर्फ जरूरी मरीज ही देखे जाएंगे।

लोकनायक अस्पताल में ही अब कोरोना के मरीजों के लिए 2000 बेड की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक और मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान के नवनिर्मित ब्लॉक में आइसोलशन वार्ड बनाया जाएगा।

चार और हॉटस्पॉट हुए सील

नई दिल्ली : राजधानी में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने चार और हॉटस्पॉट को सील कर दिया है। दिल्ली में कुल 25 जगहों को सील किया गया है। इन जगहों पर कोई भी व्यक्ति आवाजाही नहीं कर सकता। दिल्ली सरकार से मिली जानकारी के अनुसार जिन 4 अन्य जगहों को सील किया गया है उसमें लक्ष्मी नगर में गली नंबर 4 अनार वाली मस्जिद, जीटीबी एंक्लेव में जे, के, एल और एच ब्लॉक दिलशाद गार्डन, सीमापुरी में एफ 170 से 90 (दिलशाद कॉलोनी), विवेक विहार में प्रताप खंड झिलमिल कॉलोनी को सील किया गया है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली सरकार ने 21 जगहों को सील कर दिया था।

जन सरोकार

कोरोना से बचाव के लिए खाली समय में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल की पुत्री आरुषि निशंक (बीच में) लोगों को मुफ्त में बांटने के लिए खादी के मास्क बनाते हुए साथ में स्पर्श गंगा टीम की सदस्य। सौ. स्पर्श गंगा टीम

जल्द शुरू होगी रैपिड टेस्टिंग : सत्येंद्र जैन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस को व्यापक स्तर पर फैलने से रोकने के लिए रैपिड टेस्टिंग जल्द ही शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की सबसे पहले टेस्टिंग कोविड-19 अस्पतालों में की जाएगी। जैन ने कहा कि एक लाख टेस्टिंग किट जल्द आने वाली हैं। किट आते ही सबसे पहले तब्लीगियों का टेस्ट किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों एलान किया था कि दिल्ली में एक लाख कोरोना की टेस्टिंग की जाएगी। फिलहाल रोजाना 500 लोगों की टेस्टिंग की जाती है।

ग्रीष्मावकाश में काम करेगा दिल्ली हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कोविड-19 के खतरे को देखते हुए महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के कारण प्रतिवादियों को हो रही असुविधा को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रीष्मावकाश रद कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेश के तहत हाई कोर्ट के साथ ही सभी निचली अदालतें भी ग्रीष्मावकाश में पूरे जून खुली रहेंगी। यह फैसला हाई कोर्ट के सभी न्यायमूर्तियों की तरफ से लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हो रही हैं और हाई कोर्ट से लेकर निचली अदालत का कार्यसमय बर्बाद हुआ। अब इसकी भरपाई करने के लिए यह निर्णय लिया गया है, ताकि अदालत की कार्यप्रणाली को जल्द से जल्द सामान्य स्थिति पर लाया जा सके।

दिल्ली हाई कोर्ट का काम मार्च के दूसरे सप्ताह से काफी कम हो गया था और मामले से जुडे एक ही अधिवक्ता को आने की अपील की गई थी। इसके बाद 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद से हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से हो रही है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर निचली अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हो गए हैं और अदालत का काम प्रभावित हो रहा है।

बंगाली मार्केट में मिले तीन संक्रमित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

लुटियंस दिल्ली की प्रसिद्ध बंगाली मार्केट में तीन लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। वहीं जांच के दौरान एक पेस्ट्री शॉप के पीछे स्थित घर की छत पर 35 मजदूर काम करते मिले। इसमें दो संदिग्धों को क्वारंटाइन करने के साथ ही पेस्ट्री शॉप के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित पेस्ट्री शॉप मालिक डॉक्टर हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

बंगाली मार्केट के बाबर रोड के एक मकान में सोमवार को तीन लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसलिए जिला प्रशासन के साथ दिल्ली पुलिस और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एनडीएमसी) की टीम डोर टू डोर सर्वे कर रही थी। इस दौरान बंगाली पेस्टी शॉप के पीछे स्थित घर की छत पर 35 मजदूर मिले। यह लोग पेस्ट्री बनाने का काम कर रहे थे और शारीरिक दूरी के नियम का पालन भी नहीं कर रहे थे। यही नहीं यहां पर गंदगी भी मिली। जांच में यहां दो मजदूरों में कोरोना के लक्षण मिले, जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर 33 लोगों को रैनबसेरे में भेज दिया गया। साथ ही इलाके को जिला प्रशासन ने हॉटस्पॉट घोषित कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बंगाली मार्केट, बाबर रोड, टोडरमल लेन, बाबर लेन और स्कूल लेन को सील कर दिया। वहीं एनडीएमसी इलाके को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। इलाके को सील करने के बाद किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। सभी जरूरी वस्तुओं को प्रशासन द्वारा दरवाजे पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। यहां पर डॉक्टरों की टीम जाकर लोगों की जानकारी जुटा रही है। बंगाली मार्केट सहित यह पूरा इलाका पॉश इलाके में आता है। यहां पर नौकरशाह से लेकर बड़े-बड़े व्यापारी व उद्योगपति रहते हैं।

बंगाली मार्केट इलाके को बेरीकेट लगाकर आवाजाही के लिए किया गया बंद। जागरण

असर

मानसिक स्वास्थ्य की हेल्पलाइन पर लोग बुरे सपनों से बचने के लिए ले रहे हैं सुझाव, किसी को कोरोना होने के तो किसी को राशन के लाइन में लगने के आ रहे हैं सपने

लोगों को सपनों में भी डरा रहा है कोरोना

निहाल सिंह, नई दिल्ली

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू है। इसकी वजह से लोग घरों में ही समय बिता रहे हैं। लेकिन कोरोना का डर लोगों में इतना भर गया है कि सपने भी कोरोना के आ रहे हैं। कोई सपने में अपने आप को कोरोना पीड़ित महसूस कर रहा है तो कोई राशन के लिए कई किलोमीटर तक लगी लाइन में खड़ा महसूस कर रहा है तो कोई घर से बाहर निकलने पर पुलिस की पिटाई के सपने देख रहा है। इन सपनों से बचाने के लिए विशेषज्ञ लोगों को सलाह देकर उनके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने की कोशिश में जुटे हैं।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने विजन दिव्यांगजन फाउंडेशन के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हेल्पलाइन जारी की है। इस हेल्पलाइन पर प्रतिदिन 10-12 कॉल ऐसी आती हैं जिन्हें रोजाना कोरोना के डरावने सपने आ रहे हैं। इनके दिमाग पर कोरोना का डर इस तरह से हावी हो गया है कि लोगों की नींद बुरे सपनों की वजह से प्रभावित हो रही है। वहीं, कई लोगों को तो नींद ही नहीं आ रही है।

हेल्पलाइन के संचालक मुकेश गुप्ता ने बताया कि टेलिविजन पर लगातार कोरोना से जुड़ी जानकारी देखने की वजह से लोगों के दिमाग में डर भर गया है। इसकी वजह से लोगों को ऐसे सपने आ रहे हैं। ऐसे लोगों को टेलिविजन पर कोई अन्य कार्यक्रम देखने चाहिए। वहीं, कई विशेषज्ञ लोगों को किताबे पढ़ने के साथ-साथ केंद्र सरकार की तरफ से जारी ऑनलाइन कोर्स करने की सलाह दे रहे हैं।

दिव्यांगजनों को बना रहे हैं सक्षम

निगम ने फाउंडेशन की मदद से दिव्यांगों के लिए भी अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ऐसे में एक दिन में 100-125 कॉल इस हेल्पलाइन पर आ रही हैं। इसमें दिव्यांग भोजन की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हेल्पलाइन पर कार्य करने वाले लोगों को घर पर खाना भी पहुंचा रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार और जिला प्रशासन के माध्यम से भी सहायता कर रहे हैं। मुकेश गुप्ता ने बताया कि जैसे किसी की कॉल आती है तो उस जिले में सरकार द्वारा की गई व्यवस्था का नंबर देते हैं। अगर फिर भी मदद नहीं पहुंचती तो फाउंडेशन मदद पहुंचाती है।

घर बैठे इलाज के लिए आई 4953 कॉल

निगम द्वारा घर बैठे लोगों को होम्योपैथी से लेकर आयुर्वेद और यूनानी के इलाज से संबंधित जानकारी और सुझाव देने के लिए हेल्पलाइन पर अब तक 4953 कॉल आई हैं। इस पर लोग घर में ही इलाज ले रहे हैं।

एक सप्ताह में 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा दिल्ली का तापमान

राब्यू, नई दिल्ली : मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच अगले एक सप्ताह के दौरान दिल्ली के तापमान में तेजी से इजाफा होगा। अधिकतम ही नहीं, न्यूनतम तापमान में भी इजाफा होगा। खास बात यह है कि कमोबेश हर रोज ही आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे। इसके बावजूद गर्मी और तापमान में वृद्धि होगी। 15 अप्रैल तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा।

गुरुवार को भी बादलों और सूरज के बीच लुकाछिपी चलती रही। इसलिए पूरे दिन खिले रहने पर भी धूप में अधिक चुभन न थी। अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 33.0 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह के दौरान बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। आंशिक स्तर पर बादल रोजाना ही छाए रह सकते हैं।

उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान पर मिलेगी विशेष छूट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को छूट देने की घोषणा की गई है। नकद बिल भुगतान की सुविधा फिलहाल बंद कर दी गई है, इसलिए उपभोक्तओं को डिजिटल माध्यम से बिल का भुगतान करना होगा।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के निर्देश पर बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) उपभोक्ताओं के घरों में बिजली बिल भेजने के बजाय उन्हें वॉट्सएप और ईमेल पर बिल भेज रही हैं। डीईआरसी ने डिस्कॉम को 24 मार्च से 30 जून तक बिजली बिल भुगतान की तारीख में 15 दिनों की मोहलत देने को कहा है। इन 15 दिनों तक भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से विलंब शुल्क नहीं वसूला जाएगा। वहीं, बिल बनने की तिथि से 7 दिनों के अंदर तक पूरा बिल भुगतान करने पर उपभोक्ता को एक फीसद (अधिकतम दो सौ रुपये) छूट दी जाएगी। 8 से 15 दिनों के अंदर भुगतान करने पर उपभोक्ता को 0.5 फीसद (अधिकतम 150 रुपये) की छूट मिलेगी।

इसके साथ ही यदि उपभोक्ता खुद मीटर रीडिंग लेकर बिल का भुगतान करेगा तो उसे 20 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। सार्वजनिक सुविधाएं, औद्योगिक और अन्य गैर घरेलू उपभोक्ताओं से 30 जून तक बिजली बिल पर उपकर नहीं वसूला जाएगा। व्यावसायिक उपभोक्ताओं से तीन माह तक उपकर नहीं वसूला जाएगा। बांबे सबअर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई (बीएसईएस) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) के अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान भी राजधानी में निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं।

'मानवता के लिए सब कुछ करेगा भारत'

मोदी बोले ▸ हम सब मिलकर जीत लेंगे कोविड-19 से लड़ाई

भारत ने शुरू किया एचसीक्यू का निर्यात, अमेरिका व स्पेन भेजी जाएगी खेप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना महामारी में संजीवनी समझी जाने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन (एचसीक्यू) के निर्यात की अनुमति देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धन्यवाद के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत कोविड-19 से लड़ाई में मानवता की मदद के लिए हरसंभव मदद करेगा। भारत ने दूसरे देशों को एचसीक्यू की आपूर्ति शुरू कर दी है। पहले चरण में इसे अमेरिका, ब्रिटेन और स्पेन समेत कुछ देशों को भेजा जाएगा।

दरअसल, भारत ने अपनी जरूरत को भांपते हुए एचसीक्यू के निर्यात पर रोक लगा दी थी, लेकिन दूसरे देशों की मांग को देखते हुए इसे फिर से बाहर भेजने की अनुमति दे दी गई है। केंद्र के इस फैसले का भारतीय कूटनीति पर दीर्घकालिक असर पड़ने की बात कही जा रही है। भारत के इस फैसले से सबसे ज्यादा खुश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दिख रहे हैं। एक दिन पहले

नरेंद्र मोदी फाइल फोटो

ही उन्होंने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान इंसान बताया था। गुरुवार को उन्होंने दोबारा प्रधानमंत्री मोदी व भारत को तहेदिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, 'असाधारण समय में दोस्तों के बीच और करीबी सहयोग होना चाहिए। मैं एचसीक्यू पर फैसला लेने के लिए भारत व भारतीय जनता को धन्यवाद देता हूं। इसे कभी नहीं भूला जा सकता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके मजबूत नेतृत्व से सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि मानवता की मदद करने के लिए धन्यवाद।' ट्रंप के इस बयान पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, 'मैं आपकी बात से सहमत हूं, मुश्किल समय ही दोस्तों को करीब लाता है। भारत और अमेरिका की साझेदारी पहले से भी मजबूत है। भारत कोविड-19 से लड़ाई में मानवता की मदद के लिए हरसंभव मदद करेगा। हम साथ मिलकर जीतेंगे।'

अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा बुधवार रात ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो ने अपने राष्ट्रीय संबोधन में उक्त दवा की आपूर्ति के लिए भारत की जनता और प्रधानमंत्री मोदी को खास तौर पर धन्यवाद दिया था। इसी तरह, ब्रिटेन की नई दिल्ली में उच्चायुक्त जेन थाम्पसन ने भी ब्रिटेन को पैरासीटामोल की आपूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री और भारत सरकार को धन्यवाद दिया है।

साफ है कि भारत ने ब्रिटेन को इस बात की सूचना दे दी है कि उसे पैरासीटामोल की आपूर्ति की जाएगी। भारत ने एचसीक्यू के साथ पैरासीटामोल के निर्यात पर भी पिछले शनिवार को रोक लगा थी, बाद में सोमवार को इसे खोल दिया गया। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को आस्ट्रेलिया और स्पेन के विदेश मंत्रियों से बात की और उन्हें एचसीक्यू की आपूर्ति करने का आश्वासन दिया। सनद रहे कि दुनिया के तकरीबन 30 देश भारत से एचसीक्यू की खरीद करना चाहते हैं।

कोरोना से लड़ने के तरीकों पर मोदी ने की द. कोरियाई राष्ट्रपति से चर्चा

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना महामारी से निपटने के तरीकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बताया, 'कोविड-19 के मौजूदा हालात और सहयोग व तकनीक की ताकत के जरिये इस महामारी से हम कैसे लड़ सकते हैं, इस पर राष्ट्रपति मून जे इन से टेलीफोन पर बातचीत की।' इस संबंध में जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, भारतीय कंपनियों द्वारा हासिल किए जा रहे चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और परिवहन में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री ने कोरिया सरकार की सराहना भी की। साथ ही मोदी ने इस संकट से निपटने में कोरिया गणराज्य द्वारा तकनीक के इस्तेमाल की प्रशंसा भी की। वहीं, मून जे इन ने भारतीय अधिकारियों द्वारा इतनी बड़ी भारतीय आबादी को महामारी के खिलाफ एकजुटता से लड़ने के लिए प्रेरित करने की सराहना की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि कोविड-19 का अनुसंधान के जरिये समाधान निकालने के लिए उनके विशेषज्ञ एक दूसरे से विचार-विमर्श जारी रखेंगे और अपने अनुभव साझा करते रहेंगे। कोरियाई राष्ट्रपति ने भारतीय अधिकारियों द्वारा भारत में कोरियाई नागरिकों को प्रदान की जा रही मदद के लिए धन्यवाद दिया।

कोरोना संकट में भी राजनीति से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सियासत

- दक्षिण एशियाई देशों की भारत की मदद को सार्क के तहत लाना चाहता है
- कारोबारी रिश्ते सुधारने पर बुलाई गई वीडियो कांफ्रेंसिंग में नहीं लिया हिस्सा

कोविड-19 महामारी की वजह से जहां दुनिया के तमाम देश आपसी मतभेद भुलाकर एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत की कोशिशों से खीज कर राजनीति करने में जुट गया है। वह चाहता है कि भारत की तरफ से कोरोना के खिलाफ दक्षिण एशियाई देशों की मदद करने की जो कोशिश की जा रही है, वह सार्क के तहत की जाए। इस वजह से बुधवार को महामारी के बाद की स्थिति में कारोबारी रिश्ते सुधारने पर बुलाई गई वीडियो कांफ्रेंसिंग में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान अनावश्यक तौर पर मामले को राजनीतिकरण रंग दे रहा है।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि भारत कोविड-19 के बाद सभी पड़ोसी देशों को इसलिए साथ लेकर चलना चाहता है कि वह इस स्थिति में है कि इस लड़ाई से लड़ते हुए दूसरे देशों को भी कुछ मदद कर सकता है। अगर इस बारे में हो रहे प्रयासों को किसी संगठन से जोड़ा जाएगा, तो इन्हें लागू करने को लेकर कई तरह की दिक्कतें आएंगी। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के अलावा सभी देशों का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस पर संकीर्ण राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। बुधवार को भी जो बैठक बुलाई गई थी, उसका उद्देश्य यही था कि किस तरह से इस महामारी से उपजी आर्थिक चुनौतियों का सामना किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि हम इस आपातकालीन हालत में भी सार्क संगठन के तहत सारी औपचारिकताओं में उलझें, ताकि वह इसके उद्देश्यों, एजेंडा, साझा कार्यक्रमों, लक्ष्यों आदि को तय करने में हर कदम पर अड़चन लगा सके। यही वजह है कि उसने वीडियो कांफ्रेंसिंग का विरोध किया। सनद रहे कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सार्क देशों के प्रमुखों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये 15 मार्च, 2020 को बैठक हुई थी। उसमें भी पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि, उनके स्वास्थ्य सलाहकार ने इसमें हिस्सा लिया और कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। इसके बाद एक संयुक्त फंड भी बनाने का फैसला किया गया, जिसमें भारत समेत तमाम दूसरे देशों ने योगदान दिया है। पाकिस्तान ने इसमें योगदान नहीं दिया है। बुधवार को हुई बैठक में भारत की कोशिश यह रही कि कोरोना वायरस से जिस तरह की आर्थिक चुनौतियां दक्षिण एशियाई देशों के सामने पेश आ रही हैं, उसका साझा तरीके से सामना किया जाए। जिन देशों ने इसमें हिस्सा लिया, उनमें यह सहमति बनी कि अंतर-क्षेत्रीय कारोबार को और तेजी से बढ़ाया जाएगा। इसके लिए इस क्षेत्र के देश एक दूसरे के उत्पादों के आयात-निर्यात को आसान करेंगे। सबसे ज्यादा ध्यान आवश्यक वस्तुओं के आयात-निर्यात पर दिया जाएगा, ताकि एक दूसरे की मदद दी जा सके। भारत ने प्रस्ताव किया है कि वह सभी सदस्य देशों के बीच इस बारे में समन्वय स्थापित करने का काम करेगा।

कोरोना को हराना है

हिमालयी क्षेत्रों में सामान की आपूर्ति कर रही आइटीबीपी

नई दिल्ली : कोरोना संकट और देशव्यापी लॉकडाउन के बीच भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के जवान हिमालयी क्षेत्रों में बसे लोगों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। जवान लेह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमालय की तराई के दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों के बीच रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं। आइटीबीपी के प्रवक्ता विवेक पांडेय ने बताया, 'जवान देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के दौरान रोजमर्रा के लिए आवश्यक अन्य चीजों के साथ-साथ राशन, ईंधन और दवा आदि की आपूर्ति कर रहे हैं। जवान लॉकडाउन का पालन कराने में स्थानीय प्रशासन का सहयोग रहे हैं और जरूरतमंदों को दी जा रही सामग्री पर नजर भी रख रहे हैं। (एएनआइ)

सिंगापुर से मेडिकल उपकरण लाने गया स्पाइस जेट का कार्गो विमान

नई दिल्ली : स्पाइस जेट ने कहा है कि गुरुवार को उसका पहला कार्गो विमान चेन्नई से सिंगापुर भेजा गया। यह कार्गो विमान भारत में कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए कुछ जरूरी मेडिकल उपकरण एवं अन्य सामान लाने गया है। बजट कैरियर ने कहा है कि सिंगापुर से मेडिकल आपूर्ति बेंगलुरु पहुंचाने के लिए शुक्रवार को दूसरा मालवाहक विमान भेजेगा। एयरलाइंस ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है, 'स्पाइस जेट ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद से 1500 टन से ज्यादा आवश्यक सामान की आपूर्ति का परिवहन किया है। वैश्विक महामारी के खिलाफ इस युद्ध में सरकार, मेडिकल और फर्मा कंपनियों एवं अंतरराष्ट्रीय (प्रेट्र)

सुप्रीम कोर्ट में निजी अस्पतालों के राष्ट्रीयकरण की अपील

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके देश में कोविड-19 से निपटने के लिए सभी निजी स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण क्की अपील की है। इसके लिए केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए जाने की भी मांग की गई है। दिल्ली के वकील अमित द्विवेदी ने गुरुवार को अपनी याचिका में दावा किया है कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त ढांचा नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सभी स्वास्थ्य सेवाओं, संस्थानों और कंपनियों को कोरोना के संक्रमण का मुफ्त इलाज करने का निर्देश दिया जाए। (प्रेट्र)

आइसोलेशन में रखे गए लोगों की हो रही 'जियो फेंसिंग'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संक्रमण पर पैनी नजर

- कोरोना संक्रमण के संदिग्धों पर 24 घंटे रखी जा रही है नजर
- आइसोलेशन की जगह से बाहर जाते ही एजेंसियां हो जाती हैं सतर्क

रविशंकर प्रसाद फाइल फोटो

आइसोलेशन में रखे गए कोरोना वायरस से ग्रसित होने के संदिग्ध व्यक्ति के लिए घर से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। आठ राज्यों में ऐसे संदिग्धों का 'जियो फेंसिंग' कर दिया गया है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आइसोलेशन के स्थान से दूर जाएगा, उसकी निगरानी में लगी एजेंसियां सतर्क हो जाएंगी। सूचना व प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आठ राज्यों में आइसोलेशन में रखे गए कोरोना के संदिग्धों पर नजर रखने के लिए 'जियो फेंसिंग' का इस्तेमाल किया जा रहा है।

रविशंकर प्रसाद के अनुसार इस प्रणाली में व्यक्ति पर नजर रखने के लिए मोबाइल के तीन टॉवर के डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। यह किसी व्यक्ति के 100 मीटर तक दायरे तक नजर रख सकता है। जैसे व्यक्ति अपने आइसोलेशन के स्थान से 100 मीटर दूर जाता है, उसे 'जियो फेंसिंग' का उल्लंघन माना जाता है। उन्होंने कहा कि देश भर में विदेश से आए या फिर किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाले लाखों लोगों को घर पर आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। 'जियो फेंसिंग' ने इसे पूरी तरह सफल कर दिया है।

कोरोना के खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए सरकार पहले ही 'आरोग्य सेतु' एप को लांच कर चुकी है और अब तक ढाई करोड़ से अधिक लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। लेकिन इसका लाभ देश भर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले 60 करोड़ लोग ही कर सकते हैं। जबकि 60 करोड़ लोग ऐसे भी हैं, जो सामान्य फोन का इस्तेमाल करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसे लोगों को जानकारी देने के लिए तमिलनाडु में विशेष आरोग्य-वायस कॉल सेवा शुरू की गई है। वहां 9499912345 पर कोई भी व्यक्ति मिस्ड कॉल देकर कोरोना के बारे में जानकारी हासिल सकता है। यही नहीं, इसमें कोई व्यक्ति अपने कोरोना से संदिग्ध व्यक्ति के संपर्क में आने और अपनी जांच करने के लिए भी कह सकता है।

रविशंकर प्रसाद के अनुसार इसके अलावा माईगोव और एनडीएमए की पहल पर लगभग एक लाख 18 हजार व्यक्ति और 4,482 संगठनों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद करने के लिए खुद को तैयार बताया है और इसके लिए पंजीकृत कर चुके हैं। जरूरत पड़ने पर सरकार इनकी सेवाएं ले सकती हैं।

सैंपल टेस्ट में फेल कंपनियां भी बाजार में बेच रही हैं पीपीई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कपड़ा मंत्रालय ने जारी की चेतावनी

कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी कई कंपनियां फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आ रही हैं। कोरोना के इलाज के लिए जरूरी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट्स (पीपीई) की इन दिनों भारी मांग है और इसका नाजायज फायदा कई कंपनियां उठाना चाह रही हैं। इस संदर्भ में लोगों को जागरूक करने के लिए टेक्सटाइल मंत्रालय की तरफ से चेतावनी जारी की गई है।

मंत्रालय की चेतावनी में कहा गया है कि पीपीई उत्पादन के लिए सैंपल टेस्ट में फेल होने वाली कंपनियां भी बाजार में पीपीई की आपूर्ति कर रही हैं, इसलिए इसकी खरीदारी के दौरान सचेत रहने की आवश्यकता है। पीपीई का उत्पादन आरंभ करने से पहले कंपनी को सैंपल सरकार को देना होता है। पीपीई निर्माण के लिए सरकार की तरफ से बनाए गए दिशानिर्देश के अनुरूप सैंपल नहीं पाए जाने पर उस कंपनी को तैयार करने की इजाजत नहीं दी जाती है। अभी कोयंबटूर स्थित साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (सिट्रा) और ग्वालियर स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (डीआरडीइ) की प्रयोगशालाओं में पीपीई सैंपल की जांच होती है। सिट्रा पीपीई बनाने वाली हर मैन्यूफैक्चरर कंपनी के लिए अलग-अलग कोड जेनरेट करती है। इस कोड में उस मैन्यूफैक्चरिंग की जानकारी होती है। मंत्रालय के मुताबिक, कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाले पीपीई (बॉडी कवरऑल) के अंदर उसे बनाने वाली कंपनी का नाम, सिट्रा से दिए गए कोड, बैच नंबर, मैन्यूफैक्चरिंग की तारीख जैसी चीजों का अंकित होना अनिवार्य है। मंत्रालय के मुताबिक, सिट्रा की तरफ से अब तक 23 कंपनियों की फैब्रिक को टेस्ट में सफल पाया गया है।

टाटा स्काई, एयरटेल डीटीएच प्रसारित करेंगे स्वयंप्रभा चैनल

नई दिल्ली, प्रेट्र : लॉकडाउन के दौरान टाटा स्काई और एयरटेल डीटीएच मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे तीन शैक्षिक स्वंयप्रभा चैनलों को प्रसारित करेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने टाटा स्काई और एयरटेल डीटीएच ऑपरेटरों से अनुरोध किया था कि वे घर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें और अधिक से अधिक छात्रों तक यह सुविधा पहुंचाएं। जावडेकर के अनुसार, कोरोना के प्रकोप के कारण उत्पन्न हुई इस कठिन परिस्थिति में भी छात्र घर से ही अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अब देश भर में कहीं भी कोई छात्र बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इन चैनलों के लिए डीटीएच सेवा प्रदाता से अनुरोध कर सकता है। ये चैनल पूरी तरह निःशुल्क हैं।

स्वयंप्रभा 32 चैनलों का एक समूह है, जो देश भर के सभी शिक्षकों, छात्रों और नागरिकों को कला, विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषयों, इंजीनियरिंग, चिकित्सा जैसे विविध विषयों की पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराता है।

'पीपीई की उपलब्धता को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं'

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संकट से निपटने के लिए चिकित्सा कर्मियों के निजी सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) सहित अन्य संसाधन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने का भरोसा जताया है। मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पीपीई की उपलब्धता को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) की कमी की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि भारत में 20 घरेलू कंपनियां इसका निर्माण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 1.7 करोड़ के पीपीई की खरीद के आर्डर दिए जा चुके हैं। साथ ही 49 हजार वेंटिलेटर भी खरीदे जा रहे हैं।

अग्रवाल ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अफवाहों में आने या आतंकित होने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि पीपीई, एन-95 मास्क और अन्य उपकरणों की सीमित आपूर्ति को देखते हुए जरूरत के मुताबिक इनका संतुलित इस्तेमाल किया जाये। उन्होंने कहा कि मानकों के आधार पर एक स्वास्थ्यकर्मी के लिए एक दिन में एक मास्क का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति चार मास्क भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यह गैरजरूरी है। सरकार सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही संसाधनों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। संसाधनों की कोई कमी नहीं है।

अग्रवाल ने कोरोना के संक्रमण को रोकने में राज्यों की मदद के लिए पूरी तरह से केंद्र द्वारा प्रायोजित 'कोविड इमरजेंसी पैकेज' को मंजूर किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि राज्यों में संसाधनों की कमी को बाधक नहीं बनने दिया जाएगा। अग्रवाल ने कहा कि रेल मंत्रालय ने भी 3,250 डिब्बों को क्वारंटाइन इकाइयों में तब्दील किया है।

इस दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के वरिष्ठ वैज्ञानिक मनोज मुरहेकर ने संक्रमण के मामले सामने आने की गति स्थिर होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में अब तक कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 1.30 लाख परीक्षण किए जा चुके हैं। मुरहेकर ने कहा कि इनमें पिछले 24 घंटों में किए गए 13,143 परीक्षण भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षण में संक्रमित मामले सामने आने की दर तीन से पांच फीसद के स्तर पर बरकरार है। इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बनेंगे एमएलसी

मुंबई, आइएएनएस : कोरोना महामारी के कारण सभी चुनाव स्थगित रहने के कारण महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने का आग्रह किया है। अधिकृत सूत्रों ने यह जानकारी दी।

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में महा विकास अघाड़ी के तीनों घटकों शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर दिया। पिछले वर्ष 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेने वाले उद्धव ठाकरे वर्तमान में विधानमंडल के दोनों में से किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। संविधान के अनुसार पद पर बने रहने के लिए लिए उन्हें छह माह के भीतर या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुना जाना अनिवार्य है। पिछले दिनों इस बात के पुरजोर अनुमान लगाए जा रहे थे कि 28 मई तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं बनने पर उन्हें पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिससे एक बड़ा संवैधानिक गतिरोध खड़ा हो जाएगा। हालांकि राज्य के मंत्रिमंडल ने इस स्थिति का समाधान निकाल लिया है और राज्यपाल से मुख्यमंत्री को विधानमंडल के ऊपरी सदन का सदस्य मनोनीत करने का अनुरोध किया है।

जम्मू-कश्मीर में फोर जी इंटरनेट सेवा की मांग पर नोटिस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

कोरोना महामारी के चलते केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में फोर जी इंटरनेट सेवा शुरू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। शीर्ष कोर्ट में यह जनहित याचिका फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने दाखिल की है।

जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने मामले को अर्जेंट मानते हुए गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई कर आदेश दिए। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने बहस करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन में तकनीक और कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। लॉकडाउन में छात्रों की वर्चुअल क्लास भी सिर्फ तकनीक और कनेक्टिविटी बढ़ाने से ही हो सकती है। तभी पीठ ने पूछा कि क्या सरकार की ओर से कोई मौजूद है। इस पर कोई उत्तर नहीं मिलने के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ईमेल के जरिये केंद्र व राज्य की स्टैंडिंग काउंसिल को नोटिस देने की भी इजाजत दी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को भी निर्देश दिया है कि वह जम्मू-कश्मीर और केंद्र सरकार की स्टैंडिंग काउंसिल यानी पैनल वकीलों को नोटिस भेजे।

याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी के कारण अभूतपूर्व स्थिति बनी हुई है। लॉकडाउन में लोगों के पास सूचना का बेहतर साधन होना चाहिए। इंटरनेट की टूजी सेवा पुरानी पड़ चुकी है लोगों को फोरजी सेवा हाईस्पीड इंटरनेट मिलना चाहिए ताकि इस परेशानी के समय में जानकारी लेने में और संपर्क करने में उन्हें सुविधा हो। सरकार का जम्मू-कश्मीर में सिर्फ टूजी सेवा देना अतार्किक है। इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों के बराबरी व अन्य अधिकारों का हनन होता है।

महिला जनधन खातों में अगले दो माह में 1,000 रुपये और डालेगी सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) खाताधारी महिलाओं के खातों में अप्रैल माह के 500 रुपये भेज दिए गए हैं, जबकि अगले दो महीनों में 1,000 रुपये और भेजे जाएंगे।

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने ट्वीट किया कि महिला जनधन खातों में डाले गए रुपये कभी भी निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा मई और जून में जनधन खातों में 500-500 रुपये और डाले जाएंगे। इस बीच भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। उसने कहा कि महिला जनधन खातों में भेजे गए 500 रुपये किसी भी हाल में वापस नहीं लिए जाएंगे। ऐसी अफवाह फैल गई थी कि अगर खातों से महिलाएं 500 रुपये नहीं निकालेंगी तो वे वापस ले लिए जाएंगे। इसके कारण बैंकों में भीड़ लगने और कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के अनुपालन में बाधा पैदा होने लगी थी। पीएम जनधन योजना के तहत खोले गए कुल 38.08 करोड़ बैंक खातों में से कुल 20.60 करोड़ महिलाओं के नाम पर हैं।

मंथन

रेलवे बोर्ड अध्यक्ष व महाप्रबंधकों के बीच संचालन के संभावित तरीकों पर चर्चा, कोरोना संक्रमण के मुताबिक रेड, यलो व ग्रीन जोन बनाने पर किया जा रहा गौर

लॉकडाउन खुलने पर सिर्फ स्पेशल आरक्षित ट्रेनें चलाने पर विचार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेल मंत्रालय ने लॉकडाउन खुलने की स्थिति में ट्रेन संचालन के तौर-तरीकों पर मंथन शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में सरकार कोरोना संक्रमण मामलों के हिसाब से देश को तीन परिक्षेत्रों- रेड, यलो और ग्रीन जोन में विभाजित करने पर विचार कर रही है। रेड जोन में कोई भी ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। यलो जोन में सीमित संख्या में ट्रेनें चलेंगी। जबकि ग्रीन जोन में ट्रेन यातायात पूरी तरह खोल दिया जाएगा। लेकिन चलने वाली सभी ट्रेनों में कुछ नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। टाइम टेबल पर आधारित कोई सामान्य ट्रेन नहीं चलेगी। केवल स्पेशल स्लीपर और थर्ड एसी ट्रेनें चलेंगी। जिनमें आरक्षण जरूरी होगा।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने सभी जोनल महाप्रबंधकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस पर चर्चा कर सुझाव देने और प्लान तैयार करने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार लॉकडाउन के बारे में

विनोद कुमार यादव फाइल फोटो

फैसला नहीं करती और रेलवे बोर्ड द्वारा आदेश जारी नहीं कर दिए जाते, किसी भी हालत में ट्रेन संचालन की तारीख के बारे में कयास नहीं लगाए जाने चाहिए। इससे लोगों के बीच भ्रम व अफरातफरी की स्थिति पैदा हो सकती है।

मिडिल बर्थ अलॉट नहीं होगी : सूत्रों के अनुसार, चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए किसी भी यात्री को मिडिल बर्थ अलॉट नहीं की जाएगी। संक्रमण कम होने तक ट्रेनों में चादर, कंबल, तकिया और खाने की आपूर्ति नहीं होगी।

मास्क लगाना अनिवार्य होगा : स्पेशल ट्रेनों में प्रवेश से पूर्व स्टेशन के प्रवेश द्वार पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। 60 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रियों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। जिनके पास मास्क नहीं होंगे उन्हें प्रवेश द्वार पर ही मास्क दिए जाएंगे। बिना मास्क यात्रा करते पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

अनारक्षित को नहीं होगी अनुमति : बिना आरक्षण किसी को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरक्षण इसलिए जरूरी होगा ताकि यात्रा के बाद किसी के कोरोना संक्रमित पाए जाने की स्थिति में साथ में सफर करने वाले यात्रियों को खोजकर उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके।

मेट्रो शहरों के लिए ट्रेनें चलना मुश्किल : सूत्रों के मुताबिक, वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान ये बात उभरकर सामने आई कि मौजूदा रुख के मद्देनजर संभवतः कोलकाता को छोड़कर ज्यादातर मेट्रो शहर रेड जोन में आ सकते हैं। ऐसे में दिल्ली, मुंबई, सिकंदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच ट्रेन सेवाएं शायद संभव न हों। लिहाजा इन शहरों के बीच कम से कम 30 अप्रैल तक कोई यात्री ट्रेन सेवा नहीं चलाना ही बेहतर रहेगा। इस संदर्भ में इस तथ्य पर भी गौर किया गया कि कोरोना के कई ऐसे केस सामने आए हैं जिनमें व्यक्ति में शुरुआत में कोई लक्षण नहीं प्रकट हुए, परंतु बाद में गंभीर स्थिति पैदा हो गई। एक सुझाव यह भी आया कि किसी भी ट्रेन को कोरोना हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित स्टेशनों पर नहीं रोका जाना चाहिए।

राज्यों की सीमा में चलाने का सुझाव : रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने सभी महाप्रबंधकों से राज्य सरकारों से लगातार संपर्क में रहने और ट्रेनों की मांग अथवा अनिच्छा के बारे में पता करने की सलाह दी। एक जोनल महाप्रबंधक का सुझाव था कि जो ट्रेनें जहां से चलें उन्हें उस राज्य की सीमा के भीतर ही चलाया जाना चाहिए। दूसरे राज्यों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

कह के रहेंगे माधव जोशी

छत्तीसगढ़ में वायरस से सात जमाती संक्रमित मिले

नईदुनिया, रायपुर

- कोरबा जिले के कटघोरा मस्जिद में आए जमाती से फैला संक्रमण
- प्रभावित इलाका सील किया गया, पूरे गांव की होगी जांच

छत्तीसगढ़ में गुरुवार को एक साथ सात कोरोना पॉजिटिव केस मिले है। ये सभी कोरबा जिले के कटघोरा मस्जिद में आए तब्लीगी जमात के संक्रमित किशोर के संपर्क में आए थे। पॉजिटिव मिले लोगों में दो महिलाएं भी हैं। इन्हें एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है। इससे पहले यहीं से दो लोग कोराना पॉजिटिव पाए गए थे। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या अब 18 हो गई है। इसमें तब्लीगी जमात या उनके संपर्क में आए लोगों की संख्या नौ है।

तब्लीगी जमातियों के कारण कोरबा के कटघोरा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ने की आशंका को देखते हुए सरकार सख्त कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि कटघोरा का प्रभावित इलाका सील कर दिया गया है। कटघोरा और आसपास के प्रत्येक ग्रामीण की कोरोना जांच कराने की सरकार तैयारी कर रही है।

गौरतलब है कि चार अप्रैल को कटघोरा की पुरानी बस्ती स्थित जामा मस्जिद में मिला 16 वर्षीय किशोर कोरोना संक्रमित पाया गया था, जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में आयोजित तकरीर में शामिल होकर महाराष्ट्र के कामठी लौटा था। वहां से किशोर समेत 16 तब्लीगी जमाती दो मार्च को कोरबा के कटघोरा पहुंचे थे। ये सभी पुरानी बस्ती की जामा मस्जिद में ही ठहरे थे। कटघोरा आने के बाद से ही सभी तमाम घरों में दावत पर जाते रहे। हालांकि, जानकारी मिलने के बाद लॉकडाउन के दौरान सभी को मस्जिद में ही क्वारंटाइन किया गया था। कोरोना पॉजिटिव किशोर के संपर्क में आए एक शख्स की रिपोर्ट बुधवार को पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद गुरुवार को जमाती किशोर के संपर्क में आए सात अन्य लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है।

लॉकडाउन पर टिका है तब्लीगी जमात के मुखिया का भविष्य

जागरण संवाददाता, शामली

निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी जमात के मरकज के प्रमुख (अमीर) मौलाना साद कांधलवी इतने दिनों से कहां हैं? नोटिस भेजने की बात कहने के अलावा दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? साद, तब्लीगी जमात और निजामुद्दीन मरकज के विरुद्ध आरोप और जांच-पड़ताल कहां तक पहुंची है? इसमें क्या सामने आया है? इसके अलावा कुछ गंभीर सवाल भी इस फेहरिस्त में शुमार हैं! लेकिन असल स्थिति क्या है यह न तो पुलिस खुलकर बता रही है, ना कोई और। लेकिन अंदरखाने बहुत कुछ पक रहा है। जमात और साद से जुड़े करीबी लोगों और कांधला-शामली जैसे साद के मुख्य ठिकानों से छनकर आ रही सूचनाओं पर गौर करें तो काफी कुछ अनुमान मिल जाता है। ऐसी ही बड़ी सूचना यह है कि मौलाना साद दिल्ली स्थित अपने आवास में ही दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में हैं। माना जा रहा है कि लॉकडाउन की समाप्ति को लेकर सरकार के निर्णय पर ही सबकुछ टिका हुआ है। वहीं दूसरी ओर, लॉकडाउन के बाद साद, तब्लीगी जमात और मरकज के विरुद्ध संभावित कार्रवाई के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े जमावड़े की तैयारी में देश-विदेश के जमाती जुट गए हैं। दिल्ली पुलिस साद को गिरफ्तार करेगी या वह आत्मसमर्पण करेंगे? यह भी तभी साफ होगा।

शामली के कांधला स्थित मौलाना साद के फार्म हाउस पर जानकारी जुटाने पहुंची पुलिस और एलआइयू की टीम। सोशल मीडिया

न नोटिस चस्पा, न ही किसी को सौंपा

दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि उसने इस फार्म हाउस पर नोटिस चस्पा किया था। इधर, उप्र पुलिस ने आज फिर दोहराया कि उसके पास ऐसी कोई सूचना नही है। मौलाना साद के परिजन मौलाना नूरुलहसन राशिद ने भी साफ कहा कि यहां न तो कोई नोटिस चस्पा किया गया और ना ही किसी को सौंपा गया।

इधर, कोरोना संक्रमण फैलने के आरोप में नामजद मौलाना साद के स्वजनों को एतराज है कि मौलना साद को फरार, भूमिगत व तलाश जारी जैसे संबोधन दिए जा रहे हैं। वह कहते हैं, मौलाना साद दिल्ली में ही न सिर्फ अपने घर पर मौजूद हैं, बल्कि दिल्ली पुलिस व खुफिया विभाग के संपर्क में हैं। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद वह खुद लोगों व दिल्ली पुलिस के सामने आएंगे।

मौलाना साद मूलरूप से शामली के कांधला कस्बे के रहने वाले हैं। साद के बेटे मौलाना युसुफ व मौलाना सईद का निकाह कांधला में ही हुआ है। इस कारण कांधला से उनका जुड़ाव बेहद गहरा है। उनका यहां 24 बीघे का फार्महाउस भी है। वह अक्सर यहां आते-जाते रहते हैं। कांधला पुलिस व खुफिया विभाग की टीम ने गुरुवार को उनके फार्म हाउस पहुंचकर जांच-पड़ताल की। उनके नौकरों से पूछताछ की गई। मौलाना साद के पुलिस-खुफिया विभाग के तलाश के दावों पर मौलाना साद के समधी मौलाना नूरुलहसन राशिद मुस्कुराते हुए चुटकियां लेते हैं। कहते हैं, मौलाना साद फरार नहीं है, अपने घर पर ही मौजूद हैं, क्वारंटाइन में हैं। वहां उनके अधिवक्ताओं के अलावा दिल्ली पुलिस-खुफिया विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। हर कानूनी जानकारी व बातचीत उनसे की जा रही है। मौलाना साद परिजनों व अपने अजीजों के संपर्क में हैं। जरूरी जवाब भी दिए जा रहे हैं। वह कहते हैं, मौलाना साद लॉकडाउन समाप्त होते ही सरकार-पुलिस के सामने आएंगे। मौलाना साद व करीबियों की इस गुफ्तगू से साफ है, मौलाना साद का भविष्य लॉकडाउन पर टिका है।

यह भी सूचना है कि जमातियों के बीच एक संदेश साझा किया जा रहा है, जिसमें लॉकडाउन के बाद देश में एक बड़े जमावड़े (इज्तिमा) की अपील की जा रही है। देश-विदेश में जमाती इस संदेश को एक-दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। संभव है कि लॉकडाउन के बाद बनने वाली स्थितियों को लेकर यह एक तरह की तैयारी है। तब्लीगी जमात, निजामुद्दीन मरकज और इसके कर्ताधर्ताओं के विरुद्ध क्या कानूनी कार्रवाई होगी, सबकुछ इस पर निर्भर करेगा।

तब्लीगी मरकज से जुड़े लोग देशभर में सर्विलांस पर

संक्रमण की जमात ▶ फिदायीन कनेक्शन का भी है शक

सिविक एजेंसियों को दी संक्रमित जमातियों के पहचान की जिम्मेदारी

अरविंद कुमार द्विवेदी, नई दिल्ली

उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर में रह रहे बांग्लादेशी जोड़े को बुधवार को क्वारंटाइन में भेजा गया। इस जोड़े ने दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के मरकज में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। प्रेट्र

निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज से निकले जमाती अपने संदिग्ध व्यवहार के कारण निशाने पर हैं। पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसुलूकी और थूककर संक्रमण फैलाने के प्रयास के कारण जांच एजेंसियों को इनके फिदायीन कनेक्शन का अंदेशा है। इसलिए देशभर में फैले इन लोगों को सर्विलांस पर रखा गया है। जमातियों की पहचान करने के लिए पुलिस व अन्य जांच एजेंसियों के साथ ही प्रत्येक राज्य में सिविक एजेंसियों (नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत) को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दक्षिण दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि शुरू के एक-दो दिनों तक एजेंसियों को इनके मंसूबे स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आए थे। जांच आगे बढ़ी और देशभर के अस्पतालों व क्वारंटाइन सेंटरों में इनकी हरकतों के कारण जांच एजेंसियों का शक बढ़ा। सूत्रों के मुताबिक अब हर राज्य में इसके लिए अलग स्टेट सर्विलांस अफसर (एसएसओ) और हर जिले में डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस अफसर (डीएसओ) तैनात कर दिए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर उसका जमात से कनेक्शन सबसे पहले तलाशा जा रहा है। सभी राज्यों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर इन्हें सर्विलांस किया जा रहा है। इसमें उनके मोबाइल नंबर, एटीएम ट्रांजेक्शन, बैंक खातों की निगरानी के साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि वह कब, किससे और कहां मिले? इसके आधार पर क्वारंटाइन किए गए लोगों की ट्रैवेल हिस्ट्री के साथ ही उनका सामाजिक संपर्क भी देखा जा रहा है। वह क्या काम करते हैं, पैसे कहां से आते हैं, किन-किन संगठनों से जुड़े हैं आदि की जानकारी जुटाई जा रही है।

इसलिए तलाशा जा रहा कनेक्शन : शुरू में इन जमातियों ने बताया कि वे लॉकडाउन के कारण मरकज में फंस गए थे। इसके बाद कार्यक्रम के दौरान मौलाना साद द्वारा उन्हें एकत्र होने, नमाज पढ़ने और ज्यादा से ज्यादा एक साथ रहने आदि के लिए उकसाने के कई ऑडियो सामने आए। जांच आगे बढ़ी तो साफ हो गया कि ये लोग जानबूझकर मरकज में जुटे। उन्हें यह पता भी था कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं, इसके बावजूद उन्होंने जानकारी छिपाई। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि जांच का मुख्य फोकस यह है कि आखिर ये लोग इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित कैसे हुए? इन लोगों में इतना जज्बा कहां से आया? कहीं किसी फिदायीन संगठन के इशारे पर ये लोग कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं।

मरकज प्रबंधन से जुड़े मौलानाओं के घरों पर छापे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- निजामुद्दीन स्थित मरकज से नहीं मिले कंप्यूटर और लैपटॉप
- फिलहाल साद को गिरफ्तार करने पर नहीं क्राइम ब्रांच का फोकस

देश में कोरोना को लेकर बड़ा संकट खड़ा करने वाले तब्लीगी मरकज से गायब हुए दो कंप्यूटर, लैपटॉप व रजिस्टर आदि क्राइम ब्रांच अब तक बरामद नहीं कर पाई है। क्राइम ब्रांच को शक है कि प्रबंधन से जुड़े छह मौलाना सुबूत नष्ट करने के उद्देश्य से ये सब सामान अपने साथ लेकर चले गए। इनकी बरामदगी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम मौलानाओं के पुरानी दिल्ली, जामिया नगर व यमुनापार स्थित घरों पर कई बार छापेमारी कर चुकी है, लेकिन कुछ भी सामान नहीं मिला है।

क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कंप्यूटर, लैपटॉप व रजिस्टर केस के लिए सबसे अहम सुबूत हैं। इनमें मरकज को देश व विदेश से आने वाले लोगों द्वारा दिए गए चंदे, जमातियों के नाम, पते, मोबाइल नंबर व मरकज से जुड़ी अन्य जानकारियां हो सकती हैं। ये सभी 28 मार्च से ही अपने-अपने घरों से फरार हैं। इनके मोबाइल फोन भी बंद हैं।

उधर, मरकज के प्रमुख मौलाना मुहम्मद साद को लेकर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मौलाना साद के मेवात में छिपे होने की आशंका है, लेकिन पुलिस की पूछताछ में उसके बेटे व अधिवक्ता जामिया नगर इलाके में होम क्वारंटाइन होने का दावा कर रहे हैं। गुरुवार को क्राइम ब्रांच ने अनौपचारिक तौर पर साफ भी कर दिया कि कोरोना की वजह से उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की जा रही है। साद जामिया में ही कहीं छिपा हो सकता है, क्योंकि जामिया नगर, जाकिर नगर, शाहीनबाग आदि इलाकों में उसके दो दर्जन से ज्यादा रिश्तेदार रहते हैं। जाकिर नगर में साद का अपना घर भी है, लेकिन उसके अपने घर में होने की संभावना कम है। 14 दिनों तक क्वारंटाइन की अवधि समाप्त हो जाने व गिरफ्तारी के निर्देश मिलने के बाद ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा अन्य छह मौलानाओं की गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

मंत्रालय पहुंचा इलाहाबाद विवि के प्रोफेसर का जमात कनेक्शन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के जमात में शामिल होने से विवि में दहशत

इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद के निजामुद्दीन स्थित तब्लीगी जमात के मरकज में जाने का मामला केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) तक पहुंच गया है। पुलिस के पूछने पर भी इन्कार करने को गंभीरता से लिया गया है। फिलहाल, उन्हें परिवार समेत क्वारंटाइन कर कोरोना संबंधी उनकी जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है। वहीं, एसपी सिटी बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रोफेसर एक कार्यक्रम में शामिल होने जुलाई में इथोपिया गए थे। वहां से वह दिसंबर में लौटे थे। इनकी कोरोना संबंधी रिपोर्ट आने के बाद उनके भाई व परिवार के संबंध में जानकारी जुटाई जाएगी।

मूलरूप से मऊ जिले के निवासी मोहम्मद शाहिद ने राजनीति विज्ञान से पीएचडी की है, जो कि परिवार समेत प्रयागराज की मेंहदौरी कालोनी में रहते हैं। वह 10 मार्च तक तब्लीगी जमात में शामिल हुए थे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रामेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 17 मार्च को उन्होंने ड्यूटी की थी, जिसमें करीब 250 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। कर्मचारी और कई अन्य विभाग के प्रोफेसर और अतिथि प्रवक्ता भी उनके संपर्क में आए थे।

भाई भी इविवि में हैं प्रोफेसर : मोहम्मद शाहिद के बड़े भाई भी विवि के वाणिज्य विभाग में प्रोफेसर हैं। वह और उनका परिवार भी प्रो. शाहिद के संपर्क में आया था। ऐसे में दोनों प्रोफेसर भाइयों के संपर्क में अब तक कई लोग आ चुके हैं। इस संदर्भ में उनके बड़े भाई ने कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया।

इविवि प्रशासन करेगा कार्रवाई

इविवि के रजिस्ट्रार प्रोफेसर एनके शुक्ला ने बताया कि अभी मुकदमे की कापी उन्हें नहीं मिली है, जिसका इंतजार है। इसके बाद विश्वविद्यालय के अधिनियम के तहत प्रो. शाहिद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में कुलपति से भी चर्चा की जाएगी।

इंडोनेशियाई जमातियों को प्रोफेसर ने दिलाई थी मस्जिद में पनाह : कोरोना पॉजिटिव एक इंडोनेशियाई नागरिक समेत अन्य को लेकर नई जानकारी सामने आई है। गुरुवार को पुलिस ने प्रोफेसर से फिर पूछताछ की तो पता चला कि इंडोनेशिया के सात नागरिक, बंगाल और केरल के एक-एक युवक दिल्ली के तब्लीगी जमात में शामिल हुए थे। इसके बाद उक्त सभी ट्रेन से बिहार के गया जिले जा रहे थे लेकिन, इसी बीच लॉकडाउन हो गया। ऐसे में इंडोनेशियाई जमातियों ने प्रोफेसर से संपर्क किया। फिर प्रोफेसर ने अब्दुल्ला मस्जिद के मुतवल्ली वसीम से बात कर सभी को मस्जिद में ठहराया। एसपी सिटी बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रोफेसर मो. शाहिद ने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी थी।

इंदौर में कोरोना ने ली डॉक्टर की जान

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के इंदौर में एक निजी चिकित्सक की गुरुवार सुबह कोरोना से मौत हो गई। रूपराम नगर निवासी डॉक्टर का कॉलोनी में क्लीनिक था। यह अपने घर पर भी मरीजों को देखते थे। माना जा रहा है कि वे घर पर मरीजों को देखने के दौरान ही संक्रमित हुए होंगे। कुछ दिनों पहले इस बारे में चली चर्चा के बाद उन्होंने खुद पत्नी के साथ बैठकर एक वीडियो बनाया था। इसमें उन्होंने पॉजिटिव होने की खबर का खंडन किया था।

उन्हें पांच अप्रैल को सीएचएल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आठ अप्रैल को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर उन्हें अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान नौ अप्रैल की सुबह उनकी मौत हो गई। डॉक्टर 62 वर्ष के थे।

उधर, डॉक्टर की मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मवीर योद्धा को नमन, परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार से उन्हें शहीद का दर्जा देते हुए परिजनों को एक करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की मांग की है।

जमात में शामिल लोग तत्काल कराएं जांच, वरना होगी कार्रवाई

- उप्र सरकार ने कहा, संक्रमित व्यक्ति और उनके संपर्क में आने वाले न छुपाए जानकारी
- 24 घंटे में सीएमओ कार्यालय से संपर्क कर जांच करवाने के निर्देश, ताकि तोड़ी जा सके संक्रमण की चेन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उप्र में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ने से चिंतित स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी छिपा रहे लोगों को चेतावनी दी है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने ऐसे लोग जो बीते दिनों तब्लीगी जमात में शामिल होकर लौटे हैं, इनके परिजनों और इनके संपर्क में आए लोगों को स्वेच्छा से जांच के लिए आगे आने के निर्देश दिए है। वहीं इनके अलावा दूसरे लोग जो विदेश यात्रा से वापस लौटे हैं उन्हें भी जांच के लिए आगे आने को कहा है। ऐसे लोग 24 घंटे के अंदर अपने जिले के सीएमओ कार्यालय से संपर्क कर जांच करवाएं। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो कार्रवाई होगी।

अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटे तब्लीगी जमात के करीब डेढ़ हजार से अधिक लोग अब तक चिन्हित किए जा चुके हैं और और तमाम के जांच के लिए नमूने भी लिए जा चुके हैं। अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के छिपे होने की संभावना है। वहीं बीते दिनों विदेश यात्रा से लौटे लोग और उनके परिवार के लोग भी जांच करवाएं। ऐसे लोग जो अभी तक संक्रमित पाए गए मरीज के संपर्क में कभी ना कभी आए हैं वह भी सीएमओ कार्यालय से संपर्क कर अपनी जांच करवाएं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। ऐसा न करने पर महामारी अधिनियम 1897 और उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली नियमावली 2020 के प्राविधानो का उल्लंघन माना जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना और छह महीने तक की सजा भी हो सकती है।

समाज के दुश्मनों जैसी हैं संकट में इनकी हरकतें

जेएनएन, लखनऊ

- पढ़े-लिखे लोगों ने भी नहीं समझी स्थिति की गंभीरता
- खुद और अपने परिवार को समेत पूरे समाज को खतरे में डाला

इसे विडंबना कहा जाए या जान-बूझकर की गई लापरवाही, लेकिन कोरोना संकट में कई पढ़े लिखों का हरकतें भी समाज के दुश्मनों जैसी हैं। ऐसे लोगों ने कोरोना संक्रमण जैसी जानकारियों को छिपाकर न सिर्फ अपराध किया बल्कि जाने-कितने लोगों को संकट में डाल दिया है। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शाहिद अंसारी का ही उदाहरण लें। उन्होंने पुलिस के दो बार पूछने पर भी नहीं बताया था कि तब्लीगी जमात में गए थे। यदि वह पहले स्वीकार कर लेते तो विश्वविद्यालय के छात्रों और खुद उनके परिवार को ही इतनी परेशानियों का सामना शायद न करना पड़ता। अब खुद वह परिवार समेत क्वारंटाइन हैं। इसी तरह प्रयागराज में ही अब्दुल्ला मस्जिद के प्रबंधकों ने भी यह तथ्य छिपाए रखा कि उनके यहां तब्लीगी जमात से होकर आए सात इंडोनेशियाई जमाती ठहरे हैं। प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील क्षेत्र की नरसिंहगढ़ की मस्जिद और डेरवा में दिल्ली से आए 11 जमातियों के बारे में भी किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी।

आगरा जो कि इस समय प्रदेश में सर्वाधिक संकटग्रस्त है, वहां भी 13 मार्च को एक रेलवे अधिकारी ने बेटी के घर में न होने की जानकारी देकर स्वास्थ्य व पुलिस टीम को तीन घंटे तक गुमराह किया। बेटी में संक्रमण की पुष्टि हुई। मुकदमा दर्ज हुआ।

संभल में बहजोई के रमपुरा गांव का निवासी एक युवक निजामुद्दीन के तब्लीगी जमात के मरकज के पास ही कारपेंटर का काम करता था। वहां से वह 17 मार्च संभल आ गया और अपने घर में था। बाद में उसे पकड़कर अस्पताल भेजा गया। इसी तरह बांदा और औरैया में मस्जिद के संचालकों ने पुलिस को गुमराह किया। बांदा के हथौरा मदरसे के संचालक मोहम्मद हबीब पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

औरैया में मिले 13 में से चार जमातियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनकी जानकारी पुलिस को न देने पर कुरैशियान मस्जिद खानपुर के मुतवल्ली अंसार समेत कई पर मुकदमा दर्ज कराए जाने की तैयारी है।

लापरवाही बरतने वालों में अस्पताल भी : कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वालों में अस्पताल प्रबंधन भी है। बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में 30 मार्च को बस्ती के तुर्कहिया निवासी एक युवक की कोरोना से मौत हो गई। इस युवक के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं दी गई। मौत के बाद उसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। यही नहीं, रिपोर्ट आए बिना ही परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उसके जनाजे में शामिल होने वाले पांच लोगों समेत कुल सात लोग कोरोना संक्रमित हो गए। इसी तरह 17 मार्च को आगरा में एक हास्पिटल संचालक का बेटा अमेरिका से लौटा। उसे 26 मार्च को संक्रमण की पुष्टि हुई। इस बीच वह घर में ही रहा। इससे डॉक्टर भी संक्रमित हुए। अब हॉस्पिटल सील है। प्रशासन लगातार लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है।

मानव बम की तरह काम कर रहे हैं तब्लीगी जमात के लोग : रिजवी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने गुरुवार को तब्लीगी जमात पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि जमात देश में कोरोना वायरस के जरिये आत्मघाती हमले कराना चाहता था। वसीम रिजवी का आरोप है कि जमात की साजिश हिंदुस्तान में एक लाख से ज्यादा लोगों को मारने की थी। उन्होंने जमातियों पर मानव बम की तरह काम करने का आरोप भी लगाया।

उन्होंने कहा, मुमकिन है कि इस साजिश में मलेशिया में रह रहे जाकिर नाईक भी शामिल हों। रिजवी ने कहा कि जिस तरह मलेशिया के जमाती मिल रहे हैं, उससे नाईक की साजिश से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जमाती जिस तरह डाक्टरों व नर्सिंग स्टाफ के साथ लगातार मारपीट व अभद्रता कर रहे हैं, साफ है कि वह उनका मनोबल कम करने की कोशिश में हैं।

बड़ी समस्या

कश्मीर में पुलिस को है विदेश से लौटने वाले और जमातियों की तलाश, एसएसपी बोले-हमें वैसे कार्रवाई करनी पड़ रही जैसे किसी आतंकी को पकड़ने के लिए की जाती है

संदिग्ध लोग आतंकियों की तरह बदल रहे ठिकाने

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कोरोना वायरस के संकट के बीच कश्मीर घाटी में विदेश यात्रा से लौटने वाले और तब्लीगी जमात से जुड़े संदिग्ध लोग शातिर आतंकियों की तरह अपने ठिकाने बदल रहे हैं। उन्हें तलाश करना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। खुद पुलिस अधिकारी मान रहे हैं कि इन लोगों का पीछा करना जैसे किसी आतंकी को तलाशने जैसा है। सूत्रों की मानें तो कश्मीर में ऐसे करीब एक हजार लोगों की तलाश की जा रही है।

जम्मू-कश्मीर में संक्रमित 184 मामलों में 152 सिर्फ कश्मीर घाटी में ही हैं। इनमें से अधिकांश मरीज विदेश से लौट हैं या फिर जमारी या फिर उनके संपर्क में आने वाले लोग हैं। कश्मीर में मार्च माह में करीब दो हजार लोग विदेश यात्रा या दिल्ली, महाराष्ट्र से लौटे हैं। इनमें से कई अभी भी छिपकर अपने घरों में बैठे हैं। इनके सपर्क में आने वाले भी नहीं बोल रहे हैं और जब किसी की हालत बिगड़ती है तो वह अस्पताल पहुंचता है।

एसएसपी श्रीनगर डॉ. हसीब मुगल ने बताया कि विदेश यात्रा से लौटे या अन्य जगहों से संक्रमण लेकर आए लोगों को तलाशने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है, जिसमें बहुत से लोगों ने विदेश यात्रा छिपाने वालों, उनके संपर्क में आने वालों के बारे में जानकारी दी है। इसके आधार पर 800-900 लोगों को पकड़ा गया है। कई अन्य स्वेच्छा से क्वारंटाइन केंद्रों में पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि हम अपने पास उपलब्ध सभी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने वालों को तलाश कर रहे हैं। इसके लिए हम उनके मोबाइल फोन, एटीएम ट्रांजेक्शन के आधार पर उनके ठिकानों का पता लगा रहे हैं।

एसएसपी ने कहा कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि यह कितना गंभीर मामला है। उन्हें अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं छिपानी चाहिए। कई बार इन लोगों को तलाश करते हुए हमें लगता है कि जैसे किसी शातिर आतंकी का पीछा किया जा रहा है। हम टेलीफोन टॉवर के आधार पर संबंधित व्यक्ति के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वह वहां से निकलकर किसी दूसरे इलाके में या दूसरे कस्बे में अपने रिश्तेदार के घर चला गया है। हमें इन लोगों को पकड़ने के लिए ठीक वैसे कार्रवाई करनी पड़ रही है जैसे किसी आतंक को पकड़ने के लिए की जाती है।

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से बचें

एसएसपी डॉ. हसीब मुगल ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग संबंधी सवाल पर कहा कि हम रोजाना 100 के करीब लोगों के फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल की छानबीन करते हैं। लोगों से हमारा आग्रह है कि वह सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की सूचना को आगे बढ़ाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से छानबीन करें। अफवाहों से बचें।

घर पर ही करें नमाज अदा

लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते हुए एसएसपी ने कहा कि बीती रात शब-ए-बरात के मौके पर प्रशासनिक पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पांच एफआइआर दर्ज की गई है। हम लोग तो घर बैठकर भी दुआ कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। काबा शरीफ को भी इन दिनों बंद किया गया है। हम सभी की धार्मिक भावनाओं का आदर करते हैं, लेकिन मौजूदा हालात बहुत गंभीर हैं।

हाई कोर्ट ने कहा- लापता 52 जमातियों को तुरंत खोजे सरकार

नईदुनिया, बिलासपुर

- छत्तीसगढ़ सरकार को तब्लीगी जमातियों की कोरोना जांच रिपोर्ट 13 अप्रैल को पेश करने का भी निर्देश

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट तब्लीगी जमात में शामिल लोगों के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका पर गंभीर हो गया है। गुरुवार को पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने दिल्ली के निजामुद्दीन से छत्तीसगढ़ पहुंचे 52 तब्लीगी जमातियों को जल्द खोजने और आवश्यक कदम उठाने के राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं।

हाई कोर्ट ने उन विभिन्न सूचनाओं को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई की, जिसमें कहा गया था कि छत्तीसगढ़ सरकार 52 जमातियों को अब तक खोज नहीं पाई है। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिन 23 तब्लीगी जमातियों की कोरोना जांच रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है, उसकी स्थिति 13 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष पेश प्रस्तुत करें।

डिवीजन बेंच ने राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा से पूछा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शासन स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं। कोर्ट ने जानकारी मांगी कि दिल्ली के निजामुद्दीन से छत्तीसगढ़ आए उन 52 तब्लीगी जमातियों की जानकारी शासन स्तर पर जुटा ली गई है या नहीं। इनकी जांच की गई है। जांच रिपोर्ट में क्या आया है। महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 52 तब्लीगी जमातियों की अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। हाई कोर्ट ने बिलासपुर और अंबिकापुर में भी जांच की व्यवस्था करने का आदेश दिया है।

मुंबई के स्लम एरिया में सघन जांच अभियान शुरू

चिंताजनक ▶ छोटी जगह पर ज्यादा लोगों के रहने और सार्वजनिक शौचालय के इस्तेमाल से प्रसार का खतरा ज्यादा

बीएमसी की 10 टीमें 215 रेड जोन में घर-घर जाकर प्रारंभिक जांच के अभियान में सक्रियता से जुटीं

राज्य ब्यूरो, मुंबई

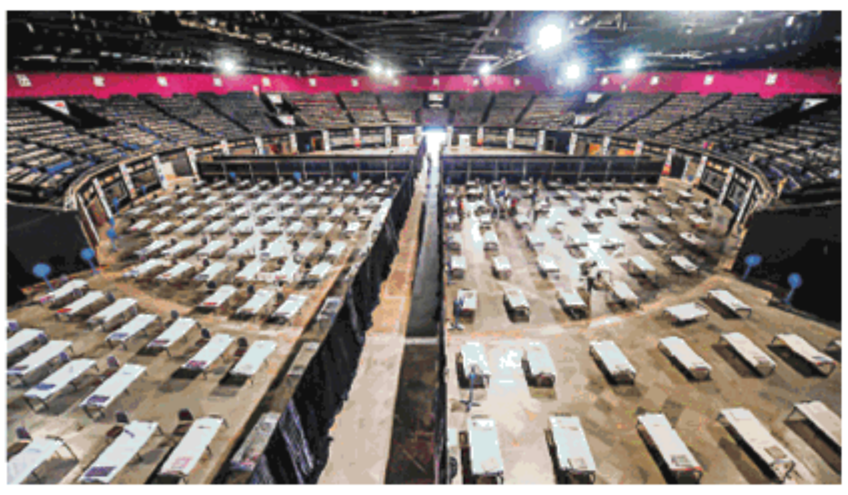

कोरोना अस्पताल में बदला स्टेडियम : मुंबई में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया (एनएससीआइ) के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम को बीएमसी अस्थाई अस्पताल में बदल रहा है। यह अस्पताल 300 बेड का होगा। स्टेडियम में आमतौर पर कबड्डी और बैडमिंटन के मुकाबले होते हैं। प्रेट्र

महाराष्ट्र में गुरुवार को एक दिन में 229 नए मामले और 25 लोगों की मौत से सरकार सतर्क हो गई है। यहां खासकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के हाल ज्यादा चिंताजनक हैं। राज्य के कुल 1,364 मामलों से 775 अकेले मुंबई से हैं। यहां घनी झोपड़पट्टी वाले इलाकों में एक कमरे में पांच से 10 लोगों के रहने और सार्वजनिक शौचालयों के इस्तेमाल के कारण कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ता जा रहा है।

प्रशासन ने इस स्थिति को टालने के लिए सघन जांच अभियान चलाने का निर्णय किया है। धारावी के पास राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं वरली के एनएसई ग्राउंड में आइसोलेशन वार्ड बनाकर संदिग्ध मरीजों को रखने की व्यवस्था की गई है। धारावी और वरली में 215 रेड जोन की पहचान कर सघन जांच अभियान चलाने के लिए बीएमसी की 10 टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें घर-घर जाकर प्रारंभिक स्क्रीनिंग कर रही हैं। इन टीमों की स्क्रीनिंग में कोरोना संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें आगे की जांच के लिए निर्धारित 10 में से किसी एक अस्पताल में भेजा जाता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा था कि मुंबई में जांच का दायरा बढ़ाए जाने के कारण नए रोगियों की पहचान बेहतर ढंग से हो पा रही है।

यह है आंकड़ा

राज्यों से मिली जानकारी के मुताबिक	
कुल मौतें	227
कुल संक्रमित	6,640
स्वस्थ हुए	596
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक	
कुल मौतें	169
कुल संक्रमित	5,865
स्वस्थ हुए	600

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बात पर चिंता जताई कि खतरा बढ़ने के बावजूद कुछ लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई के सघन इलाकों में राज्य रिजर्व पुलिस बल (एसआरपीएफ) लगाने का एलान किया है। उन्होंने कुछ स्कूलों को खोलकर सघन आबादी वाले इलाकों में रहने वालों के लिए आश्रय स्थल बनाने की बात भी कही है। सघन आबादी वाले इलाकों में सार्वजनिक शौचालयों को हर घंटे सैनिटाइज करने का अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जरूरतमंद लोगों के घरों तक खाना पहुंचाया जाएगा।

रोगियों की बढ़ती संख्या एवं नागरिकों की लापरवाही को देखते हुए मुंबई में अब सब्जियों की दुकानें सप्ताह में सिर्फ दो दिन सोमवार एवं गुरुवार को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खोलने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा किसी दिन दुकान खोलने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) आयुक्त द्वारा यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल में लॉकडाउन का ठीक से पालन न होने पर चिंता जताए जाने के बाद लिया गया है। बीएमसी एक दिन पहले ही बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की घोषणा कर चुकी है।

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए सरकार गंभीर है। धारावी में संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद सरकार को कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा सता रहा है। ऐसे में इस पर काबू पाने के लिए वह हरसंभव प्रयास कर रही है।

किस राज्य में कितने संक्रमित

राज्य	संक्रमित
महाराष्ट्र	1364
तमिलनाडु	834
दिल्ली	720
केरल	357
उत्तर प्रदेश	410
आंध्र प्रदेश	348
राजस्थान	430
मध्य प्रदेश	415
तेलंगाना	453
कर्नाटक	197
गुजरात	262
जम्मू-कश्मीर	184
हरियाणा	156
पंजाब	130
बंगाल	104
उत्तराखंड	35
बिहार	51
असम	28
ओडिशा	44
चंडीगढ़	18
लद्दाख	14
हिमाचल प्रदेश	29
अंडमान-निकोबार	11
छत्तीसगढ़	18
गोवा	7
पुडुचेरी	5
झारखंड	13

सभी जिलों को आकस्मिक योजना तैयार करने का निर्देश

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह ने गुरुवार को बैठक कर वायरस की रोकथाम और प्रबंधन योजनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए अब तक की गई कार्रवाइयों पर भी चर्चा की गई। कोरोना वायरस के संचरण की शृंखला को तोड़ने के लिए लागू किए जा रहे शारीरिक दूरी का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मंत्री समूह को सूचित किया गया कि सभी जिलों को महामारी से निपटने के लिए अपनी आकस्मिक योजना तैयार करने और मजबूत करने के लिए कहा गया है।

बयान में कहा गया है कि राज्यों की क्षमता मजबूत करने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसमें सिर्फ कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पताल बनाना, चिकित्सा संस्थानों को पीपीई, वेंटिलेटर और अन्य आवश्यक उपकरणों से लैस करना शामिल है। बयान में कहा गया है कि राज्यों को कोविड-19 केंद्रों और अस्पतालों की पहचान करने के लिए कहा गया है।

आइसीएमआर ने बदली रणनीति, हॉटस्पॉट के इंफ्लुएंजा मरीजों की भी होगी जांच

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश में इस हफ्ते कोरोना वायरस के मामलों में आई तेजी के मद्देनजर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। परिषद ने गुरुवार को कहा कि अब हॉटस्पॉट या क्लस्टर इलाकों और विस्थापित केंद्रों पर ऐसे लोगों की भी कोरोना संक्रमण जांच की जाएगी जिनमें बुखार, खांसी, खराश या नाक बहने जैसे एंफ्लुएंजा के लक्षण होंगे। यह जांच बीमारी के सात दिन के भीतर और बीमारी के सात दिन बाद कराई जाएगी।

▶ बीमारी के सात दिन के भीतर और बीमारी के सात दिन बाद होगी जांच

अभी तक श्वसन की गंभीर बीमारी से ग्रसित, सांस लेने में तकलीफ और बुखारी-खांसी वाले अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों की कोरोना जांच की जा रही थी। संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बिना लक्षण वाले और हाई रिस्क वाले व्यक्तियों का भी संपर्क में आने के पांचवें और 14वें दिन टेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा गाइडलाइंस के मुताबिक, ऐसे व्यक्तियों की भी जांच की जा रही थी जिन्होंने पिछले 14 दिनों में अंतरराष्ट्रीय यात्रा की और जिनमें पहले लक्षण नहीं थे और बाद में दिखने लगे, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले ऐसे सभी व्यक्ति जिनमें लक्षण दिखाई दिए और ऐसे सभी स्वास्थ्यकर्मी जिनमें लक्षण दिखाई दिए हैं। दरअसल, आइसीएमआर की इस नई रणनीति का मकसद प्रभावी रूप से कोरोना संक्रमण की रोकथाम करना और ऐसे सभी व्यक्तियों की विश्वसनीय जांच करना है जो कोराना जांच के मानदंडों के दायरे में आ रहे हैं।

सुरक्षित खून संग्रह के लिए सरकार ने जारी कीं गाइडलाइंस

कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रक्तदान अभियान में आई बाधा के मद्देनजर नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (एनबीटीसी) ने राज्यों को अंतरिम सिफारिशें जारी की हैं। इसमें अस्पतालों में खून की उपलब्धता बनाए रखने के लिए राज्यों को विवेकपूर्ण तरीके से रक्तदान और रक्त संग्रह जारी रखने को कहा गया है। इस दौरान समुचित शारीरिक दूरी, हाथों की स्वच्छता और चिकित्सकीय कचरे के सुरक्षित निस्तारण का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। एनबीटीसी की निदेशक डॉ. शोबिनी रंजन ने कहा कि रक्तदान प्रक्रिया या रक्त चढ़ाने से कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं है क्योंकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

विदेशी, जमाती और निजी अस्पतालों ने बढ़ाए आगरा में मरीज

जागरण संवाददाता, आगरा

▶ अराजक जमातियों की वजह से संक्रमितों की संख्या में तेजी आई

▶ निजी अस्पतालों ने समझी ही नहीं आपदा की गंभीरता

कोरोना वायरस के आगरा के आंकड़े अब डराने लगे हैं। गुरुवार को एक ही दिन में 19 मरीज पॉजिटिव और कुल संख्या 84। यह सिलसिला नहीं थमा तो ताजनगरी में स्थिति गंभीर हो सकती है। हालांकि प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत इसकी रोकथाम में झोंक रखी है। ताजनगरी में कोरोना संक्रमण पहले विदेश से लौटने वालों ने फैलाया। यह निर्यंत्रित होने लगा था तभी जमातियों ने मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ा दी। अब निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के बाद तो हालात बिगड़ने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज आगरा में हैं। चार हॉस्पिटल सील किए गए हैं, जिनके आठ आठ कर्मचारी तथा उनके तीन परिजन सहित 11 संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना मरीज का इलाज करने वाले एक वरिष्ठ डॉक्टर में भी कोरोना की पुष्टि हो चुकी है।

इस संकट को लेकर निजी अस्पतालों में विशेष सावधानी नहीं बरती गई। निजी अस्पतालों को गंभीर सांस संबंधी समस्या (सीवियर एक्यूट रेस्पेरेटरी इलनेस,सारी) के मरीजों की कोरोना जांच के लिए सैंपल भेजने की अनिवार्यता की गई। इसके लिए उनके टेक्नीशियन को प्रशिक्षण भी दिया गया। मगर, निजी अस्पतालों ने स्वास्थ्य विभाग को जानकारी नहीं दी और सैंपल भी नहीं भेजे। डॉक्टरों ने सावधानी बरती मगर, स्टाफ को मास्क तक नहीं उपलब्ध कराए। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। निजी हॉस्पिटल की लापरवाही का क्या परिणाम हुआ इससे इस बात से भी समझा जा सकता है कि रकाबगंज क्षेत्र के एक हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर और उनके डॉक्टर बेटे सहित छह लोग संक्रमित हो चुके हैं। हॉस्पिटल में छह में कोरोना की पुष्टि हुई है। मुगल रोड कमला नगर के हॉस्पिटल में 76 साल की महिला मरीज का पांच दिन इलाज चला, 7 अप्रैल को कोरोना की पुष्टि के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, 8 अप्रैल को मौत हो गई।

50 फीसद से अधिक जमाती, तीन अप्रैल से बढ़े मामले : जमातियों की वजह से 3 अप्रैल से मामले बढ़े। मस्जिदों से 147 जमाती और उनके संपर्क में आए लोग पकड़े गए, इसमें से 28 निजामुद्दीन से जुड़े हुए थे। 3 अप्रैल को सात जमातियों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसके बाद से लगातार केस आ रहे हैं। अभी तक जमाती और उनके संपर्क में आए 43 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कुल मरीजों की संख्या 84 है।

विदेश से लौटने वालों की शुरुआत

खंदारी क्षेत्र के जूता कारोबारी के दो बेटे इटली से लौटे परिवार के तीन सदस्य, फैक्टरी मैनेजर और उनकी पत्नी सहित पांच संक्रमित हुए। इसी तरह बाइपास स्थित हॉस्पिटल संचालक का बेटा अमेरिका से लौटा और उससे डॉक्टर पिता संक्रमित हुए। कमला नगर मुगल रोड की एक कॉलोनी निवासी कंपनी में कार्यरत युवक नीदरलैंड से लौटा तो 76 साल की उसकी दादी संक्रमित हुईं, जिनकी मौत भी हो गई। वह खुद कोरोना संक्रमित है, पिता और मां में भी कोरोना की पुष्टि हुई है।

आगरा में अभी तक कोरोना

पॉजिटिव मिले	84
मरीज हो चुके ठीक	8
मरीज की मौत	1
जमाती और उनके संपर्क में आने वाले	43
विदेश से लौटने वाले	12

जमाती और हॉस्पिटलों के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों को सील किया है।

– प्रभु एन सिंह, जिलाधिकारी

श्रीनगर में स्थिति गंभीर, नहीं माने लोग तो बेकाबू हो जाएंगे हालात

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जिला उपायुक्त श्रीनगर डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी ने गुरुवार को लोगों को आगाह करते हुए कहा कि श्रीनगर में संक्रमितों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर की स्थिति बहुत गंभीर है। अगर जनता ने पूरा सहयोग नहीं किया तो हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाएंगे। हम संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए शुक्रवार से लॉकडाउन को और सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि कर्फ्यू पास सिर्फ घर से कार्यस्थल के लिए ही मान्य होगा।

कोरोना वायरस के संक्रमितों में श्रीनगर जिला जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों से आगे चल रहा है। प्रदेश में अब तक 184 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 152 कश्मीर घाटी में हैं। श्रीनगर शहर और उसके साथ सटे इलाकों में ही संक्रमितों की संख्या 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है। जिला उपायुक्त श्रीनगर डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी के साथ एसएसपी श्रीनगर डॉ. हसीब मुगल ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर स्थिति से अवगत करवाया। डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि पूरे श्रीनगर को 25 जोन में बांटा गया है और इसमें 14 रेड जोन हैं। उन्होंने बताया कि छत्ताबल, लालबाजार, ईदगाह और गोरीपोरा में स्थिति संवेदनशील है। रेड जोन में शामिल इलाकों में 1000 दस्ते (चार हजार कर्मी) सैनिटाइजेशन व डिकंटेमिनेशन में जुटे हुए हैं।

जीवनरक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं : डॉ. शाहिद इकबाल ने कहा कि वादी विशेषकर श्रीनगर में जीवनरक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं है। छह और सात अप्रैल को दो जहाज यहां दवाएं लेकर पहुंचे हैं। गुरुवार को भी एक विमान में सिर्फ दवाएं आईं। हमारे पास डेढ़ माह के लिए सभी आवश्यक दवाओं का भंडार है। डॉक्टरों व पैरामेडिकल कर्मियों के लिए पीपीई किट्स की आपूर्ति को पूरी तरह सुचारू बनाया गया है। लॉकडाउन के दौरान रोजाना एटीएम पर 19 हजार और काउंटर पर नौ हजार ट्रांजेक्शन हुई हैं। श्रीनगर में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में पूछे जाने पर डॉ. शहिद इकबाल ने कहा कि मैं अभी इस बारे में हां या न में जवाब नहीं दे सकता। इस समय श्रीनगर में ऐसे कई लोग घूम रहे हैं, जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाए हुए हैं। हम ऐसे लोगों का पता लगाने में जुटे हैं।

ड्रोन, सीसीटीवी से स्थिति पर रखी जा रही नजर : लॉकडाउन के उल्लंघन पर एसएसपी श्रीनगर डॉ. हसीब मुगल ने कहा कि किसी की जान को खतरे में डालने वालों को नहीं छोड़ा जा सकता। हम ड्रोन, सीसीटीवी व अन्य उपकरणों की मदद से भी स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। यह लॉकडाउन या निषेधाज्ञा सामान्य दिनों की तरह नहीं है। आप दिनभर घर में बंद रहें और शाम को सैर करने के लिए घर से बाहर आ जाएं। ऐसा करना संक्रमण को रोकने की कवायद पर पानी फेर देगा।

जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के कोरोना वायरस रेड जोन इलाके में गुरुवार को डोर-टू-डोर सर्विलांस अभियान चलाया गया। प्रेट्र

मुजफ्फरनगर में सिसौली सील, 428 लोग क्वारंटाइन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : उप्र के मुजफ्फरनगर में सिसौली कस्बा निवासी महिला के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने गुरुवार को कस्बे को सील कर दिया। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) अध्यक्ष चौ. नरेश टिकैत, उनके परिवार के सभी सदस्य समेत कुल 94 परिवारों के 428 लोगों को होम क्वारंटाइन किया है। कोराना संक्रमित महिला के परिजनों को मुजफ्फरनगर शहर में क्वारंटाइन किया है। टीम ने जांच के लिए कई के सैंपल लिए हैं।

सिसौली निवासी महिला बुधवार को नोएडा के एक हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। रात्रि में ही पुलिस-प्रशासनिक टीम ने कस्बे में पहुंचकर लोगों को क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया। संक्रमित महिला से मिलने वालों की हिस्ट्री निकाली गई। इससे पता चला कि पहली अप्रैल को महिला नोएडा के अस्पताल में उपचार को गई थी। 6 अप्रैल को ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। इसी बीच चार दिन वह सिसौली में रहीं, जहां उन्होंने बाजार से सब्जी व दैनिक प्रयोग की अन्य वस्तुएं खरीदीं। बैंक में जाने के साथ कस्बे के दो चिकित्सकों के यहां भी गईं। संक्रमित महिला के पति भी इस दरम्यान कई बार बाजार गए। पूरी हिस्ट्री देखी तो पता चला कि महिला सिसौली के 94 परिवारों के 428 लोगों के वह संपर्क में आई। गुरुवार को इन सभी को चिह्नित कर होम क्वारंटाइन किया गया।

sn

कोविड-19 परीक्षण में बहुत पीछे भारत

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण दुनिया के सामने चुनौती है। इस चुनौती से सबसे शक्तिशाली होने का दावा करने वाला अमेरिका भी बच नहीं सका है। वुहान से उपजा कोरोना का जिन्न जब अमेरिका जा पहुंचा है। उसके सामने चुनौती बड़ी है और इससे पार पाने के लिए वह भारत से भी गुहार लगा चुका है। अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या चार लाख को पार कर चुकी है और मौत का आंकड़ा बढ़कर 14 हजार से ज्यादा हो चुका है। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस की पुष्टि के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं। इससे पता लगता है कि कौन कोरोना के संक्रमण से ग्रसित है और कौन है जो सिर्फ सामान्य खांसी-बुखार या वायरल से पीड़ित है। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में कोरोना को लेकर बहुत कम टेस्ट हुए हैं।

कोरोना से जूझती दुनिया

कोरोना के कारण दुनिया के सामने भी बड़ा संकट है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस से 15 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और मौतों का आंकड़ा 85 हजार को पार कर चुका है। हालांकि उम्मीद की किरण वो लोग जरूर नजर आते हैं जो कोरोना संक्रमण से जूझकर लौटे हैं। वैश्विक स्तर पर करीब कोरोना से संक्रमित 3 लाख लोग ठीक हो चुके हैं।

दस लाख पर 121 परीक्षण

दूसरे देशों की अपेक्षा कोरोना संक्रमण का परीक्षण करने में भारत बहुत ही पीछे है। यहां तक की वो सबसे कम परीक्षण करने वाले देशों में शुमार है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार भारत ने 9 अप्रैल तक प्रति दस लाख की आबादी पर महज 121 परीक्षण किए हैं। वहीं इस दिन तक भारत ने कुल 1,67,235 टेस्ट किए हैं।

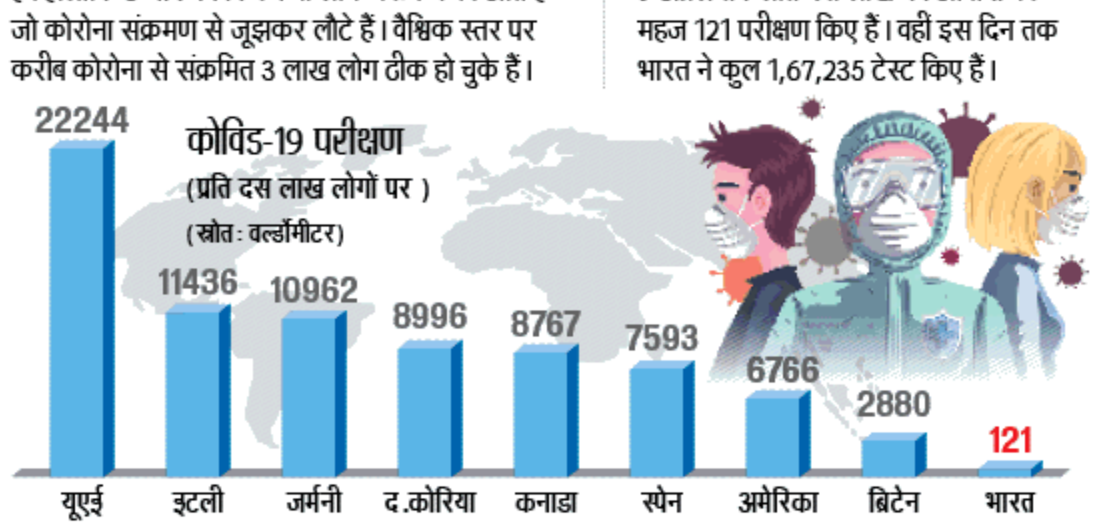

अमेरिका की आलोचना

कोविड-19 महामारी के कम परीक्षण को लेकर अमेरिका की भारी आलोचना की गई है। मार्च के मध्य तक अपने निवासियों के प्रति दस लाख जनसंख्या में से केवल 125 परीक्षण किए थे, जबकि दक्षिण कोरिया ने प्रति दस लाख लोगों में से 5,567 और इटली में 2,514 लोगों के परीक्षण किए। अमेरिका ने अब परीक्षण की पुष्टि की है और कोविड-19 की पुष्टि के मामलों की संख्या जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार 06 अप्रैल तक 3,37,646 थी। सुधार के बावजूद, अमेरिका अभी भी परीक्षण में अन्य देशों से पीछे है और वर्ल्डोमीटर द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, उसने 09 अप्रैल तक प्रति दस लाख लोगों पर 6766 परीक्षण किए थे। यह अभी भी देशों की एक लंबी सूची के पीछे है, जिसमें कनाडा प्रति दस लाख की जनसंख्या पर 8,767 परीक्षण और जर्मनी 10,962 टेस्ट कर रहा है।

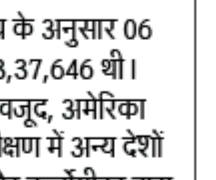

आर्थिक संकट

वकीलों और मुंशियों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट चिंतित

बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूपी बार काउंसिल, प्रमुख सचिव न्याय व बार संगठनों से 15 अप्रैल तक मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

लॉकडाउन में अदालतों की बंदी के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे अधिवक्ताओं व मुंशियों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुधि ली है। कोर्ट ने कहा है कि वकीलों व मुंशियों को राहत की मांग में अर्जियां आ रही हैं। हाई कोर्ट के पास ऐसे संसाधन (फंड) नहीं हैं, जिससे वह इनकी मदद कर सके। सरकार नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है।, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी-रोटी अदालतों पर निर्भर है।

अधिवक्ता अधिनियम के तहत वकीलों की कल्याणकारी योजनाएं बनाने का अधिकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यूपी बार काउंसिल सहित हाई कोर्ट व जिला बार संगठनों की है। उन्हें इस संबंध में कदम उठाना चाहिए। इसको लेकर कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव, यूपी बार काउंसिल के सचिव, प्रमुख सचिव न्याय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव, एडवोकेट एसोसिएशन के सचिव व अवध बार एसोसिएशन के सचिव को नोटिस जारी करके 15 अप्रैल तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि जवाब ई-मेल के जरिए भेजे जाएं। फिर 15 अप्रैल को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस मुद्दे पर सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने जानना चाहा है कि अधिवक्ताओं व मुंशियों की भुखमरी की स्थिति में राहत देने के लिए बार काउंसिल एवं बार एसोसिएशन ने क्या कदम उठाए हैं? कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है। हाई कोर्ट सहित प्रदेश की अदालतें बंद है अदालतों से जुड़े लाखों लोगों की जीविका पर इसका बुरा असर पड़ता दिखाई दे रहा है।

कोर्ट ने अधिवक्ता अधिनियम का हवाला देते हुए कहा की बार काउंसिल ऑफ इंडिया और यूपी बार काउंसिल का दायित्व है वह अधिवक्ताओं के कल्याण की योजनाएं बनाकर उन तक लाभ पहुंचाएं। इसी मद में उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि 1974 में गठित की गई है। ट्रस्टी कमेटी को व्यापक अधिकार प्राप्त है, जो इस फंड का उपयोग अधिवक्ताओं के हित में कर सकती है। ऐसी स्थिति में न्यायिक संज्ञान लेते हुए 15 अप्रैल को बार काउंसिल व बार एसोसिएशनों उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।

कलकत्ता हाई कोर्ट समेत बंगाल की सभी अदालतों में 30 तक नहीं होगी सुनवाई

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

कोरोना महामारी के मद्देनजर कलकत्ता हाई कोर्ट और इसके सर्किट बेंचों में नियमित कामकाज अब 30 अप्रैल तक निलंबित कर दिया गया है। हाई कोर्ट के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

बताया गया है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन ने महामारी की मौजूदा स्थिति पर विचार करते हुए निर्णय लिया है कि 30 अप्रैल तक उच्च न्यायालय का नियमित कामकाज स्थगित रखा जाए। इसके लिए एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें में कहा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जलपाईगुड़ी स्थित कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के साथ-साथ बंगाल की समस्त निचली अदालतों में भी नियमित कार्य निलंबित रहेगा। हाईकोर्ट में 9 से 30 अप्रैल के बीच, पांच दिन - 16 , 21, 23, 28 और 30 अप्रैल को अति आवश्यक व अहम मुकदमों के लिए दो खंडपीठ व तीन एकलपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हो सकती है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल राय चट्टोपाध्याय ने बताया कि दो डिवीजन बेंच और तीन एकल बेंच में अति आवश्यक मामलों की सुनवाई होगी। गौरतलब है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर 25 मार्च से नौ अप्रैल तक कोरोना महामारी की वजह से कार्य स्थगित रखने की घोषणा की थी।

20 अप्रैल के बाद होगी कनिका से पूछताछ, तैयार हो रहे सवाल

जागरण संवाददाता, लखनऊ

▶ डॉक्टरों ने बालीवुड गायिका को 14 दिन तक क्वारंटाइन रहने को कहा

बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर से पुलिस 20 अप्रैल के बाद पूछताछ करेगी। कनिका को डॉक्टरों ने 14 दिन तक क्वारंटाइन रहने को कहा है। इसलिए क्वारंटाइन अवधि पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है। कनिका को पीजीआइ से 6 अप्रैल को छुटटी मिली थी। लखनऊ के सरोजनीनगर थाने के इंस्पेक्टर आनंद कुमार शाही ने बताया कि अभी कनिका की यात्रा का ब्योरा जुटाया जा रहा है। शुरू में कनिका की ओर से दिए गए बयानों को भी पुलिस विवेचना में शामिल करेगी। कनिका से पूछताछ के लिए सवालों की सूची भी तैयार की जा रही है।

कनिका पुलिस की निगरानी में हैं और वह अपने घर न जाकर एक परिचित के यहां ठहरी हैं। पुलिस मुंबई और लखनऊ एयरपोर्ट की फुटेज के आधार पर मामले की विवेचना करेगी। कनिका ने जानबूझकर कोरोना वायरस संक्रमित होने की बात छिपाई थी या नहीं, यह भी पता लगाया जाएगा।

पुलिस के मुताबिक, मुंबई एयरपोर्ट पर कनिका कपूर को क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद वह प्रदेश की राजधानी लखनऊ आकर पार्टियों में शामिल हुई, जो नियमों का उल्लंघन है। कनिका कपूर 11 मार्च को लखनऊ आई थीं। यहां वह तीन पार्टियों में शामिल हुई थीं। विदेश से लौटीं कनिका डालीबाग स्थित आदिल अहमद के यहां 13 मार्च की रात में आयोजित पार्टी में पहुंची थीं, जिसमें कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। कनिका के संपर्क में आए किसी भी व्यक्ति को अब तक संक्रमण नहीं हुआ है, जबकि वह खुद भी कोरोना से मुक्त हो गई हैं और अस्पताल से भी उन्हें छुट्टी मिल चुकी है।

ईएसआइसी के अस्पताल भी चाक चौबंद

तैयारी ▸ देश भर में इन हॉस्पिटलों में 2200 आइसोलेशन और 1200 क्वारंटाइन बेड उपलब्ध

बीमित कर्मचारियों का सामान्य इलाज अनुबंधित अस्पतालों में होगा

जागरण ब्यूरो नई दिल्ली

कोरोना को हराने के प्रयासों में सभी सरकारी विभाग व संस्थान अपने-अपने हिसाब से योगदान दे रहे हैं। इस कड़ी में कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआइसी) के अस्पतालों ने भी अपनी तैयारियां चाक-चौबंद कर ली हैं। ईएसआइ कारपोरेशन के देश भर में फैले अस्पतालों ने अब तक लगभग 2200 आइसोलेशन बेड और 1200 क्वारंटाइन बेड तैयार कर उपलब्ध करा दिए हैं। इतना ही नहीं, ईएसआइसी के फरीदाबाद स्थित अस्पताल में कोविड-19 की जांच के लिए टेस्टिंग लैब भी स्थापित कर दी गई है।

ईएसआइसी प्रवक्ता के अनुसार कोरोना को काबू करने के लिए ईएसआइसी ने सरकार के प्रयासों में सहभागी बनते हुए देश के विभिन्न शहरों में स्थित अपने अस्पतालों में कुल मिलाकर 2154 आइसोलेशन बेड तैयार कर उपलब्ध करा दिए हैं। इनमें से कोरोना के इलाज के लिए विशेष रूप से समर्पित आठ अस्पतालों के 1042 बेड शामिल हैं। सबसे ज्यादा 470 बेड जोका (बंगाल) के ईएसआइसी अस्पताल में तैयार किए गए हैं।

इसके अलावा 100 बेड अंकलेश्वर (गुजरात), 100 बेड (वापी) गुजरात, 100 बेड उदयपुर (राजस्थान), 100 बड बद्दी (हिमाचल प्रदेश) 80 बेड गुरुग्राम (हरियाणा), 50 बेड जम्मू और 42 बेड आदित्यपुर झारखंड में उपलब्ध कराए गए हैं। कोरोना वायरस के पीड़ितों के इलाज के लिए समर्पित आइसोलेशन बेड के अलावा ईएसआइसी के अन्य सामान्य अस्प तालों में भी 1112 आइसोलेशन बेड तैयार कर दिए गए हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाएगा।

राजस्थान में है सबसे ज्यादा क्वारंटाइन बेड : इसके अतिरिक्त 197 वेंटीलेटर समेत कुल 555 आइसीयू/एचडीयू बेड भी इन अस्पतालों में उपलब्ध हैं। क्वारंटाइन सुविधा के लिए 1184 बेड का और इंतजाम विभिन्न ईएसआइसी अस्पतालों की ओर से किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 444 क्वारंटाइन बेड अलवर (राजस्थान) के ईएसआइसी अस्पताल में उपलब्ध हैं। जबकि बाकी में 400 क्वारंटाइन बेड पटना, 240 गुलबर्गा (कर्नाटक) और 100 बेड कोरबा (छत्तीसगढ) के ईएसआइसी अस्पताल में उपलब्ध कराए गए हैं।

विशेष उपचार वाले मामलों में किए जाएंगे अनुबंधित अस्पतालों को रेफर

जिन ईएसआइसी अस्पतालों को कोरोना के इलाज के लिए समर्पित किया गया है, वहां ईएसआइ के बीमित सदस्य कर्मचारियों के सामान्य इलाज की सुविधा नहीं होगी। बीमित कर्मचारियों के सामान्य इलाज के लिए ईएसआइसी ने प्राइवेट अस्पतालों के साथ अनुबंध किए हैं। ऐसे कर्मचारियों को विशेष उपचार वाले मामलों में इन अनुबंधित अस्पतालों को रेफर किया जाएगा। हालांकि आपातकालीन एवं सामान्य चिकित्सा सेवाओं के लिए कर्मचारियों को रिफरल लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी।

लॉकडाउन के दौरान बीमित कर्मचारियों को सुविधा

लॉकडाउन के दौरान जो लाभार्थी अपनी वार्षिक एकमुश्त रकम जमा नहीं करा पाए हों और जिससे उनके ईएसआइसी बीमा कार्ड का नवीकरण न हो सका हो, वे कर्मचारी भी ईएसआइ एक्ट के नियम 60 एवं 61 के तहत मेडिकल सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ईएसआइसी ने स्थायी दिव्यांग लाभ एवं आश्रित लाभ के मद में लाभ प्राप्त करने वाले तकरीबन चार लाख लाभार्थियों का पैसा उनके खातों में डाल दिया है।

नियोक्ताओं को राहत, मई में किया जा सकता है भुगतान

लॉकडाउन के दौरान नियोक्ताओं द्वारा फरवरी का जो योगदान 15 मार्च तक जमा किया जाना था उसकी तारीख अप्रैल अंत तक बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार मार्च का भुगतान मई में किया जा सकता है। जिन नियोक्ताओं ने अप्रैल 2019 से सितंबर, 2019 की अवधि का ईएसआई योगदान नहीं जमा किया है उन्हें एक बार की रियायत के तहत अंतिम तारीख के 42 दिनों के भीतर अर्थात 15 मई 2020 तक योगदान जमा करने की छूट दी गई है।

मास्क के निस्तारण में भी बरतें पूरी सावधानी, धोकर डालें कूड़ेदान में

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ घर में कपड़े से तैयार मास्क का प्रयोग सबसे बेहतर

कोरोना के खिलाफ जंग में मास्क सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। इसका इस्तेमाल जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक सही तरीके से उसका निस्तारण भी है। डॉक्टरों के मुताबिक इस्तेमाल के बाद मास्क को गर्म पानी और साबुन से धोने के बाद ही कूड़ेदान में डालें। अन्यथा यह बहुत ही घातक साबित हो सकता है।

केंद्र सरकार लगातार मास्क पहनने की हिदायत दे रही है। महाराष्ट्र समेत कई सरकारों ने इसे पहनना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन बाजार में मास्क की कमी के कारण लोग परेशान हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जरूरी नहीं कि बाजार से खरीदे मास्क ही पहनें। सबसे अच्छा घर पर कपड़े से तैयार किया गया मास्क है। एन-95 मास्क स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ही जरूरी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. केके अग्रवाल ने कहा कि आम आदमी के लिए सबसे बेहतर है कि घर में तैयार कपड़े का मास्क इस्तेमाल करें। इसे साफ कर दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है।

डॉक्टरों का कहना है कि मास्क के निस्तारण में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अस्पतालों में ब्लीचिंग पाउडर से संक्रमण मुक्त करने के बाद इसे निस्तारण के लिए भेजा जाता है। घर में जरूरी नहीं कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करें। गंगाराम अस्पताल के श्वांस रोग विशेषज्ञ डॉ. बॉबी भलोत्रा ने बताया कि इस्तेमाल किए हुए मास्क को साबुन व गर्म पानी से साफ करने के बाद उसे पॉली बैग में ठीक से पैक करके कूड़ेदान में डालें।

ऐसे साफ करें मास्क : सबसे जरूरी है कि अपने पास दो मास्क रखें। ताकि एक को साफ करने के बाद दूसरे का इस्तेमाल कर सकें। इसे साबुन व गर्म पानी से साफ करने के बाद पांच घंटे तक तेज धूप मे सुखाएं या फिर आयरन से उसे सुखाएं।

मुरादाबाद की जेल सैनिटाइज होने के बाद प्रवेश करेंगे बंदी

जासं, मुरादाबाद

मुरादाबाद की जेल में बंदियों ने खुद ही सैनिटाइजिंग टनल बना दिया है। तीन दिन में बनकर तैयार टनल का ट्रायल सफल रहा। शुक्रवार को टनल शुरू हो जाएगा। इसमें प्लास्टिक की शीट से छत बनी हैं। इसी में स्प्रे लगाया गया है। टनल से ही होकर जेल में प्रत्येक को प्रवेश करने दिया जाएगा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक उमेश सिंह ने बताया कि अब कारागार में टनल से सैनिटाइज होकर ही अफसर, कर्मचारी और बंदी प्रवेश करेंगे। कारागार में कोरोना वायरस से बचाव के लिए शासन ने 10 लाख रुपये का बजट भेजा है। इस बजट का उपयोग कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। जिला कारागार के बंदी अभी तक मास्क और सैनिटाइजर बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन गुरुवार को बंदियों ने सैनिटाइज टनल का निर्माण पूरा कर दिया। जेल के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश होते ही इस टनल से निकलने वालों को चार स्प्रे सैनिटाइज करेंगे।

चार फीट चौड़ी, सात फीट लंबी होगी टनल : जिला कारागार में जिस सैनिटाइज टनल को बनाया गया है। वह चार फीट चौड़ी और सात फीट लंबी है। प्लास्टिक की मोटी शीट से बने इस टनल के अंदर चार फव्वारे लगाए गए हैं। टनल में प्रवेश के साथ ही फव्वारों से सैनिटाइजर निकलने लगेगा। प्रवेश करने वाले को दो से तीन मिनट तक सैनिटाइज होने के लिए टनल में रुकना पड़ेगा। फव्वारा चलाने के लिए एक सिपाही की तैनाती गई है। उत्तर प्रदेश की आठ जेलों में बंदियों ने सैनिटाइज टनल बनेंगे। इनमें गोरखपुर, मेरठ, अयोध्या, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद का नाम शामिल है। मुरादाबाद में सैनिटाइज टनल बनकर तैयार है।

मुरादाबाद जिला कारागार में प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज टनल बनाते बंदी। (सौजन्य से जेल प्रशासन)

सर्वे ने बताया देश का विचार

लॉकडाउन के लिए 77 फीसद साथ

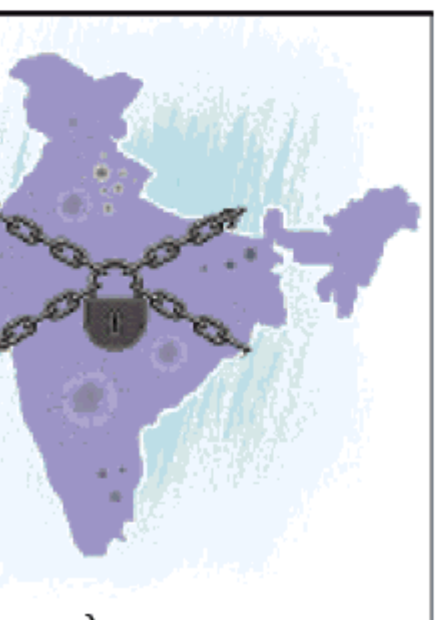

भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन करीब-करीब पूरा होने को है। देशव्यापी लॉकडाउन कब और कैसे उठाया जाएगा, इसे लेकर केंद्रीय स्तर पर चर्चा की जा रही है। वहीं आम लोगों में यह सर्वाधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी स्थिति में लोकल सर्कल्स ने देश के लोगों के विचारों को जानने के लिए एक सर्वे किया है। इस सर्वे में देश के 280 जिलों के 11,386 वोट मिले हैं। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि भारत सरकार को 15 अप्रैल से लॉकडाउन किस तरह से हटाना चाहिए।

लॉकडाउन बढ़ाने पर देश की राय

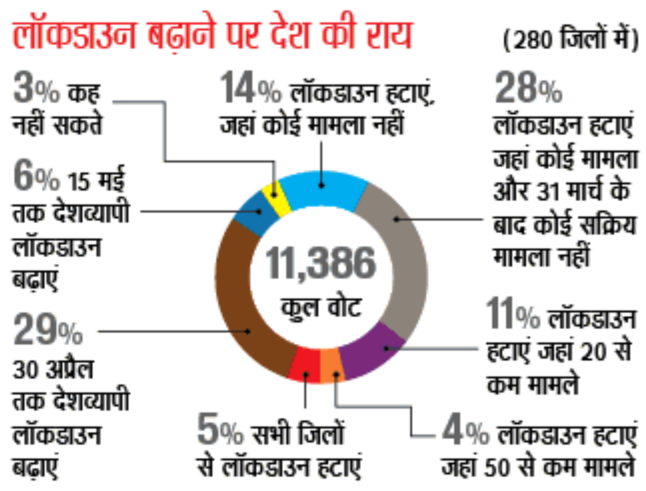

ये है निष्कर्ष

सर्वेक्षण के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि 77 फीसद लोग चाहते हैं कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 14 अप्रैल के बाद भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। हालांकि सरकारी स्तर पर भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। यदि लोग चाहते हैं तो सरकार को भी ऐसा करने में आसानी होगी।

लॉकडाउन हटाने पर जनता का मत

सर्वे में शामिल 29 फीसद लोगों का मत था कि देशव्यापी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक और 6 फीसद ने 15 मई तक बढ़ाने की बात कही है। इसके अतिरिक्त 14 फीसद ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ ऐसे जिलों से लॉकडाउन हटाना चाहिए जहां पर कोई मामला नहीं है। 28 फीसद का मत था कि सरकार को उन सभी जिलों से लॉकडाउन हटाना चाहिए जहां पर कोई मामला नहीं है और किसी भी जिले में 31 मार्च के बाद कोई सक्रिय मामला सामने नहीं आया है। सर्वे में 11 फीसद चाहते हैं कि सरकार उन सभी जिलों को अनलॉक करे जहां पर 20 से कम मामले हैं, जबकि 4 फीसद ने 50 से कम मामलों वाले जिलों को अनलॉक करने की बात कही है। सर्वे में महज 5 फीसद लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मामलों की संख्या की परवाह किए बिना सभी जिलों को 15 अप्रैल से अनलॉक किया जाना चाहिए। 3 फीसद ने अपनी राय नहीं दी।

चला जाए स्वाद, न आए महक तो हो जाएं सतर्क

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ कोरोना वायरस के संक्रमण का लक्षण हो सकती हैं ये स्थितियां

कोरोना वायरस के संक्रमण का लक्षण बड़ा रहस्य बना हुआ है। विशेषज्ञ भी यकीनी तौर पर कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं। रोज नई-नई बातें सामने आ रही हैं। ज्यादातर पीड़ितों में बुखार, गला खराब व खांसी होने की समस्या देखी जा रही है। यह बात भी सामने आ रही है कि संक्रमण होने पर स्वाद और सूंघने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। हालांकि कई अन्य बीमारियों में भी स्वाद खराब हो जाता है और किसी चीज की महक पता नहीं चलता, लेकिन दोनों स्थितियों में अंतर है।

डॉक्टरों का कहना है कि सामान्य बीमारियों में दवा के इस्तेमाल के बाद यह समस्या आती है, लेकिन कोरोना में यह पहले ही हो जाता है। गंगाराम अस्पताल के चेस्ट फिजिशियन डॉ. बॉबी भलोत्रा ने बताया कि बुखार, सूखी खांसी, गला खराब होना, छाती में दर्द व सांस लेने में परेशानी इसके प्रमुख लक्षण देखे जा रहे हैं। कई शोधों में यह बात सामने आ चुकी है कि संक्रमित व्यक्ति में स्वाद व सूंघने की क्षमता प्रभावित होती है। यह लक्षण सबसे पहले आता है।

कुछ मामलों में 25 दिन तक पाया गया इंक्यूबेशन पीरियड : डॉ. बॉबी भलोत्रा ने कहा कि सामान्य तौर पर दो से 14 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना गया है। यानी कोई व्यक्ति संक्रमित होने के 14 दिन तक दूसरों में बीमारी फैला सकता है। लेकिन कुछ मामलों में इंक्यूबेशन पीरियड 25 से 28 दिन तक देखा गया है। कई लोगों में बीमारी के लक्षण सामने नहीं आ पाते। वे देखने में स्वस्थ लगते हैं, लेकिन वायरस के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. केके अग्रवाल ने कहा कि इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन माना गया है, लेकिन कुछ मामलों में नए तथ्य सामने आए हैं।

किसी को हल्का तो कुछ को तेज बुखार : अपोलो अस्पताल के श्वांस रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेश चावला ने कहा कि सिर्फ 15 फीसद मरीज को ही ऑक्सीन की जरूरत पड़ रही है। इनमें ज्यादातर बुजुर्ग होते हैं। कोरोना से पीड़ित कुछ लोगों में 99 व 100 डिग्री फारेनहाइट बुखार देखा जा रहा है।

तकनीक की मदद से प्रवासी बिहारियों का सहारा बन रहा बिहार फाउंडेशन

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

बिहार सरकार से संबंधित संस्था बिहार फाउंडेशन इन दिनों बिहार के प्रवासियों के लिए न सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि पूरे देश में वरदान साबित हो रही है। करीब 10 राज्यों में लॉकडाउन के कारण अटके बिहार के लोगों को तकनीक की मदद से राशन एवं आर्थिक मदद आदि पहुंचाई जा रही है।

बिहार फाउंडेशन के सीईओ भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी आरएस श्रीवास्तव एक घटना का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि पुणे में फंसे किसी व्यक्ति का मदद के लिए फोन आया। उसे राशन की जरूरत थी, लेकिन वह मोबाइल तकनीक से ज्यादा परिचित नहीं था। उसे नजदीकी राशन की दुकान तक जाने के लिए कहा गया। बिहार फाउंडेशन के कार्यकर्ता के कहने पर दुकानदार ने जरूरतमंद व्यक्ति की फोटो खींचकर उसके आधार नंबर और अपने बिल के साथ कार्यकर्ता को भेज दिया। कुछ मिनटों में ही दुकानदार के खाते में भीम एप के जरिये 788 रुपये पहुंच गए और दुकानदार ने इतनी कीमत का राशन जरूरतमंद व्यक्ति को सौंप दिया। इसी प्रकार जो व्यक्ति मोबाइल तकनीक का उपयोग करना जानता है उसे फाउंडेशन के कार्यकर्ता बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए आपदा मदद एप के जरिये पूरे 1000 रुपये की मदद चंद मिनटों में पहुंचाते हैं। श्रीवास्तव ने कहा कि बुधवार शाम तक आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से देश भर में फंसे बिहार के प्रवासी श्रमिकों तक 10 करोड़, 35 लाख रुपये की मदद पहुंचाई जा चुकी है। श्रीवास्तव कहते हैं कि कोरोना जैसी आपदा के समय में दो चीजें सीखने को मिलीं। एक तो वस्तुओं का विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। दूसरा तकनीक का उपयोग बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से भुगतान का आश्वासन दिए जाने के बावजूद जब बड़े-बड़े स्टोर्स ने राशन आपूर्ति में असमर्थता जता दी, तो गली-नुक्कड़ के परचून दुकानदार काम आए। इन्हीं से राशन लेकर आज बिहार फाउंडेशन देश भर में प्रतिदिन 30,000 लोगों को भोजन करवा रहा है और प्रतिदिन 2000 पैकेट राशन (एक पैकेट में 21 दिन का निर्धारित राशन होता है) बंटवा पा रहा है। इसी प्रकार तकनीक की मदद से 10 राज्यों में बैठे अपने 500 कार्यकर्ताओं के साथ यह संगठन राहत कार्यों का बेहतर संयोजन कर रहा है।

यह मुहिम बिहार फाउंडेशन से जुड़े कार्यकर्ताओं एवं बिहार मूल के धनाढ्य लोगों को मदद के लिए प्रेरित कर रही है। अन्य राज्यों में फंसे बिहारी श्रमिकों की मदद के लिए आपदा प्रबंधन विभाग एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष सामने आ रहा है। फाउंडेशन के मुंबई चैप्टर के चेयरमैन अभय कुमार के अनुसार लॉकडाउन शुरू होने के बाद से धारावी में चल रहा प्रवासी किचन प्रतिदिन 1000 प्रवासी श्रमिकों को भोजन उपलब्ध करा रहा है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर महाराष्ट्र सरकार से भी बात कर इधर-उधर फंसे श्रमिकों को मदद मुहैया करा रहा है।

जनमत
मुद्दा

क्या कोरोना की जंग में अनमोल मानव संसाधनों को बचाकर हम फिर से अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई आसानी से करने में सक्षम होंगे?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं।

बच्चों की भावनात्मक अस्थिरता को समझें

कोरोना से कैसे लड़ें मनोवैज्ञानिक की सलाह

डॉ. प्रीति सिंह
क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट, पारस अस्पताल

दिल्ली की ज्योति अजमेरा वर्किंग हैं। बेटा नौंवीं कक्षा में पढ़ता है और बेटी दसवीं में। ज्योति को इस वक्त ऑफिस व घर के काम से ज्यादा बच्चों के बीच विवाद और उनकी कड़वी बातें परेशान कर रहीं हैं। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक इस माहौल के लिए हालात के सिवा कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में थोड़ा धैर्य रखकर माता-पिता बच्चों के नकारात्मक भावनाओं को संभाल सकते हैं और परिवार के लिए शांतिपूर्ण माहौल बना सकते हैं। इस बारे में पारस अस्पताल की क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. प्रीति सिंह ने बताया कि बच्चों की भावनाओं को समझते हुए उन्हें मनमाफिक माहौल व उनका स्पेस देकर उनसे दोस्ती की जा सकती है।

मूड स्विंग को समझें

किशोरावस्था में हार्मोनल बदलावों की वजह से बच्चों में चिडचिड़ापन आ जाता है। इस अवस्था में भावनात्मक उतार-चढ़ावों और अस्थिरता आ जाती है जिसे वे स्वयं आम दिनों में भी हैंडल नहीं कर पाते और बात-बात पर गुस्सा हो जाते हैं। अब इस होम आइसोलेशन में उनमें भावनात्मक अस्थिरता बढ़ेगी तो अभिभावकों को यह चाहिए कि उनकी भावनाओं को समझें। उन्हें बात-बात पर डांटें नहीं बल्कि उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें समझने का प्रयास करें।

बच्चों को दें स्पेस

आमतौर पर माता पिता बच्चों पर पूरी निगरानी रखते हैं। उनके पीछे-पीछे लगे रहते हैं, उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। इस होम आइसोलेशन में बच्चे अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, पार्टी नहीं कर पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं तो उनकी कुंठा और बढ़ रही है। उन्हें इस वक्त में थोड़ा अलग से स्पेस दें। उन्हें जो करना है करने दें, दोस्तों से फोन पर बात करने से न रोकें।

इंटरनेट उपयोग पर रोक टोक न करें

किशोरों के पास अभी मनोरंजन के लिए इंटरनेट के अलावा कोई साधन नहीं है। उन्हें इंटरनेट का उपयोग करने पर आम दिनों की तरह पाबंदी न लगाएं। हां, नजर जरूर रखें कि कहीं वे साइबर क्राइम के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं।

उनसे करें दोस्ती

बच्चों से दोस्ती करने का इससे बेहतर समय और अवसर नहीं मिलेगा। उनके दोस्तों, उनकी परेशानियों पर रसोई में उनसे मदद लेते हुए बात करें। काम का बोझ भी कम होगा, बच्चों में स्किल्स भी विकसित होंगी। मूड भी संतुलित हो सकेगा।

● प्रस्तुति: गुरुग्राम से **प्रियंका दुबे मेहता**

सलाह

अमेरिका से हापुड़ की प्रियंका ने दैनिक जागरण से फोन पर साझा किए कोरोना से लड़ने के अनुभव, कहा-अद्भुत है, पीएम मोदी का पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन का फैसला

समझदार बनें, घर में रहें और लक्ष्मण रेखा न लांघें

मनोज त्यागी, हापुड़

'भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन किया है। यह अद्भुत है। हम न्यूयार्क से तीन सौ किमी दूर रोचेस्टर में रहते हैं। हम 15 मार्च से अपने घर में लॉकडाउन हैं। घर से बाहर कदम नहीं रखा है। इसलिए हम सुरक्षित हैं। सभी सुविधाएं होने के बाद भी यहां कई लोग संक्रमित पाए गए हैं। जबकि अभी तक 34 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। अभी भी यहां लगातार संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है और मौतें भी हो रहीं हैं।

भारत में अभी भी कुछ लोग कोरोना का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि कोरोना अमीर-गरीब, धर्म-जात नहीं देखता।' यह बातें हापुड़ निवासी प्रियंका ने पर फोन दैनिक जागरण से कहीं। आगे कहा कि हमें जब घर में बोरियत होती है तो घर की खिड़की से दूसरी ओर देखकर मन को खुश कर लेते है। लेकिन किसी भी हाल में लक्ष्मण रेखा का उलंघन नहीं करते हैं। अमेरिका में लॉकडाउन है, लेकिन जरूरत के सामान की सभी दुकानें हर समय खुली रहती हैं। यही कारण है कि यहां लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं।

पीएम मोदी को दिया धन्यवाद : प्रियंका ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने किसी की परवाह किए बिना पूरे देश को एक साथ लॉकडाउन किया है। पूरे देश को एक साथ लॉकडाउन का असर इससे भी देखा जा सकता है कि भारत में अमेरिका की तरह मामले नहीं बढ़ रहे हैं। जबकि अमेरिका में भारत के मुकाबले सभी सुविधाएं बेहतर हैं। लॉकडाउन से सभी एक दूसरे से दूर हो गए और कोरोना को दूसरों के संपर्क में आने का मौका नहीं मिला।

तुरंत नहीं उठाते हैं सामान : अमेरिकी सरकार ने 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा दे रखी है। घर के सभी सामान ऑनलाइन मिल जाते है। यह बात जरूर है कि सामान आने में एक सप्ताह का समय लग जाता है। बहुत जरूरी सामान होता है तो 24 घंटे में भी मिल जाता है। घर में आने वाले सूखे सामान को तो कम से कम दस घंटे घर के बाहर ही रखते हैं। जो गीला सामान होता है उसे सीधे नहीं उठाते हैं, बल्कि उसे उठाने से पहले हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, फिर सामान को सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद फ्रिज में रखते हैं। अधिकांश लोग वर्क फ्राम होम ही कर रहे हैं। इसके बाद भी कोरोना वायरस का आतंक समाप्त नहीं हो रहा है।

प्रतिदिन घर वालों का जानती हूं हाल : कहा कि घर वालों से बात कर उनका प्रतिदिन हाल जानती हूं और उनसे लगातार हाथ सैनिटाइज करने, घर से बाहर न निकलने के लिए कहती हूं। साथ ही उनसे यह भी कहती हूं कि दूसरे लोगों को फोन करके उनसे भी आग्रह करें कि वह भी घर के अंदर ही रहें। तभी इस कोरोना से जंग जीती जी सकती है।

जो लोग कोरोना की मार को नहीं समझ रहे हैं। वह समझदार बनें। एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। वह एक साथ इकट्ठा न हों। कम से कम छह फीट की दूरी बनाकर रखें। हाथों को कई बार सैनिटाइज करें। यही कोरोना का इलाज है।

– प्रियंका, रोचेस्टर (अमेरिका) से फोन पर

अमेरिका के रोचेस्टर में रह रहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी प्रियंका। सौ. प्रियंका

आइआइटी भिलाई ने तैयार की किफायती पीपीई किट

नईदुनिया, रायपुर: छत्तीसगढ़ में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आइआइटी) भिलाई ने महज 350 रुपये में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट (पीपीई) किट तैयार कर दी है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर रहे स्वास्थ्यकर्मी इसका दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे खुद को सिर से सीने तक कवर (ढका) किया जा सकता है।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग ने जो किट तैयार की है, उसमें कोरोना वायरस को रोकने का भी दावा किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक रजत मूणा का कहना है कि हमने जो किट बनाई है, उसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद दूसरी बार भी इस्तेमाल (रि-यूल्ड) कर सकते हैं। आइआइटी भिलाई ने इस किट की जानकारी केंद्रीय विज्ञान एवं प्राद्योगिकी मंत्रालय को भी दी है। आइआइटी भिलाई ने मंत्रालय को जानकारी दी है कि इस किट का इस्तेमाल डॉक्टर, नर्सिंग स्टॉफ और खासकर ऐसे स्वास्थ्यकर्मी, जोकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनके लिए फायदेमंद है।

यह है विशेषता : इसमें एन-95 मॉस्क में इस्तेमाल होने वाला फिल्टर लगा हुआ है। यह सिर से सीने तक व्यक्ति को कवर कर सकती है। यह शुद्ध हवा भीतर जाने देती है और वायरस को रोकती है। इसको पहनने पर सांस लेने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। यहां जो किट बनाई गई है, वह दो टाइप की है। पहली हेलमेट टाइप पीपीई किट है, जिसकी कीमत 200 रुपये है और यह चेहरे को ढक लेती है। इसी तरह दूसरी फेस सील टाइप पीपीई किट है, जिसकी कीमत 350 रुपये है।

फिर मुस्कुराएगा इंडिया..., गुनगुना रहा देश

बिहार के युवक का लिखा गाना वायरल, आम और खास सभी गुनगुना रहे, पीएम भी कर चुके हैं ट्वीट

जागरण विशेष

अक्षय पांडेय, पटना

बिहार के एक युवक ने गीत लिखा- फिर मुस्कुराएगा इंडिया...। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने ट्वीट कर लिखा- फिर जीत जाएगा इंडिया...। प्रधानमंत्री की तरह ही देश के लाखों लोगों को यह गीत बेहद पसंद आ रहा है। यूट्यूब और अन्य सोशल साइट्स पर इसे लाखों व्यूज मिल रहे।

'फिर मुस्कुराएगा इंडिया' गीत को अभिनेता अक्षय कुमार और जैकी भगनानी ने प्रोड्यूस भी किया है। आवाज व म्यूजिक कंपोजिंग विशाल मिश्रा की है। बिहार के पूर्वी चंपारण के रहने वाले कौशल किशोर बताते हैं कि देश में कोरोना के विरुद्ध चेतना जगाने के उद्देश्य से यह गीत लिखा। अब बॉलीवुड के सितारे इसके बहाने एकजुट होकर संदेश दे रहे हैं। वीडियो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। पीएम ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर लिखा है, फिर मुस्कुराएगा इंडिया... फिर जीत जाएगा इंडिया...।

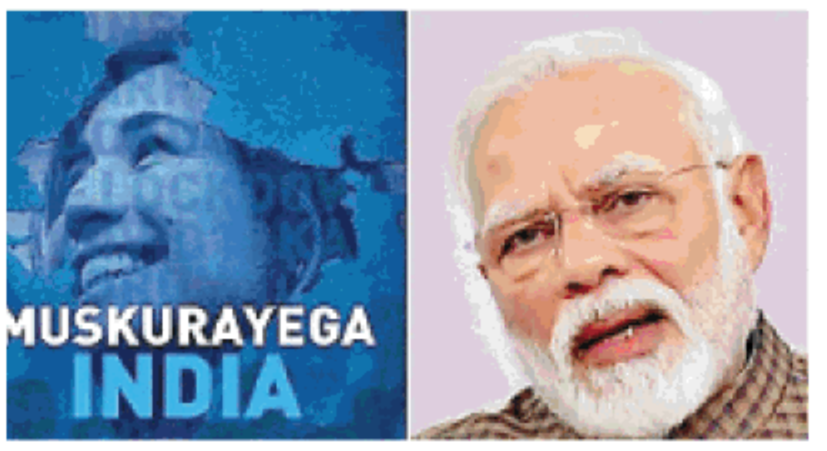

कौशल किशोर के गीत पर आधारित एल्बम जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा। सौ. ट्विटर

पटना से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले लेखक कौशल किशोर के इस गीत को गुनगुनाते हुए अक्षय कुमार, विकी कौशल, आयुष्मान खुराना, शिखर धवन, कार्तिक आर्यन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, भूमि पेडनेकर, तापसी पन्नू, राजकमार राव, टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन जैसे सितारे जागरूकता फैला रहे हैं। कौशल कहते हैं कि फिर शहरों में रौनक आएगी, फिर से गांवों में लौटेगी हंसी... जैसे बोल से शुरू होता गीत देश को समर्पित है।

वह कहते हैं कि संकट की घड़ी में लोगों को हौसला देने की जरूरत है। 3.24 मिनट के गीत में जो साथ दे सारा इंडिया तो मुस्कुराएगा इंडिया... जैसे बोल हमारी एकता को दर्शाते हैं। गीत में मैंने शहर के ठहरे जीवन से लेकर खेल के मैदान और गांव का जिक्र किया है।

कौशल कहते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा गाने के कुछ बोल ट्वीट करना मेरे लिए बड़ी बात है। कौशल ने इसके पहले सलमान खान की फिल्म नोटबुक के लिए भी दो गाने लिखे थे, जो काफी पसंद किए गए थे। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र के लोगों और हस्तियों से बात की थी और समाज में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता फैलाने की अपील की थी। यह गीत उसी अभियान को आगे बढ़ाता है।

कौशल किशोर। सौजन्य : ट्विटर

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

भाजपा सांसद की बेटी ने कहा, योग व प्राणायाम से हराया कोरोना

बेंगलुरु, प्रेट्र : कोरोना वायरस को मात देकर घर लौटाने वाली कर्नाटक के एक भाजपा सांसद की बेटी ने कहा कि हॉस्पिटल में क्वारंटाइन के दौरान भी उन्होंने योग और प्राणायाम किया, जिससे उन्हें ठीक होने में मदद मिली।

दावणगेरे के सांसद जीएम सिद्धेश्वर की बेटी जीएस अश्विनी ने कहा, 'मैं अस्पताल में 14 दिनों तक रही। इस दौरान मैं योग और प्राणायाम करती थी। इससे मुझे बहुत मदद मिली। योग और प्राणायाम सभी लोगों को करना चाहिए।' उनका एक वीडियो संदेश गुरुवार को वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस कुछ ऐसा नहीं था, जिससे डरने की जरूरत थी। योग, प्राणायाम और मजबूत मानसिक स्तर ने इसे हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में हर किसी को अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए क्योंकि जैसे ही विश्वास डगमाया ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। अश्विनी पिछले महीने गुयाना से लौटने के बाद कोरोना संक्रमित पाई गई थीं। उन्हें 14 दिनों के लिए एसएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा, 'अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मुझमें कोरोना वायरस का कोई लक्षण नहीं पाया गया। न तो मुझे सर्दी थी, न ही कफ था और न ही मेरी नाक बह रही थी। यहां तक कि मुझे बुखार भी नहीं था।'

प्रियंका ने चार कोरोना फाइटर्स को दिए एक लाख डॉलर

नई दिल्ली, एएनआइ : फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने कोरोना वायरस से जंग लड़ने वाली चार सशक्त महिलाओं की कहानी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उन्हें एक लाख डॉलर (करीब 76 लाख रुपये) देने का ऐलान किया है। उन्होंने उन चारों का नाम लेते हुए बताया कि वो इस महामारी के दौर में किस तरह लोगों की मदद कर रही हैं।

इन चारों महिलाओं की कहानी इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, 'धन्यवाद, सभी को इन सशक्त महिलाओं की कहानी को साझा करने के लिए, आप सभी ने उन्हें नामित किया। आज के महामारी के दौर में उन्होंने जिस तरह से अपना योगदान दिया है वो काबिले तारीफ है। इस हफ्ते हम चार महिलाओं की स्ट्रगल कहानी के बारे में आपको दिखाएंगे। सभी लोग प्लीज मिलें... एमिली जो जरूरतमंदों की मदद कर रही हैं और अपने परिवार से भी अलग रह रही हैं ताकि वो सुरक्षित रहें।' उन्होंने आगे एक जो नाम की महिला के बारे में बताते हुए कहा कि वह डॉक्टरी के पेशे से जुड़ी हैं और मरीजों का ख्याल रखती हैं। वहीं जया नाम की एक महिला ने अपना समय और पैसा एन95 मॉस्क बंटवाने में खर्च कर दिया जो उसे खरीद नहीं सकते थे। चौथी सशक्त महिला का नाम है जेनी।

प्रियंका चोपड़ा। फाइल

वह जरूरतमंद लोगों तक खाना और बाकी की जरूरी चीजें पहुंचाती हैं।

दरअसल कुछ समय पहले प्रियंका चोपड़ा ने कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए 1,00,000 डॉलर का दान देने का फैसला किया था। ये दान उन्होंने चार ऐसी महिलाओं को देने का वादा किया था जो महामारी के वक्त लोगों की बढ़चढ़ कर मदद कर रही हैं। उन्होंने हर हफ्ते चार सशक्त महिलाओं कि कहानी को उजागर करने का वादा भी किया था और इस हफ्ते उन्होंने चार महिलाओं के संघर्ष की कहानी को भी साझा किया। इनकी प्रेरणादायक कहानियां बाकी महिलाओं को कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगी। इन सभी महिलाओं ने महामारी के इस दौर में अपने-अपने तरीके से लोगों की सहायता की है और कर रही हैं।

कोरोना से लड़ने को दान कर दी जीवनभर की पूंजी

शत-शत नमन ▸ उत्तराखंड की देवकी भंडारी ने जमा कराया दस लाख का चेक

ललिता प्रसाद लखेड़ा, चमोली

कोरोना महामारी के खिलाफ छिड़ी जंग में खास ही नहीं, आम लोग भी खुलकर भागीदारी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं, जिन्होंने जीवनभर की कमाई इस यज्ञ में होम कर दी। इन्हीं में से एक हैं चमोली, उत्तराखंड के गौचर की रहने वालीं 60 वर्षीय देवकी भंडारी। उन्होंने बुधवार को दस लाख रुपये की राशि का चेक पीएम केयर फंड में दान किया। यह उनके जीवनभर की जमापूंजी थी।

स्वस्थ समाज

यहां कुछ निर्धन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का जिम्मा संभाल रहीं देवकी सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भागीदारी करती हैं। मूलरूप से बच्छणस्यूं पट्टी (रुद्रप्रयाग) की रहने वाली हैं। वर्तमान में गौचर नगर पालिका क्षेत्र में किराये के मकान पर रहती हैं। उनके पति हुकुम सिंह भंडारी रेशम विभाग में बाबू थे, जिनका 12 साल पहले देहांत हो गया। इसके बाद देवकी ने समाज सेवा को ही जीवन समर्पित कर दिया। क्षेत्र के लोग उन्हें लोग देवकी दीदी के नाम से जानते हैं।

बताती हैं कि समाचार माध्यमों से उन्हें कोरोना की विकरालता का पता चला तो उनके मन में भी संकट के इस कठिन दौर में देश के लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा हुआ। फिर प्रधानमंत्री केयर फंड के बारे में पता चला तो संकल्प किया कि जो भी पास में है, सब दान कर देंगी। बुधवार को वह गौचर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पहुंचीं और अपनी व पति की जमापूंजी को दान करने की पेशकश की। इस पर बैंक कर्मियों ने उन्हें जमा पर्ची भरने को कहा। देवकी ने जब पीएम केयर फंड में दस लाख रुपये जमा करने की बात कही तो बैंककर्मी व अधिकारी अपनी कुर्सियों से उठ गए और उनकी दानवीरता को नमन किया। बकौल देवकी, इस संकट काल में हम सभी का फर्ज है कि देश के लिए, देश के लोगों के लिए और मानवता की रक्षा के लिए कुछ न कुछ योगदान अवश्य करें। अपने-अपने स्तर से सभी कोरोना के खिलाफ जंग में देश और प्रधानमंत्री के साथ खड़े होंगे तो देश इस बाधा को भी आसानी से पार कर लेगा। देवकी के पिता आजाद हिंद फौज में थे। पालिका सभासद अनिल नेगी ने बताया कि देवकी दीदी की अपनी कोई संतान नहीं है और वह निर्धन बच्चों को पठन-पाठन में लगातार मदद करती हैं।

पीएम केयर फंड में जीवनभर की जमा पूंजी दान करने वाली गौचर निवासी देवकी भंडारी। जागरण

मिल रही सराहना : केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री और उत्तराखंड से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को जब देवकी भंडारी की दानशीलता की जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर देवकी की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। उन्होंने लिखा, मुझे अपनी इस मातृशक्ति पर गर्व है। भारत माता की इस दानवीर रत्न और इनके समर्पण भाव को मैं शत-शत नमन करता हूं।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

आइआइएससी, आइआइटी ने मोबाइल एप डेवलप किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आइआइएससी) बेंगलुरु और चार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आइआइटी) ने देश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए 'गोकोरोनागो' से लेकर 'संपर्क-ओ-मीटर' समेत कई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किए हैं। आइआइएससी की एक टीम ने एप 'गोकोरोनागो' डेवलप किया है जिससे कोविड-19 के पथ से गुजरने वाले व्यक्ति की पहचान की जा सकती है।

आइआइएससी के फैकल्टी सदस्य तरुण रंभा ने कहा, 'यह एप उस व्यक्ति की पहचान कर लेगा जो कोरोना-19 पॉजिटिव व्यक्ति या संदिग्ध के संपर्क में आया होगा। पूर्व में ब्लूटूथ और जीपीएस के इस्तेमाल से उनके संपर्क को पकड़ा जा सकेगा। खतरे की प्रवृत्ति और यहां तक कि दूर संपर्क को समझने के लिए यह सामयिक नेटवर्क विश्लेषण का इस्तेमाल करता है। यह बीमारी के प्रसार को समझता है और ऐसे जोखिम वाले लोगों की पहचान करता है जो वायरस फैला सकते हैं।'

आइआइटी रोपड़ के बीटेक के एक छात्र ने मोबाइल आधारित एप 'संपर्क-ओ-मीटर' डेवलप किया है। यह एप नक्शे पर कोरोना वायरस संक्रमण की अधिकतम आशंका वाले क्षेत्रों का संकेत दे सकता है। विभिन्न फैक्टरों पर विचार करने के बाद एप रिस्क स्कोर तैयार करेगा। इतना ही नहीं, लोगों को सेल्फ आइसोलेट या डॉक्टर से संपर्क करने समेत सतर्कता के उपाय करने के लिए यह एप सतर्क भी कर सकता है।

कोरोना के विजेता

चांद की धरती से उम्मीद की रोशनी बने दो भाई

वैश्विक महामारी कोरोना पर सख्त जान लद्दाखी भारी पड़ गए। कोरोना को मात देकर लेह के चुशौत गांव के दो भाई भी इस जीत के नायक बने हैं। इन भाइयों के बीमारी से लड़ने के जज्बे ने अन्य मरीजों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ में भी कोरोना से जीत की उम्मीद जलाई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद दोनों सगे भाई लेह के चोगलमसर में होटल में क्वारंटाइन हैं। सुनिए उन्हीं की जुबानी कोरोना से जीत की कहानी:

रिश्तेदार के संपर्क में आने से हुआ संक्रमण

लद्दाख में मार्च माह के आरंभ में ही कोरोना का संक्रमण पहुंच गया था। पिता में संक्रमण के बाद हम दोनों भाइयों में भी संक्रमण की पुष्टि हुई। हमें यह संक्रमण ईरान से जियारत कर लौटे एक करीबी रिश्तेदार के संपर्क में आने से हुआ था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पहले तो बहुत डर लगा लेकिन संक्रमितों के ठीक होने के किस्सों से हिम्मत बंधी फिर हमने भी खुद पर विश्वास दिखाया और जज्बे से जंग लड़ी।

शुरुआत में सख्ती से मिले नतीजे

पहला मामला आने के बाद ही गांव को सील कर दिया गया था। सख्ती से सुनिश्चित किया गया कि मेल-मिलाप से यह संक्रमण आगे न फैले। फिर हमें अस्पताल में पता चलता था कि बहुत कम नए मरीज आ रहे हैं। इससे हौसला बढ़ता गया। डॉक्टरों व स्टाफ ने भी दिन रात मेहनत की। इसके नतीजे सामने हैं। एक महीने से यहां सख्ती है, लोगों ने भी पूरा सहयोग दिया, इसके नतीजे सामने हैं। बस इंतजार है कि पिताजी भी ठीक होकर जल्दी आ जाएं और एक बार फिर हम सभी लोग पहले जैसी जिंदगी बिताएं। अभी पिताजी अस्पताल में हैं तो मां और बहन गांव में क्वारंटाइन हैं।

अभी कुछ दिन और क्वारंटाइन में

अस्पताल में जो डॉक्टरों ने कहा, उनकी सारी सलाह मानी। एक विश्वास हमेशा मन में रहता था कि ठीक होना है और जल्द से जल्द घर पहुंचना है। दवाओं ने शरीर स्वस्थ रखा तो विश्वास से मन को। अब जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं हो जातीं तब तक क्वारंटाइन में रहेंगे।

● प्रस्तुति : जम्मू से **विवेक सिंह**

नवजन्मे बच्चों का दस दिन तक नहीं किया दीदार

एसडीएम अमित कुमार।

कोविड 19 को हराने में जुटे अधिकारी न केवल दिन-रात एक कर रहे हैं, बल्कि पारिवारिक जिंदगी में भी कई त्याग कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं 2016 बैच के आइएएस अधिकारी अमित कुमार पंचाल। नकोदर में कर्फ्यू और सरकारी आदेशों को लागू करवाने के लिए जब वह पुलिस टीम के साथ फ्लैग मार्च कर रहे थे तो उसी समय इसी शहर में उनकी पत्नी का सिजेरियन ऑपरेशन चल रहा था। उनकी पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। यह डिलीवरी प्री-मेच्योर थी और उसके बाद दोनों नवजन्मे बच्चों को एक हफ्ते तक अस्पताल की नर्सरी में भर्ती किया गया। पंजाब में 23 मार्च को कर्फ्यू लगा और 25 मार्च को एसडीएम अमित की पत्नी का सिजेरियन हुआ। क्योंकि वह लगातार ड्यूटी के लिए फील्ड में जा रहे थे और लोगों से मिल रहे थे इसलिए कोरोना संक्रमण से बचाव के चलते न तो 10 दिन तक पत्नी से मिले और न ही नवजन्मे बच्चों का दीदार किया। अब भी वह सुबह पांच बजे से रात को करीब दो बजे तक लगातार अपने क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं।

कोरोना के योद्धा

कर्फ्यू के दौरान राशन इकट्ठा करने व जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए एसडीएम अमित कुमार द्वारा तैयार करवाया नेकी का रथ।

पूरा देश हमारा परिवार

एसडीएम अमित कुमार कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार ही है। लोग घरों में बैठकर प्रशासन पर भरोसा जता रहे हैं तो हम भी उनका भरोसा किसी कीमत पर तोड़ नहीं सकते। परिवार के बारे में बताते हैं कि अब भी बच्चों को छूता नहीं हूं, बस स्नान करने के बाद दूर से निहार लेता हूं। पहले कोरोना से जंग जीतेंगे और फिर बच्चों को समय देंगे। अभी नकोदर में कोई पीड़ित नजर नहीं आया है। कोशिश है कि आगे भी लोग इसी तरह सुरक्षित रहें।

नेकी के रथ से लोगों की मदद

लोगों से मदद लेने और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अनोखी पहल करते हुए नेकी का रथ चलाया है। छोटे हाथी पर बना यह रथ पूरे नकोदर में घूमता है। जिस किसी को सूखे राशन की मदद देनी हो, वो इसमें डाल देता है और जिसे राशन की जरूरत हो वह रथ रुकवाकर राशन ले लेता है। मुश्किल घड़ी में मदद करने वालों से जुड़ाव रहे, इसलिए राशन देने वालों के नंबर ले लिए जाते हैं। इसके बाद शाम को उन्हें फोन करके प्रशासन की तरफ से मदद के लिए धन्यवाद का मैसेज भी भेजा जाता है।

● प्रस्तुति : जालंधर से **मनीष शर्मा**

अक्षय कुमार ने शुरू किया 'दिल से थैंक यू' अभियान

▸ करन जौहर, कट्रीना कैफ समेत कई दिग्गज जुड़े मुहिम से

▸ डॉक्टर, नर्स व निगमकर्मियों को धन्यवाद कर रहे लोग

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई : कोरोना वायरस से सबसे आगे आकर लोहा ले रहे योद्धाओं को धन्यवाद देने के लिए अब अक्षय कुमार ने एक श्रृंखला की शुरुआत की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर हाथों में एक पेपर पकड़े हुए तस्वीर साझा की है, जिस पर लिखा है- हैशटैग दिल से थैंक यू। अक्षय ने इसके जरिये पुलिस, डॉक्टर, नर्स, नगर निगम के कर्मचारी, एनजीओ के कार्यकर्ता व बिल्डिंग के गार्ड्स आदि को धन्यवाद दिया है। इस मुहिम को शुरू करने का आइडिया अक्षय को मुंबई पुलिस में कार्यरत अपने एक दोस्त से बात करके आया।

अक्षय ने अपने वीडियो में कहा, 'मेरे दोस्त ने कहा कि आप लोग अपने घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं और हम अपने घर में जाने से डर रहे हैं। सारा दिन सड़क पर रहते हैं। कहीं बीमारियां अपने परिजनों को न दे दें, इसलिए कई दिनों तक घर नहीं जाते। उनकी इस बात को सुनकर मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि हमें अंदाजा भी नहीं है हम सुरक्षित रहें इसके लिए कितने लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रात-दिन काम कर रहे हैं।'

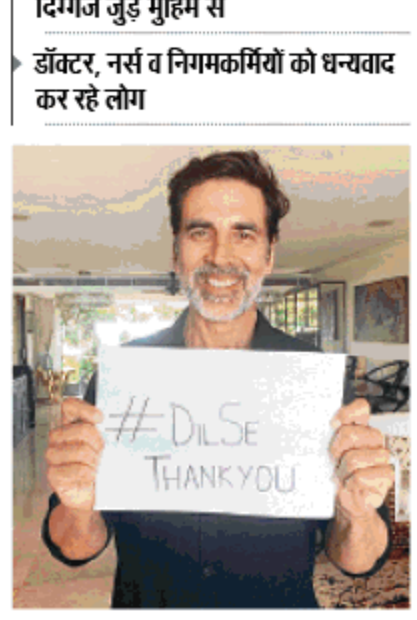

अभिनेता अक्षय कुमार। सौ. ट्विटर

मुंबई पुलिस ने अजय से कहा, हम वही कर रहे जो खाकी को करना चाहिए

मुंबई पुलिस मुस्तैद होने के साथ काफी हाजिरजवाब भी है। दरअसल, अजय देवगन ने बुधवार को मुंबई पुलिस द्वारा साझा किए गए एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए लॉकडाउन में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए उसकी तारीफ की थी। इसके जवाब में मुंबई पुलिस लिखा, 'प्रिय सिंघम, वंस अपॉन एक टाइम इन मुंबई को वापस लाने के लिए हम वही कर रहे हैं जो खाकी को करना चाहिए।' ज्ञात हो कि सिंघम, खाकी और वंस अपॉन ए टाइन इन मुंबई तीनों फिल्मों में अजय देवगन ने काम किया है।

वीडियो साझा करने के साथ अक्षय ने लिखा, 'बाहर एक पूरी आर्मी हमारी सुरक्षा के लिए दिन-रात काम कर रही है। हम कम से कम उन्हें साथ मिलकर धन्यवाद तो कह ही सकते हैं।' इस मुहिम से कई सितारे जुड़ रहे हैं। करण जौहर ने लिखा, 'यह वक्त है उनके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने का है जो बिना किसी फायदे के बिना थके अपने परिवार से दूर हमें सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। हम मुंबई पुलिस के शुक्रगुजार रहेंगे।' करन के अलावा कट्रीना कैफ, मौनी राय समेत कई सितारे भी इस मुहिम से जुड़े हैं।

महेश मांजरेकर ने बनाई वास्तव-2 : फिल्ममेकर महेश मांजरेकर ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, जिसका नाम है- वास्तव 2। इस फिल्म को सलमान खान ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किया है। फिल्म में दिखाया गया है कि महामारी में बाहर जाने का अंजाम क्या होता है। फिल्म का लेखन और निर्देशन करने के साथ मांजरेकर ने इसमें अभिनय भी किया है। उनकी बेटी सईं भी फिल्म में हैं। बेटे सत्या ने इसे शूट किया है।

कोविड-19 से जंग के लिए बड़ी संख्या में वॉलेंटियर्स आ रहे आगे

चुनौती का सामना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना जैसी महामारी के चलते लॉकडाउन से जहां सब कुछ बंद पड़ा है और लोग घरों में कैद है। वहीं दूसरी ओर इन परिस्थितियों में भी आगे आकर सेवाभाव के साथ दूसरों तक मदद पहुंचाने वाले योद्धाओं की भी कोई कमी नहीं है। बड़ी संख्या में लोग स्वेच्छा से इस काम के लिए आगे आ रहे है। एनसीसी, रेडक्रास सोसाइटी, नेहरू युवा केंद्र संगठन और भारत स्काउट गाइड जैसे संगठनों से जुड़कर अब तक दो लाख से ज्यादा वॉलेंटियर्स इसके लिए आगे आए है। इनमें सबसे ज्यादा 1.17 लाख वॉलेंटियर्स नेहरु युवा केंद्र संगठन के हैं। फिलहाल इन सभी को मैदान में उतारने से पहले खास प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इन कामों में दे रहे हैं सहयोग

कोरोना के खिलाफ छिड़ी इस जंग में स्वेच्छा से लोगों की मदद के आगे आए इन वॉलेंटियर्स को खास प्रशिक्षण के बाद जिन क्षेत्रों में लगाया जा रहा है, उनमें हेल्थ, कम्यूनिकेशन, अतिआवश्यक सेवाएं और ऐसी स्थिति में रात-दिन जरूरी सामान तैयार करने वाले उद्योग आदि हैं। इसके अलावा इन्हें लोगों को जागरूक करने, बुजुर्गों की मदद, डेड बॉडी मैनेजमेंट, मरीजों का परिवहन, लोगों को भीड़ से बचने और दूरी रखने के लिए जागरूक करने, हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में घर-घर लोगों तक जरूरी खाने-पीने और दवा को पहुंचाने के साथ पुलिस थानों से जुड़कर लोगों की मदद देने में लगे हैं।

वहीं महामारी बन चुके कोरोना संकट से निपटने में इस संगठनों के अलावा एनएसएस और नागरिक संगठनों के लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। फिलहाल इस वर्कफोर्स का गठन राज्य के साथ-साथ प्रत्येक जिला स्तर पर भी किया जा रहा है। जो जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में काम कर रहा है। हालांकि सरकार ने इन वॉलेंटियर्स को मैदान में उतारने के पहले स्वास्थ्य कर्मियों की तरह विशेष प्रशिक्षण के बाद ही उतारने का फैसला किया है। जिस पर तेजी से काम शुरू भी हो चुका है। रेडक्रास सोसाइटी ने ऐसे समय में मदद देने के लिए आगे आ रहे लोगों को कोरोना योद्धा नाम दिया है।

नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सभी राज्यों में संगठन बड़ी संख्या में वॉलेंटियर्स को तैयार कर रहा है। इनके पहले चरण का प्रशिक्षण भी पूरा हो गया है। इसके तहत मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए थे। अब यह सभी जिला स्तर पर प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। फिलहाल यह सारा प्रशिक्षण लोगों को घर बैठे और ऑनलाइन माध्यमों से दिया जा रहा है।

दैनिक जागरण

निरंतर कोशिश करना सफलता की गारंटी है

आपात सहायता

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रांतों को आपात सहायता के रूप में 15 हजार करोड़ रुपये का पैकेज देने की जो घोषणा की वह वक्त की जरूरत थी। अच्छी बात यह है कि इस पैकेज की पहली किस्त जारी भी कर दी गई ताकि राज्य सरकारें स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के साथ ही आवश्यक चिकित्सा उपकरणों का भी प्रबंध कर सकें। राज्यों को यह काम प्राथमिकता के आधार पर करना होगा, क्योंकि एक तो कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और दूसरे सरकारी स्वास्थ्य ढांचा संसाधनों के अभाव का सामना कर रहा है। चूंकि इस महामारी ने इसकी जरूरत रेखांकित कर दी है कि स्वास्थ्य तंत्र को सुधारने पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाए इसलिए केंद्र के साथ-साथ राज्यों को भी अपनी प्राथमिकताएं नए सिरे से तय करनी होंगी। कमजोर सरकारी स्वास्थ्य तंत्र को लेकर केवल चिंता जताने का समय बीत गया। यह समय इन चिंताओं का समाधान करने का है और वह भी युद्धस्तर पर, क्योंकि यह दिखने लगा है कि कोरोना संकट से आसानी से छुटकारा मिलने वाला नहीं है।

वर्तमान स्थितियों में बेहतर यही है कि जिस तरह सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की सुध ली जा रही है उसी तरह इसकी भी ली जाए कि देश को दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए? यदि ऐसा किया जा सके तो स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में देश को सक्षम बनाने के साथ ही दुनिया की मदद भी की जा सकती है और आर्थिक हितों की रक्षा भी। चूंकि कोरोना के कहर ने जीवन के हर क्षेत्र को गहराई से प्रभावित किया है इसलिए उन सभी समस्याओं पर निगाह रखने के साथ ही उनका समाधान भी करना होगा जो सिर उठा रही हैं या आगे सिर उठा सकती हैं। लॉकडाउन को सफल बनाने, कोरोना मरीजों की तलाश कर उनके उपचार की व्यवस्था करने, आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने की संभावना टटोलने के साथ ही सरकारों को यह भी देखना होगा कि न तो फसल कटाई का काम प्रभावित होने पाए और न ही अन्न की खरीद-ब्रिकी के साथ उसके भंडारण, वितरण का काम। यह सब देखते समय इसकी भी फिक्र करनी होगी कि किसानों-मजदूरों के बीच कोरोना वायरस का संक्रमण न फैलने पाए। यह पर्याप्त नहीं कि कारोबार जगत से लेकर कृषि क्षेत्र तक में जो समस्याएं उभर रही हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। जो भी ऐसा कर रहे हैं उन्हें समस्याओं के समाधान के तौर-तरीकों पर भी प्रकाश डालना चाहिए। यह आपदा का समय है और ऐसे वक्त केवल समस्याओं का उल्लेख करके कर्तव्य की इतिश्री नहीं की जानी चाहिए।

कोर्ट में कोरोना मामला

बंगाल में शायद ही कोई ऐसा आपदा या फिर घटना हो जो कलकत्ता हाईकोर्ट न पहुंचा हो। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर भी कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हो गई है। जिस पर बुधवार सुनवाई भी शुरू हो गई। पहले दिन सुनवाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को राज्य में कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के दो जजों की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 16 अप्रैल तक ई-मेल से रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। उस दिन मामले में आगली सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मरीजों और संदिग्ध मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाएं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को उपयुक्त सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता फुआद हलीम का प्रतिनिधित्व करने वाले भट्टाचार्य ने यह आरोप भी लगाया कि अब तक की गई जांच और वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या के बारे में सभी आंकड़े सरकार द्वारा साझा नहीं किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से हुई मौत और संक्रमित लोगों की सही संख्या नहीं बताई जा रही है। इसीलिए माकपा नेता व पेशे से चिकित्सक फुआद हलीम ने सही जानकारी सामने लाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। परंतु आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अन्य राज्यों में संक्रमितों और कोरोना से हुई मौत की संख्या को लेकर कोई विवाद नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि बंगाल में 71 कोरोना संक्रमित रोगी हैं और पांच की मौत हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी सभी राज्यों के आंकड़ों में पश्चिम बंगाल में कुल कोरोना पॉजेटिव केस की संख्या 99 दर्ज थी और दस लोगों के मरने के आंकड़े दर्ज हैं। ऐसे में क्यों ममता सरकार की ओर से यह बता जा रहा है कि राज्य में 71 केस ही हैं। यह तो ऐसी आपदा है कि जिस पर किसी का कोई जोर नहीं है। यह बीमारी आम लोगों की गलतियों के कारण फैली है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की नाकामी

विवेक काटजू

फिलहाल तो विश्व समुदाय का ध्यान कोरोना संकट से निपटने में होना चाहिए, लेकिन वह इसकी भी अनदेखी न करे कि डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य प्रहरी की भूमिका निभाने में नाकाम रहा

अवधेश राजपूत

कोरोना वायरस से उपजी कोविड-19 महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ की भूमिका भी संदेह के दायरे में आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो उसकी खुली आलोचना कर डाली है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या डब्ल्यूएचओ ने गंभीरता दिखाते हुए पर्याप्त कदम उठाए? क्या उसने चीन से सही सवाल पूछे ताकि इस बीमारी के संभावित खतरे को लेकर कुछ भनक लगती? क्या इस बीमारी को लेकर विश्व को समय से सलाह न दे पाने में नाकाम रहने के लिए उसे जिम्मेदार माना जाना चाहिए? डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में एक अंतर-सरकारी संगठन के रूप में हुई थी। इसका मकसद मानवीय स्वास्थ्य के सभी पहलुओं को सुधारने और बीमारियों की रोकथाम में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। इसे एक निष्पक्ष तकनीकी संगठन के रूप में काम करना चाहिए, लेकिन कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों की तरह यह भी अमीर और ताकतवर देशों के दबावों से प्रभावित होता है। दवा कंपनियों के अलावा मानवीय स्वास्थ्य पर असर डालने वाले अन्य अनेक उद्योगों की लॉबी भी इस पर असर डालती है। डब्ल्यूएचओ का कामकाज एक सचिवालय से चलता है। इसमें तकनीकी और प्रशासनिक सलाहकारों का अमला होता है। ये महानिदेशक के मातहत काम करते हैं। महानिदेशक का चुनाव कार्यकारी बोर्ड की सिफारिश पर सदस्य देशों द्वारा किया जाता है।

किसी भी किस्म की स्वास्थ्य आपदा में डब्ल्यूएचओ से यह अपेक्षा होती है कि वह बिना किसी पक्षपात समय रहते कारगर कदम उठाए। इसमें महानिदेशक की भूमिका बेहद अहम होती है। उसे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसकी निजी पसंद क्या है या उसके मूल देश का इस पर क्या रुख है? मौजूदा महानिदेशक टेड्रोस गेब्रेयसस 2017 में चुने गए थे। इसके पहले वह इथियोपिया के विदेश मंत्री और उससे पहले वहीं के स्वास्थ्य मंत्री थे। उनकी अकादमिक पृष्ठभूमि सार्वजनिक स्वास्थ्य मसलों से जुड़ी है और उन्हें आपदा नियंत्रण का भी अनुभव है। इसे देखते हुए उन्हें तब एकदम सतर्क हो जाना चाहिए था जब 7 जनवरी को चीन ने कोरोना वायरस के फैलने की सूचना दी। इससे एक हफ्ते पहले चीन ने डब्ल्यूएचओ को बताया था कि वुहान शहर में हो रही मौतों की वजह उसे पता नहीं लग पा रही। गेब्रेयसस तब भी सावधान नहीं हुए। क्या वह चीन के प्रभाव में थे जिसने उनके चुने जाने का जबरदस्त समर्थन किया था?

डब्ल्यूएचओ ने 20 जनवरी को कोविड-19 से जुड़ी पहली रिपोर्ट जारी की तब तक कोरोना थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया में दस्तक दे चुका था। डब्ल्यूएचओ ने दावा किया कि उसने बदलते घटनाक्रम को देखते हुए खुद को सक्रिय कर दिया था, पर ऐसा लगा नहीं कि वह जरूरी तत्परता दिखा रहा था। 23 जनवरी को चीन ने अपने हूबे प्रांत को लॉकडाउन कर दिया। वुहान इसी प्रांत की राजधानी है। चीन को जब संक्रमण को रोकने का कोई और उपाय नहीं सूझा तब उसने यह कदम उठाया। इससे डब्ल्यूएचओ और एक तरह से दुनिया भर में खतरे की घंटी बज जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं हुआ। हालांकि कुछ देशों ने चीन से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग जरूर शुरू कर दी। हालात का मुआयना करने के लिए टेड्रोस 27 जनवरी को चीन पहुंचे। इस दौरान वह राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीनी स्वास्थ्य विशेषज्ञों से मिले। फिर उन्होंने शी की तारीफों के पुल बांधे और चीन के सख्त कदमों की सराहना करते हुए कहा कि यदि ऐसा न किया जाता तो यह वायरस और खतरनाक तरीके से दुनिया भर में फैलता। तब तक कोरोना 15 देशों में फैल चुका था। फिर भी टेड्रोस ने कहा कि कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर चीन दुनिया के आभार और सम्मान का पात्र है।

इस पड़ाव पर चीन का सहयोग बेहद जरूरी था, क्योंकि एक तो वायरस वहीं जन्मा और दूसरे, केवल उसे ही इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टेड्रोस का रुख भी किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के मुखिया जैसा नहीं था। उनका रवैया तब और संदिग्ध हो गया जब उन्होंने डब्ल्यूएचओ-चीन की संयुक्त टीम पर सहमति जताई, जबकि डब्ल्यूएचओ की टीम को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए था। आखिरकार 30 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 को अंतरराष्ट्रीय चिंता वाली स्वास्थ्य आपदा करार दिया। यह एलान पहले ही हो जाना चाहिए था। लापरवाही का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। 4 से 8 फरवरी के बीच डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड की बैठक हुई। वहां 52 सूत्रीय एजेंडे में कोविड-19 को शामिल तक नहीं किया गया। टेड्रोस ने केवल दो संक्षिप्त ब्रीफिंग की। 7 फरवरी को दूसरी ब्रीफिंग के समय तक कोरोना 24 देशों में फैल चुका था। इसके लिए कार्यकारी बोर्ड के सभी सदस्यों सहित उसके जापानी प्रमुख भी गैर-जिम्मेदार माने जाएंगे जो इस खतरे को भांपकर डब्ल्यूएचओ को सक्रिय नहीं कर पाए। डब्ल्यूएचओ-चीन के विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने 14 से 29 फरवरी के बीच कोविड-19 के मेडिकल एवं तकनीकी पहलुओं का विश्लेषण किया। इसकी रोकथाम के सुझावों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इन विशेषज्ञों ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को यह सलाह दी कि वे चीन के साथ अपना संपर्क पुनः जोड़ें, ताकि वहां आर्थिक गतिविधियां फिर से जोर पकड़ सकें। उन्होंने चीन के कदमों का पुरजोर समर्थन किया। चूंकि इसमें शामिल चीनी सदस्य अपनी ही सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे इसलिए इस रिपोर्ट को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता था।

कोविड-19 का प्रकोप बढ़ाता रहा, फिर भी डब्ल्यूएचओ उसे वैश्विक महामारी घोषित करने से कतराता रहा। उसने 11 मार्च को यह एलान किया। कुल मिलाकर इस मामले में डब्ल्यूएचओ का रुख उसके उद्देश्यों के उलट रहा। उससे यही अपेक्षा है कि वह किसी जोखिम का स्वतंत्र रूप से आकलन करे, न कि किसी देश का पिछलग्गू बनकर। यहां वह चीन के पिट्ठू के रूप में काम करता दिखा। फिलहाल तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय का पूरा ध्यान कोरोना संकट से निपटने में सहयोग और एकजुटता पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन वह इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि जिस डब्ल्यूएचओ को प्रहरी की भूमिका निभानी थी वह उसमें नाकाम रहा।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

दुनिया को रास्ता दिखाए भारत

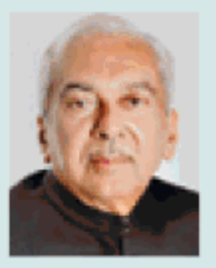

जगमोहन सिंह राजपूत

भारत मानव-प्रकृति संबंधों का ऐसा उदाहरण पेश कर सकता है, जिसकी आवश्यकता आज सारे विश्व को है

आज मानव के समक्ष एक ऐसा संकट उपस्थित हुआ है, जिसकी वैज्ञानिकों को न तो कोई आशंका थी, न ही उससे निपटाने की कोई तैयारी। यह संकट है कोरोना वायरस के संक्रमण से तेजी से फैल रही कोविड-19 नामक महामारी का। आज तो केवल यही कहा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर किए जा रहे मानवीय प्रयास शीघ्र ही सफल होंगे और कोविड-19 का उन्मूलन उसी तरह संभव होगा जैसे प्लेग, टीबी, चेचक इत्यादि का हुआ। कोरोना वायरस ने मनुष्य के सामने उसके भविष्य को लेकर कई प्रश्न उपस्थित कर दिए हैं जिन पर मानव समाज को गहनता से विचार-विमर्श करना होगा। आज मनुष्य के इस अहंकार को गहरा धक्का लगा है कि उसने प्रकृति के रहस्यों को समझने और उस पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। कोरोना ने मनुष्य के ज्ञान और समझ की अपूर्णता और सीमाओं को सामने ला दिया है।

ज्ञान, बुद्धि और विवेक मनुष्य को पीढ़ियों की असीमित और सतत साधना के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इनकी ऐसी कोई सीमा नहीं जहां पर पहुंचकर कहा जा सके कि वही सीमांत है। जब तक मानव सभ्यता पृथ्वी पर विद्यमान है, उसका विकास जारी रहेगा, उसके लिए मानव के प्रकृति के रहस्यों को समझने के प्रयास भी जारी रहेंगे। हालांकि प्राचीन काल में भारत के ऋषियों और साधकों ने इन प्रयासों को नियमबद्ध किया था। उन्होंने इस पर जोर दिया था कि हर नए ज्ञान और कौशल का उपयोग केवल जनहित में हो। प्रकृति के प्रति सम्मान और आदरभाव रखते हुए ही मनुष्य उसके संसाधनों का उपयोग करे। इसी दर्शन को महात्मा गांधी ने कुछ इस तरह कहा था कि भारत अपने मूलरूप में कर्मभूमि है, भोगभूमि नहीं। उनका यह भी कहना था कि भारत में आत्मशुद्धि के लिए स्वेच्छापूर्वक जैसा प्रयत्न किया गया, उसका दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। इसी चिंतन के कारण पूरे विश्व ने ज्ञान और आध्यात्म के क्षेत्र में भारत की श्रेष्ठता को स्वीकार किया।

भारत में अपरिग्रह को मनुष्य और प्रकृति के बीच की संवेदनशील कड़ी बनाए रखने का आधार बनाया गया था। गांधी जी ने अपरिग्रह को समझा, सराहा, अपनाया और दूसरों को समझाने का प्रयास भी किया। अनेक कारणों से कालांतर में भारत में इस आत्मशुद्धि की स्वीकार्यता और व्यावहारिकता में कमी आती गई। अपनी संस्कृति को पीछे छोड़कर भारत पश्चिम की भोगवादी संस्कृति की नकल करने में संलग्न हो गया और प्रकृति का सम्मान करना भूल गया। कोरोना संकट ने भारत के सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि विश्व को अपरिग्रह का अर्थ और मंतव्य समझाना मुख्यतः उसका भौतिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक उत्तरदायित्व है। हर प्रकार की विविधता को स्वीकार करने का उदाहरण विश्व के सामने प्रस्तुत करनेवाला और प्रकृति के लगभग हर अंग में दैवत्व देखने वाला भारत उसके वैश्विक संरक्षण में आगे रहने का दायित्व कैसे भूल सकता है? यह वैश्विक समझ और चिंता लगातार बढ़ रही है कि अनियंत्रित भौतिकवाद और चिंताजनक ढंग से मानव-मूल्यों का क्षरण और आध्यात्मिकता के प्रति बढ़ता विरक्ति-भाव मानव-मात्र को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। भारत का जनमानस परसेवा को सबसे बड़ा पुण्य मनाता है। वह 'यह मेरा-वह तेरा' से ऊंचे उठकर वसुधैव कुटुंबकम को हजारों साल पहले समझ चुका है। यदि उसकी नई पीढ़ी को प्रारंभ से ही मानव मूल्यों, प्राचीन भारतीय संस्कृति और साहित्य की श्रेष्ठता से परिचित करा दिया जाए, उसकी गतिशीलता और हर प्रकार के जन-उपयोगी नए ज्ञान और परिवर्तन को आवश्यक विश्लेषण के पश्चात स्वीकार करने की छूट से अवगत करा दिया जाए तो भारत फिर एकबार मानव-मानव और मानव-प्रकृति के संबंधों का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी आज सारे विश्व को आवश्यकता है। ऐसे में भारत को अपनी जिम्मेदारी उठनी चाहिए और कोरोना से उबरे विश्व को नया रास्ता दिखाना चाहिए।

कोरोना के बाद विश्व व्यवस्था में भी बहुत कुछ बदलाव होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हिंसा और युद्ध की विभीषिका से मनुष्य को निजात दिलाने की आवश्यकता तेजी से उभरी थी। महात्मा गांधी पहले दक्षिण अफ्रीका और फिर भारत में अहिंसा के महत्व और उसकी व्यावहारिकता को स्थापित कर विश्व का ध्यान आकर्षित कर चुके थे। संघर्ष और युद्ध से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र, उसकी सुरक्षा परिषद, यूनेस्को जैसी अनेक संस्थाएं बनीं। इनकी उपलब्धियों की लंबी सूची है, मगर शांति और सौहार्द के लिए इन संस्थाओं का प्रभाव सीमित ही रह पाया। इनकी संरचना भी बदलते समय के अनुकूल नहीं बदल सकी है। इन संस्थाओं में आज भी उपनिवेशवाद की उपस्थिति महसूस की जाती रही है। वहीं दुनिया में हथियारों की होड़ भी लगातार जारी है।

उम्मीद है कि सभी देश कोरोना को पराजित करने के क्रम में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, मानव-प्रकृति के संबंधों में सुधार और समय के अनुरूप संगठन स्थापित करने में अधिक खुले दिल से एक-दूसरे को समझने के लिए तैयार होंगे। अब सबसे बड़ी चुनौती इसके लिए आगे की रणनीति बनाने की होगी। इसका एक खाका महात्मा गांधी ने 6 मई, 1926 को यंग इंडिया में लिखे एक लेख में खींचा था। उन्होंने कहा था कि यदि हमें प्रगति करनी है, हमें अपने पुरखों की धरोहर को बढ़ाना है तो हम नए आविष्कार और खोज अवश्य करें, मगर आध्यात्मिक पक्ष को कदापि न भूलें। आज के संदर्भ में कहा जा सकता है कि वैश्विक सहयोग की नई प्रभावी संरचना बनाई जाए जो मानव के मस्तिष्क में मानवता के बीज बोये, अविश्वास का निर्मूलन करे और नया इतिहास रचे।

(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

धर्म युद्ध

धर्म युद्ध से तात्पर्य है जो युद्ध मानवता की रक्षा के लिए लड़ा जाए। जैसे कि द्वापर युग में श्रीकृष्ण ने कौरवों द्वारा किए जा रहे अन्याय तथा अनैतिकता को मिटाने के लिए महाभारत रूपी धर्म युद्ध के लिए पांडवों को प्रेरित किया था। इसी प्रकार त्रेता युग में राक्षसों को मिटाकर पूरी मानव जाति को भय मुक्त करने के लिए ईश्वर ने श्रीराम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर मानवता की रक्षा की। आज उसी प्रकार कोरोना रूपी दानव ने मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। इसलिए आज पूरे विश्व में इसके विरुद्ध एकजुट होकर युद्ध लड़ा जा रहा है। श्रीकृष्ण ने गीता में कर्म योग की व्याख्या करते हुए कहा है कि शरीर रूपी मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य को नियत कर्म करने चाहिए, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का स्वरूप है और मनुष्य के अंदर वही ईश्वर विराजमान है। ऐसे में कोरोना के विरुद्ध युद्ध भी धर्म युद्ध कहा जा सकता है।

इस युद्ध में अस्त्र-शस्त्र के स्थान पर लॉकडाउन और सावधानियां जैसे उपायों से हम कोरोना को परास्त करेंगे। समस्त मानव जाति को नियत कर्म के रूप में वह सब सावधानियां बरतनी चाहिए जिनसे इस कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। लोगों को सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। अध्यात्म की गलत व्याख्या करने वालों की तरह इन सावधानियों को अपने ऊपर प्रतिबंध मानते हुए इनको मानने में कोताही नहीं करनी चाहिए। इस समय इस धर्म युद्ध में सहयोग न देना एक प्रकार से मानवता के विरुद्ध बहुत बड़ा पाप होगा।

इसलिए इस धर्म युद्ध रूपी लड़ी जाने वाली लड़ाई को जीतने में हमें शासन व्यवस्था को पूरा सहयोग देना चाहिए। इस युद्ध में जो मानव अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं उनकी हर प्रकार से उसी प्रकार सहायता करनी चाहिए जैसे धर्म युद्ध के पक्ष में लड़ने वालों की की जाती है। यह सहायता एक प्रकार की ईश्वर भक्ति ही होगी।

कर्नल शिवदान सिंह

चिंतित करती आइएलओ की रिपोर्ट

चंदन कुमार चौधरी

> अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार इस साल दुनिया भर में 19 .5 करोड़ लोगों की पूर्णकालिक नौकरी छूट सकती है

कोरोना संकट के बीच अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) ने हाल ही में चेतावनी दी है कि भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं। इतना ही नहीं अपनी रिपोर्ट में आइएलओ ने कोरोना संकट को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयानक संकट बताया है। इस साल दुनिया भर में 19.5 करोड़ लोगों की पूर्णकालिक नौकरी छूट सकती है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रयासरत है उस समय में रोजगार और गरीबी से जुड़ी आइएलओ की रिपोर्ट निश्चित रूप से चिंता और परेशानी बढ़ाने वाली है। रिपोर्ट में भारत के 40 करोड़ लोगों के गरीबी में फंसने की बात कही जा रही है जो एक बड़ी संख्या है और इससे बचने के लिए गंभीर प्रयास करने ही होंगे। दरअसल दुनिया के सभी देश अभी इस वायरस से लड़ने में लगे हैं और इसे नियंत्रित करने का अभी तक कोई कारगर उपाय सामने नहीं आया है। दुनिया को अभी यह भी नहीं मालूम है कि यह बीमारी कितने दिनों तक रहेगी और इसके क्या-क्या दुष्परिणाम सामने आएंगे। इस समस्या का सही और वास्तविक आकलन तभी संभव है जब कोरोना वायरस महामारी पर दुनिया जीत हासिल कर ले। अभी ऐसा लगता है कि आइएलओ की यह रिपोर्ट शुरुआती आकलन और तात्कालिक अध्ययन पर ही आधारित है। ऐसे में शायद आने वाले दिनों में यह संकट बड़ा भी हो सकता है।

दरअसल कोरोना वायरस के कारण विकसित और विकासशील, दोनों अर्थव्यवस्थाओं में श्रमिकों और व्यवसायों को तबाही का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर में दो अरब लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं और भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वालों की हिस्सेदारी लगभग 90 प्रतिशत है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत में लागू किए गए देशव्यापी बंद के कारण श्रमिक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और उन्हें अपने गांवों की ओर लौटने को मजबूर होना पड़ा है।

हालांकि विभिन्न सरकारों ने इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं और वे लगातार प्रयास भी कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में कल्याणकारी और जन सरोकारों से जुड़े कई फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के लिए राहत पैकेज की घोषणाएं की है और अपने खर्च में कटौती करने का निर्णय भी लिया है। इसका असर भी होता दिख रहा है। सरकार की पहली प्राथमिकता अभी किसी भी कीमत पर कोरोना वायरस को नियंत्रित करना है। ऐसे में शायद वह अर्थव्यवस्था से जुड़ी समस्या की ओर उतना ध्यान नहीं दे पा रही हो जितना उसे देना चाहिए। यह ठीक भी है, क्योंकि पहली प्राथमिकता जान बचाना ही होनी चाहिए। लोग रहेंगे तो अर्थव्यवस्था को बाद में भी खड़ा कर लेंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

कौमी नेतृत्व की आवश्यकता नहीं

निराश करता मुस्लिम नेतृत्व शीर्षक से लिखे अपने लेख में डॉ. एके वर्मा ने सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए उदार मुस्लिम नेतृत्व के आगे आने की अपेक्षा की है, जो इस वक्त नदारद है। हिंदू-मुस्लिम सद्भाव की लेखक की सदिच्छा का आदर करते हुए भी कहना चाहता हूं कि जब भी आप किसी कौम विशेष (हिंदू, मुस्लिम या कोई अन्य) के नेतृत्व की बात करते हैं, चाहे वह आपकी कल्पनाओं में कितना ही उदार क्यों न हो, आप, दरअसल गलत नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक राष्ट्र संविधान और जनमत द्वारा चुनी हुई सरकार से संचालित होता है। लोगों के अधिकार और कर्तव्य की सीमाएं भी उसी के द्वारा निर्धारित होती हैं। अतः समाज को सही दिशा देने और उसके नागरिकों के मन में देश और उसके कानून के प्रति समुचित सम्मान की भावना को जगाने के लिए किसी कौमी जमात अथवा नेतृत्व की आवश्यकता नहीं। यह काम सरकार और उसकी संस्थाएं ही करेंगी। रही बात उदार अथवा अनुदार नेतृत्व की तो कोई भी सांप्रदायिक अथवा जातीय नेतृत्व उदार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके प्रभाव और शक्ति का स्रोत ही कौमी अथवा जातीय एकता, अस्मिता और उसकी विशिष्टता की रक्षा है। इसलिए उसमें कट्टरता आ ही जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना का ही उदाहरण लें, कभी उदार माने जाने वाले जिन्ना ने भी मुस्लिम लीग में अपने नेतृत्व को मजबूत करने के लिए कट्टरता का ही सहारा लिया, जिसकी परिणति भयानक दंगों और देश विभाजन के रूप में सामने आई। अतः मेरे विचार से मुस्लिम नेतृत्व की किसी उदारवादी धारा के फूटने का इंतजार न कर सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर विश्वास बढ़ाने वाले कार्यक्रम चलाने चाहिए। यदि इस कार्य में कोई धार्मिक अथवा सामाजिक संस्था आगे बढ़कर मदद करना चाहे तो उसका भी सहयोग लिया जा सकता है।

चंदन कर्ण, देवघर

ट्रकों का हो संचालन

देश में सामानों की ढुलाई के लिए सामान्यतः 10 लाख ट्रक लगे रहते हैं। पूर्ण नाकेबंदी से उनमें से केवल 10 से 15 प्रतिशत ट्रक ही आज माल की ढुलाई कर पा रहे हैं। सरकारी स्तर पर ट्रक चालकों व उनके खलासियों को ई-पास जारी किया जा रहा है, लेकिन इसकी गति बहुत धीमी है। अनेक ट्रक चालक व खलासी ट्रकों को छोड़कर अपने घरों को चले गए हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में सब कुछ जारी तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन लंबे समय तक सब कुछ ठप भी रखना कठिन होगा। क्योंकि माल की सप्लाई व आपूर्ति अगर रुकी रही तो आगे चलकर दूसरी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। सरकार को लॉकडाउन में ढिलाई देते समय इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

हर कोई ले प्रण

इस महामारी ने बहुत कुछ सिखा दिया। लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने पर हमें अपने आप से कई प्रण करने होंगे। दिखावे की संस्कृति को अलविदा कहना होगा। शोशेबाजी से बचना होगा। उत्सवों, समारोहों का आयोजन करने में तड़क-भड़क से दूर रहना होगा। देसी पहनना, देसी खाना होगा। देश में बनी वस्तुओं का उपभोग करना होगा जिससे देश का धन देश में रहे। रोजगार के अवसर यहीं पैदा करने होंगे। विदेशों में रह रहे भारतीय लोग भारत में अधिक से अधिक निवेश करें ताकि लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा मिले।

अंजु दुआ जैमिनी, फरीदाबाद

अधिक हों टेस्ट

देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि और बढ़ाने संबंधी चर्चा तेज हो गई है। इसका कारण दिन प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या का बढ़ना है। हालांकि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या कम है, परंतु इसकी एक वजह कम टेस्ट होना भी हो सकता है। लॉकडाउन को लेकर सरकार जो भी निर्णय ले, लेकिन सरकार को अधिक से अधिक टेस्ट की प्रक्रिया अविलंब शुरू करनी चाहिए।

मो. फैयाज आलम, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721

33 साल बाद दूरदर्शन पर एक बार फिर से प्रसारित रामायण धारावाहिक ने टीआरपी के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रसार भारती के अनुसार रामायण की टीआरपी के सामने अभी कोई शो नहीं है।

आजकल

प्रदीप
विज्ञान विषय के जानकार

कोरोना के खिलाफ तकनीक बना कारगर हथियार

विशेषज्ञों का मानना है कि हम बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, थ्रीडी प्रिंटिंग और थर्मल इमेजिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बेहद प्रभावी ढंग से कोरोना वायरस से मुकाबला कर सकते हैं

कोरोना की महामारी से निपटने के लिए आज यह बेहद जरूरी है कि सरकार लोगों की निगरानी रखे। तकनीक की बदौलत सभी लोगों पर एक साथ हर समय निगरानी रखना आज मुमकिन है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कई सरकारों ने तकनीक को मोर्चे पर लगा दिया है। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चीन ने इस वायरस पर काफी हद तक काबू पाया है। लोगों के स्मार्टफोन, चेहरा पहचानने वाले कैमरों और शरीर का तापमान रिकॉर्ड करने और अपनी मेडिकल जांच की अनुमति देने की इच्छा रखने वाली जनता के बल पर चीनी अधिकारियों ने न केवल शीघ्रता से यह पता कर लिया कि कौन व्यक्ति कोरोना वायरस का संभावित वाहक है, बल्कि वह उन पर नजर भी रख रहे थे कि वे किस-किस के संपर्क में आते हैं। कई सारे ऐसे मोबाइल एप्स हैं जो नागरिकों को संक्रमित व्यक्ति के आसपास मौजूद होने के बारे में चेतावनी देते हैं।

कोरोना वायरस को रोकने के लिए चीन ने सबसे पहले कलर कोडिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। इसके लिए चीन की दिग्गज टेक कंपनी अलीबाबा और टेनसेंट ने साझेदारी की है। यह सिस्टम स्मार्टफोन एप के रूप में काम करता है। इसमें यूजर्स को उनकी यात्रा के दौरान उनकी मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक ग्रीन, येलो और रेड कलर का क्यूआर कोड दिया जाता है। ये कोड ही यह निर्धारित करते हैं कि यूजर को क्वारंटाइन करना चाहिए या फिर उसे सार्वजनिक स्थान पर जाने की इजाजत दी जानी चाहिए। चीनी सरकार ने इस सिस्टम के लिए कई चेक प्वाइंट्स बनाए हैं जहां लोगों की चेकिंग होती है। यहां उन्हें उनकी यात्रा और मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक क्यूआर कोड दिया जाता है। अगर किसी को ग्रीन कलर का कोड मिलता है तो वह इसका उपयोग कर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है। अगर किसी को लाल रंग का कोड मिलता है तो उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इस सिस्टम का इस्तेमाल 400 से ज्यादा चीनी शहरों में हुआ है। भारत में भी एप आधारित कलर कोडिंग टेक्नोलॉजी को विकसित करने के प्रयास जोर-शोर से किए जा रहे हैं।

हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के जोखिम का आकलन करने वाला आरोग्य सेतु एप लांच किया है। सरकार का कहना है कि यह एक ही समय में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवाएं देने और युवा भारत की क्षमता और देश के रोग मुक्त और स्वस्थ भविष्य के बीच एक संपर्क है। भारत में भी तमाम जगहों पर दूर से तापमान रिकॉर्ड करने के लिए स्मार्ट थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे संभावित कोरोना वायरस वाहक की पहचान करने में आसानी हो रही है। भारत में बाजार पर केंद्रित हेल्थ टेक स्टार्टअप भी रोग के निदान के लिए नवाचार की ओर कमर कस रहे हैं जिससे हेल्थकेयर सिस्टम पर दबाव कम हो रहा है। कन्वर्जेंस कैटलिस्ट के संस्थापक जयंत कोल्ला बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप वनब्रेथ का उदाहरण देते हैं जिसने सस्ते और टिकाऊ वेंटिलेटर विकसित किए हैं। यह भारत की ग्रामीण आबादी को ध्यान में रखकर किया गया है जहां अस्पतालों और डॉक्टरों तक पर्याप्त पहुंच का अभाव है। बेंगलुरु आधारित एक अन्य स्टार्टअप डेटुडे ने घर पर क्वारंटाइन रोगियों को विभिन्न सुविधाओं और अस्पतालों में रखने के लिए एक केयर मैनेजमेंट सोल्यूशन विकसित किया है और इसके जरिये बाद में निदान गतिविधियों को भी पूरा किया जाता है।

चीन सहित विभिन्न देशों ने कोरोना वायरस को मात देने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया है। ये रोबोट साफ-सफाई करने के अलावा सैनिटाइजर का छिड़काव भी करते हैं। चीन की कई टेक कंपनियां भी इन रोबोट का उपयोग मेडिकल सैंपल भेजने के लिए करती थीं। कोरोना वायरस को रोकने के लिए चीन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ड्रोन के जरिये चीनी सरकार ने लोगों तक फेस मास्क और दवायां भी पहुंचाई हैं। इनके जरिये कोरोना वायरस से संक्रमित क्षेत्रों में सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया गया है। अगर भारत भी ड्रोन का इस्तेमाल इन कामों के लिए करता है तो कोरोना के प्रसार को रोका जा सकेगा। कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल बेहद कारगर साबित हो रहा है। इस सिस्टम में इंफ्रारेड डिटेक्शन तकनीक मौजूद है जो लोगों के शरीर का तापमान जांचने में मदद करती है। इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यह भी बताता है कि किसने मास्क पहना है और किसने नहीं।

इस चुनौतीपूर्ण समय में वर्क फ्रॉम होम का चलन काफी बढ़ गया है। आज आपको अपने ऑफिस के सर्वर तक पहुंचने, अपने प्रोजेक्ट पर काम करने और वांछित परिणाम देने के लिए केवल एक लैपटॉप और एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। रिमोट एक्सेस, डेस्कटॉप शेयरिंग, ऑनलाइन मीटिंग, वेब कांफ्रेंसिंग और कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफर के लिए टीमव्यूअर और एनिडेस्क जैसी ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। घर से काम करना ही भविष्य में अंतर्निहित है, क्योंकि यह महंगा कार्यालय स्थान बचाने, परिवहन व्यय कम करने और कर्मचारी की उत्पादकता बढ़ाने में कारगर साबित हो सकता है।

शारीरिक संपर्क से बचने के लिए, कार्यालयों में पेपरलेस वर्किंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज ऑनलाइन मीटिंग के लिए ज्यादातर जूम और स्काइप जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौजूदा लॉकडाउन के समय में अधिकांश स्कूल अपने छात्रों को इसी माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन मुहैया करा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मुद्रा के भौतिक विनिमय की जगह डिजिटल लेनदेन की वकालत की है। ऐसे में यह अधिक कारगर साबित होता दिख रहा है। वैज्ञानिक कोरोना के वैक्सीन और दवा को विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे चंद दिनों में 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे रसायनों की जांच हो सकती है जो वायरस को खत्म कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि आज टेक्नोलॉजी ने किसी महामारी से लड़ने के लिए हमारी सीमाओं को काफी हद तक बढ़ा दिया है जिसकी बदौलत हम परंपरागत रक्षात्मक उपायों को अपनाते हुए महामारी के विरुद्ध कारगर ढंग से लड़ सकने में सक्षम हुए हैं। टेक्नोलॉजी न केवल वर्तमान स्वास्थ्य महामारी से लड़ने में मदद कर रही है, बल्कि भविष्य में ऐसे स्वास्थ्य आपदाओं की पुनरावृत्ति से निपटने का तरीका भी बदल देंगी।

असमानता खत्म करने का अवसर

प्रवीण श्रीवास्तव, डॉ. संदीप पाण्डेय एवं बॉबी रमाकांत

कोरोना वायरस ने दुनिया के तमाम विकसित और अमीर देशों तक की स्वास्थ्य प्रणाली की कठोरतम परीक्षा ले ली है। अमेरिका, फ्रांस, इटली, स्पेन और इंग्लैंड जैसे देशों में एक-एक दिन में हजार के आस-पास लोगों की मौत होने के कारण स्वास्थ्य प्रणाली पर चरमरा देने वाला भार पड़ा है। साथ ही कोरोना वायरस ने शहरी, विकसित व अति-आधुनिक समाज को भी ठहर जाने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि इससे संक्रमण व रोग का खतरा सबको है। हवाई जहाज, रेल और बस समेत सारे यातायात के साधन ठप हैं, तो खाने-पीने की वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर मॉल और बाजार सब बंद हैं।

आज इस मुश्किल दौर में अनेक राज्यों की सरकारें कई निजी अस्पतालों का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही हैं। इस देश में समाजवादी सोच रखने वाले लोगों की हमेशा से मांग रही है कि शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र का निजीकरण नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने तो अपने दो अलग अलग फैसलों में यहां तक कहा है कि सरकारी वेतन पाने वाले ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठने वाले को भी अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ाना चाहिए। साथ ही स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों का इलाज सरकारी अस्पताल में उसी चिकित्सक से कराना चाहिए जो उस समय ड्यूटी पर हो। ऐसा इसलिए कहा गया ताकि जब सरकारी अस्पताल और विद्यालय ठीक तरीके से काम करेंगे तो बहुसंख्यक गरीब आबादी को भी उसका लाभ मिलेगा।

कोरोना वायरस का खतरा जब सर पर आकर खड़ा हो गया है तब आज लोग यह महसूस कर रहे हैं कि हमारी सरकारी स्वास्थ्य सेवा की स्थिति चिंताजनक है और कोरोना से निपटने में तो बिल्कुल अक्षम है। इसलिए आज तमाम अन्य जगहों को अस्थाई अस्पतालों में तब्दील किया जा रहा है। काश हमने जन स्वास्थ्य प्रणाली पर शुरू से ही ध्यान दिया होता। अब भी समय है कि हम चेत जाएं और चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में संचालित नीतियों की एक बार फिर से समीक्षा करें। इस बात में कोई शक नहीं कि इस समय कोरोना वायरस पर अंकुश लगाना जरूरी है और यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है, परंतु यह भी समझने की जरूरत है कि बिना हर किस्म की और हर स्तर पर गैर-बराबरी मिटाए ऐसी आपदा से निपटना आसान नहीं होगा।

यह गैर-बराबरी अनेक पीढ़ियों की देन है। यह हमारे लिए एक अवसर है कि हम उक्त गैर-बराबरी को समझदारीपूर्वक, सबकी सहमति और प्रयासों से खत्म करें। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और कोई भी इंसान सड़क पर न सोए। हमें यह समझना होगा कि जिस देश में आधे बच्चे कुपोषित हों, देश की लाखों आबादी को एक समय का भोजन नहीं उपलब्ध हो पाता हो, जिनका आशियाना सड़क पर ही हो तो ऐसे लोगों की चिंता करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। हालांकि कोरोना जनित कारणों से पैदा हुए लॉकडाउन के दौर में सरकारों ने जिस तरह से समाज के हाशिये पर बैठे लोगों को राहत मुहैया कराया है, वह प्रशंसनीय है, लेकिन अभी भी उनके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है।

(लेखक सोशलिस्ट पार्टी, इंडिया से जुड़े हैं)

खरी-खरी

लिखने-छपने का रोग

ब्रजेश कानूनगो

कहने को साधुरामजी हमारे लंगोटिया यार हैं। लेकिन अपनी हरकतों से हमारी लंगोट खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उस दिन हमारी एक व्यंग्य रचना अखबार में छपी थी। बहुत से बधाई फोन आ रहे थे। लेकिन इन सबके उलट मित्र साधुरामजी स्वयं अखबार पकड़े साक्षात पधार गए। आते ही बोले, आज चड्डी-बनियान गिरोह पर आपने जो लेख लिखा है उसमें चोरों के प्रति आप का रवैया सहानुभूतिपूर्ण लग रहा है। ऐसा लगता है कि आप अपराधी के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं।

हमने अपनी सफाई दी और उन्हें समझाया, वह व्यंग्य लेख है मित्र! यह उन फटेहाल चोरों के बारे में नहीं है जो रात में छोटी-मोटी चोरियां करते हैं, बल्कि इसमें टीम वर्क के साथ दिन के उजाले में देश को लूटने वाले सफेदपोश बड़े अपराधियों पर व्यंजना और लक्षणा में शब्द शक्ति से प्रहार की कोशिश की गई है। वे फिर बोले, किंतु ऐसा स्पष्टतः समझ में आता नहीं लेख पढ़कर। हमने समझाया, वह तो समझना पड़ता है मित्र। साहित्य में बहुत से अव्यक्त को पढ़ना आना चाहिए। यह भी एक विधा है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। साधुरामजी अपनी बात पर अड़े रहे। वे बोले, फिर भी आपको स्पष्ट लिखना चाहिए कि आप सफेदपोश लुटेरों पर प्रहार कर रहे हैं। हमने तनिक ज्ञान बांटने के अंदाज में उन्हें समझाया, साहित्यिक विधा में ऐसा नहीं होता मित्र, पत्थर फेंकने और लाठी चलाने से अलग होता है रचनात्मक प्रहार। वरना अभिधा में लिखी रचना तो एक रिपोर्टिंग में बदल जाती है। ये सब व्यंग्य के खास औजार होते हैं। किंतु वे मानने को तैयार नहीं थे। बोले, नहीं यह तो ठीक नहीं है। ये आपकी अभिधा-उभिधा टाइप की शक्तियां तो बहुत अराजक लगती हैं अपने आचरण से। इन्हें हटाइए साहित्य से। अन्यथा हमें कोई कानून लाना पड़ेगा।

बता दें कि साधुरामजी का सार्वजनिक जीवन मोहल्ले की राजनीति से शुरू हुआ था और मोहल्ले की पार्षदी पर जाकर बहुत दिनों तक अटका रहा। जब पार्षदी में वे कुछ खास न कर पाएए तो साधुरामजी को भी लिखने-छपने का रोग लग गया। जब भी कीड़ा उन्हें काटता, वे कुछ नया लिख डालते और हमारे पास बताने चले आते। अब वे ही हमें ज्ञान दे रहे हैं।

ट्वीट-ट्वीट

देशव्यापी लॉकडाउन ने यह सबक दिया है कि ऑनलाइन स्टोर भले ही बहुत सहूलियत वाले हों, पर आड़े वक्त में आस-पड़ोस वाले किराना स्टोर ही आपके काम आते हैं। जब यह सब गुजर जाएगा तब भी उनका सहयोग जारी रखना मत भूलिएगा।
भावना अरोड़ा@BhavnaArora

कश्मीर में जमीनी हकीकत को लेकर कभी किसी को हैरत नहीं होती। कोविड-19 महामारी के दौर में भी लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखकर जैश आतंकी के जनाजे में शामिल हो रहे हैं।
हरिंदर बावेजा@shammybaweja

आखिर ये तब्लीगी तहजीब से पेश क्यों नहीं आ रहे? क्या इन लोगों को नहीं पता कि ये पहले ही काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। अगर आप ईश्वर के संदेश का प्रसार करते हो तो आपको समाज के जिम्मेदार सदस्य की भूमिका भी निभानी चाहिए। लगता है कि उन्होंने जो करतूत की वही उन्हें काफी नहीं लगती।
मनीष तिवारी@ManishTewari

यह लॉकडाउन का तीसरा हफ्ता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने यहां टेस्ट की रफ्तार बढ़ाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता। यहां टेस्ट की रफ्तार पाकिस्तान से भी सुस्त है। इस तरह तो लॉकडाउन का उद्देश्य ही अधूरा रह जाएगा
सीताराम येचुरी@SitaramYechuri

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या सांसद निधि को दो साल के लिए स्थगित करने के सरकार के फैसले पर विपक्ष की आपत्ति उचित है?

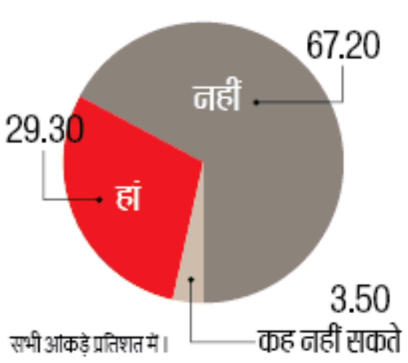

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की तैयारियां सही दिशा में हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

सिब्बल-ममता साथ में दादा शरद पवार,
संकट में भी कर रहे राजनीति के वार।
राजनीति के वार जरा अब करिए भी बस,
अगर बचेगा देश करेंगे पुनः चकल्लस।
आरोपों से आज न निकलेगा कोई हल,
बेहतर होगा शांत रहें अब ममता-सिब्बल।
- ओमप्रकाश तिवारी

प्रदीप शुक्ला
स्थानीय संपादक, झारखंड

झारखंड डायरी

ये तब्लीगी और इनकी जमात

तब्लीगी जमात को लेकर समाज में जो कुछ फैल रहा है, और वह भविष्य में कितना घातक होने वाला है, इसे दो घटनाओं से समझ सकते हैं। पहला रांची का है। लालपुर सब्जी मंडी गए हमारे ही एक साथी सिर्फ तीस रुपये किलो कटहल इसलिए नहीं खरीदते हैं, क्योंकि विक्रेता उन्हें एक संप्रदाय विशेष का लगा। वह मास्क हटाकर बार-बार थूक भी रहा था। ठीक बगल की दुकान से उन्होंने कटहल खरीदा वह भी पचास रुपये में। दूसरी घटना गुमला जिले के सिसई की है जहां यह बात फैल गई कि तब्लीगी जमात के लोग घूम-घूम कर कुएं में थूक रहे हैं और पूरे इलाके को संक्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अफवाह तनाव के बाद सांप्रदायिक संघर्ष में तब्दील हो गई। इसमें एक की जान चली गई और दो की हालत गंभीर हुई है।

इन्हें यदि सिर्फ बानगी भर मान लें तो यह तो समझ ही सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम सामाजिक दुराव की किन दिक्कतों से दो-चार होने वाले हैं। और इसके लिए कोई जिम्मेदार होगा तो सिर्फ और सिर्फ तब्लीगी जमात। समाज में ऐसी धारणा गहरी पैठ बनाती जा रही है कि कोरोना जैसी आपदा में तब्लीगी जमात से जुड़े लोगों का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना रहा है। झारखंड में बुधवार तक चौदह मामले सामने आ हो चुके हैं, इनमें से एक कोरोना पीड़ित की मौत भी हो गई है। इन चौदह में से बारह मामले सीधे-सीधे तब्लीगी से जुड़े पाए गए हैं। प्रशासन लगातार तब्लीगी जमात से जुड़े लोगों से आग्रह कर रहा है कि वह सामने आएं। बावजूद इसके स्वयं अब तक कोई सामने नहीं आया है। छापों में जरूर मदरसों, मस्जिदों और यहां तक घरों में कई तब्लीगी पाए गए हैं जिन्हें क्वारंटाइन किया जा चुका है। रांची का हिंदपीढ़ी इलाका जहां सबसे पहला मामला आया था उसे पूरी तरह सील किया जा चुका है। रांची के सभी सात मामले यहीं से जुड़े हुए हैं। बोकारो में भी जो केस सामने आए वे भी तब्लीगी से जुड़े हुए हैं। सवाल उठ रहा है कि मरकज से लौटे लोग सामने आकर अपनी, अपने परिजनों और प्रशासन की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं-डॉक्टरों का सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? यही सवाल पूरे समाज को खाए जा रहा है और बड़ी चिंता का विषय बन गया है।

राज्य सरकार महसूस कर रही है कि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। इस बाबत पुलिस-प्रशासन को चौकन्ना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपील कर चुके हैं कि ऐसे लोगों को छुपने की जरूरत नहीं है, वे सामने आएं। धनबाद में तब्लीगी जमात के दस इंडोनेशियाई समेत बारह लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इन पर टूरिस्ट वीजा पर गोविंदपुर में आने की सूचना पुलिस को नहीं देने का आरोप लगाया गया है। राज्य में इनके खिलाफ यह पहली कार्रवाई है। आने वाले दिनों में ऐसे कई और मामले दर्ज हो सकते हैं। फिलहाल तब्लीगी जमात ने पूरे राज्य को परेशानी में तो डाल ही दिया है। इस बीच चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, क्योंकि राज्य का स्वास्थ्य ढांचा इतना मजबूत नहीं है कि यदि बड़ी संख्या में लोग इससे पीड़ित होते हैं तो उससे निपटा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 13 अप्रैल को लॉकडाउन बढ़ाने अथवा खोलने पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि हेमंत सोरेन 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री के साथ संवाद में इसे बढ़ाने की अपील कर सकते हैं।

राज्य में कम जांच होने पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। केंद्र से लगातार जांच किट मांगी जा रही है। हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को निर्देशित किया है कि राज्य को जरूरत के हिसाब से वेंटिलेटर, जांच किट और पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सहित अन्य जरूरी स्वास्थ्य उपकरण मुहैया करवाएं। मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलकर भी इसकी गुहार लगा चुके हैं। इस बीच राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से पांच हजार जांच किट मंगवाई हैं। उम्मीद है जल्द ही जांच की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। यह जरूरी भी है, क्योंकि राज्य में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से मजदूर भी इस बीच आए हैं। ये सभी गांवों में चले गए हैं। बेशक सरकार यह दावा कर रही है कि पंचायत भवनों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन वहां नाममात्र भी मजदूर नहीं हैं। जिन गांवों के लोग जागरूक थे वहां जरूर बाहर से आने वाले मजदूर चौदह दिन क्वारंटाइन में रहने के बाद अपने घर में घुस पा रहे हैं। संकट विकट है। शासन-प्रशासन के साथ-साथ पूरे समाज को एकजुट होकर इससे मुकाबला करना होगा।

मंथन

कमलेश कुमार सिंह
स्वतंत्र पत्रकार

सोशल मीडिया पर भी वायरल होता कोरोना!

कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में फैल जाने और भयाक्रांत करने के दौर में सोशल मीडिया पर भी यह वायरल है, लेकिन अधिकांश संदेशों, सूचनाओं में सच्चाई कम, भ्रामकता ज्यादा है जिसे हमें समझना चाहिए

आज हम लॉकडाउन, क्वारंटाइन और शारीरिक दूरी के इस आपातकाल में एक-दूसरे से अलग होकर भी आपस में जुड़े हैं। ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से आज हम आपस में आसानी से संपर्क कायम कर पा रहे हैं। हालांकि इन दिनों सोशल मीडिया के हरेक प्लेटफॉर्म पर कोरोना वायरस भी काफी वायरल है। वाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों ने कोरोना वायरस संबंधी समाचार और सूचना साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन साथ ही अफवाहों और गलत सूचनाओं को प्रसारित करने में भी।

चीन से वायरस के आने संबंधी शुरुआती सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से ही सामने आई। हालांकि चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे वीवो और वीचैट पर ऐसी सूचनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बावजूद वहां के लोगों ने पुलिस के साथ चूहे-बिल्ली का खेल खेलते हुए सूचनाओं की झड़ी लगा दी। यह वायरस ज्यों-ज्यों फैलता गया, त्यों-त्यों सोशल मीडिया पर वायरल भी होता गया। सरकार द्वारा जब कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान शुरू करने की बात हो रही थी, सोशल मीडिया पर हाथ धोने और बचाव की अन्य जानकारियां वायरल हो चुकी थीं।

दूसरी ओर सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस संबंधी अफवाहें और गलत सूचनाएं भी खूब वायरल हुईं। अफवाहों और गलत सूचनाओं के कारण देश में राशन की खरीदारी एवं जमाखोरी के लिए होड़ सी मच गई। वैसे भी संकट के समय भय का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में हर नई सूचना पर लोगों को जल्द विश्वास हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने भी कहा है कि हम सिर्फ कोरोना महामारी से ही नहीं लड़ रहे, बल्कि सूचनाओं की महामारी से भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के इस युग में कोरोना वायरस जैसी महामारी पहली बार सामने आई हो। पिछले एक दशक में कम से कम तीन महामारी स्वाइन फ्लू, इबोला और जीका जैसे संक्रमण वाले वायरस आए। एक दशक पहले सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन ऑनलाइन सूचना प्रदान करने के लिए अच्छी तरह तैयार नहीं थे, जबकि लोग सोशल मीडिया का उपयोग सूचना प्राप्त करने के लिए करते थे, जहां तब अविश्वसनीय या गैर आधिकारिक स्रोतों का बोलबाला था।

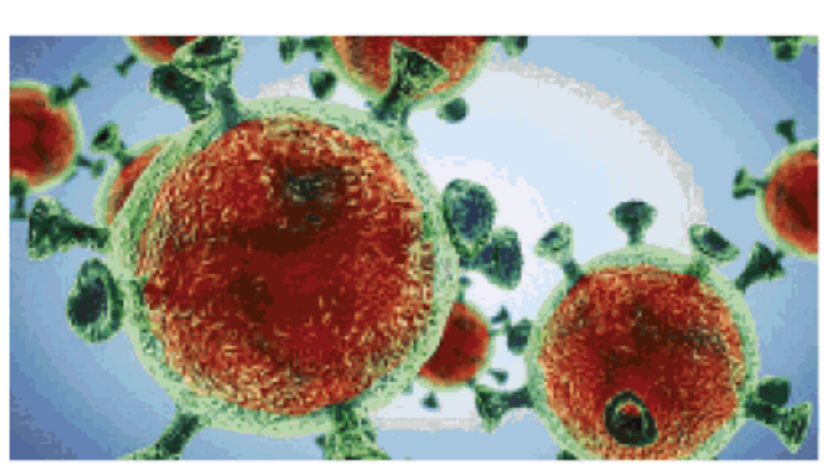

पिछले कुछ वर्षों में लोगों में इस बात की जागरूकता आई है कि क्या अफवाह है यानी कौन सी सूचना गलत है, और कौन सी सही है। फेक न्यूज को लेकर लोगों में सतर्कता आई है। वर्ष 2009 में एच1एन1 को लेकर सरकारी सूचना तंत्र को याद कीजिए, और अब कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया के जरिये जागरूकता एवं सूचना अभियान में अंतर स्पष्ट नजर आएगा। हालांकि इसका यह कतई मतलब नहीं है कि सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं के बीच कोरोना वायरस को लेकर भ्रामक, अफवाह एवं गलत सूचनाओं का आदान-प्रदान नहीं हो रहा है। लेकिन साथ ही सोशल मीडिया वेबसाइटें प्रामाणिक तौर पर ऐसे संदेशों के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। वस्तुतः अफवाह, गलत सूचना वाले संदेशों को छांटने-छानने की प्रणाली सटीक नहीं बन पाई है। बीते माह ही फेसबुक, गुगल, ट्विटर, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट रेडिट और यूट्यूब जैसे महत्वपूर्ण संगठनों ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि वे सभी कोविड-19 से निपटने के प्रयासों पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वे संयुक्त रूप से इस वायरस के बारे में भ्रामक और गलत सूचनाओं का मुकाबला करते हुए लाखों लोगों के आपस में जुड़े रहने में मदद कर रहे हैं। साथ ही अपने प्लेटफॉर्मों पर आधिकारिक सामग्री को बढ़ाते हुए और दुनिया भर में सरकारी स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण अपडेट साझा कर रहे हैं। जैसे ही कोरोना वायरस ट्रेंडिंग विषय बना, वैसे ही लोग सोशल मीडिया का उपयोग अपनी मानसिकता साधने में करने लगे। लेकिन अब ऐसे लोगों को पकड़ा जाना शुरू हो गया है। मसलन एक नामचीन आइटी कंपनी के एक कर्मचारी ने कोरोना फैलाने को लेकर एक विवादास्पद संदेश प्रेषित किया। उसे न सिर्फ नौकरी से हाथ धोना पड़ा, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की गई है। दिल्ली हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई इसका पुख्ता उदाहरण हमारे सामने है।

भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से कहा है कि वे ऐसे लोगों के अकाउंट को हटा दें या डिलीट कर दें जो कोरोना वायरस को लेकर भ्रामक और गलत जानकारियां साझा कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में फेक न्यूज या गलत जानकारियां फैलाने के आरोप में कई लोगों पर पुलिस थानों में एफआइआर भी दर्ज की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब पुलिस टिक टॉक और शेयरचैट जैसे माध्यमों के जरिये मनोरंजक तरीके से कोरोना पर जानकारी साझा कर रही है। फिलहाल कोरोना के कड़े इम्तिहान में सोशल मीडिया को गुजरना है।

कोरोना का नौकरी की पेशकश पर मामूली असर

कोलकाता : कोरोना के चलते इस समय देश के ज्यादातर बिजनेस स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए नौकरी हासिल करना और इंटर्नशिप करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आइआइएम कोलकाता का दावा इसके उलट है। उसने दावा किया है कि उसके यहां नौकरियों की पेशकश पर मामूली असर हुआ है। (राब्यू)

वेंटीलेटर, पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर की मांग पिछले एक माह में तेजी से बढ़ी है। एमएसएमई सेक्टर को इसके उत्पादन में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
– नितिन गडकरी
एमएसएमई मंत्री

सरकार के पास पूरे सालभर के लिए पर्याप्त खाद्यान्न : राम विलास पासवान

कोरोना महामारी को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से पैदा हुए विकट हालात से निपटने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कई बड़े फैसले लिए हैं। 130 करोड़ आबादी वाले देश की खाद्य सुरक्षा को महफूज रखने की जिम्मेदारी उठा रहा खाद्य मंत्रालय इन दिनों 24 घंटे काम कर रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता व खाद्य मंत्री राम विलास पासवान अपने मंत्रालय के आला अफसरों के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लगातार संपर्क में हैं। सरकारी स्टॉक का हवाला देते हुए पासवान ने कहा 'सरकार के पास पूरे साल की जरूरत के लिए पर्याप्त खाद्यान्न है।' जमाखोरी व कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इन्हीं मुद्दों पर हमारे राष्ट्रीय ब्यूरो के डिप्टी प्रमुख **सुरेंद्र प्रसाद सिंह** ने **राम विलास पासवान** से विस्तृत बातचीत की। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश...

साक्षात्कार

- एफसीआई से अनाज खरीदने की टेंडर प्रक्रिया समाप्त
- निर्धारित मूल्य पर कोई भी खरीद सकता है गेहूं व चावल
- पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में हर परिवार को तीन माह तक एक किलो दाल देने का प्रावधान

● **लॉकडाउन में सबके लिए अनाज देने का एलान किया गया है। क्या इतना अनाज सरकार के गोदामों में है?**

सरकार के पास पूरे साल के लिए खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक है। इस वक्त सरकारी गोदामों में 544 लाख टन अनाज है। इसमें 306 लाख टन चावल और 238 लाख टन गेहूं है। जबकि राशन प्रणाली के लिए हर महीने 60 लाख अनाज की जरूरत होती है। रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की बंपर पैदावार होने वाली है, जिसकी खरीद अगले पखवाड़े में चालू हो जाएगी।

● **सरकार की पांच किलो मुफ्त अनाज अगले तीन महीने तक देने की योजना में कितने अनाज की जरूरत होगी? राज्यों की ओर से कितना अनाज उठाया जा रहा है?**

देश की 81 करोड़ की आबादी को हर महीने अति रियायती दर पर गेहूं व चावल दिया जाता है। इसके अलावा लॉकडाउन के प्रभावों को कम करने के लिए सरकार ने अगले तीन महीने तक पांच किलो प्रत्येक व्यक्ति मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है। सभी राज्यों को अपने हिस्से का अनाज उठाने और उपभोक्ताओं को बांटने का निर्देश दिया गया है। लेकिन कुछ राज्य अनाज उठाने में अभी भी विलंब कर रहे हैं।

● **खुले बाजार में अनाज बेचने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?**

एफसीआइ से अनाज खरीदने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल कर दिया गया है। इसके तहत एफसीआइ ने टेंडर प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है, जिससे किसी भी निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान अथवा बड़े उपभोक्ता प्रतिष्ठान के साथ कोई भी संस्थान यहां से अनाज बेरोकटोक एक निश्चित मूल्य पर खरीद सकता है।

● **कुछ राज्यों ने गेहूं की जगह चावल की मांग की है। क्या चावल का इतना स्टॉक है?**

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 111 लाख टन चावल और 11 लाख टन गेहूं की जरूरत है। इसमें चार राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ ने चावल की जगह गेहूं की मांग की है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई गेहूं की जगह अतिरिक्त चावल की मांग करता है तो सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है।

● **एफसीआइ से रोजाना कितना अनाज दूसरे राज्यों को भेजा जा रहा है। इसके लिए कितने श्रमिक कार्यरत हैं?**

निगम के कुल 70 से 80 हजार श्रमिक दिनरात काम कर रहे हैं। इनमें कांट्रैक्ट श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है। लॉकडाउन के लागू होने के बाद से अब तक 721 रेल रैक्स से 20 लाख टन से अधिक अनाज की ढुलाई हो चुकी है।

● **अनाज के साथ दाल देने का भी प्रावधान किया गया है। दालों की सप्लाई कौन कर रहा है?**

सरकारी एजेंसी नैफेड की ओर से दालों की सप्लाई की जानी है। इनमें अरहर को छोड़कर बाकी दालों को साबुत ही दिया जा सकता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रत्येक परिवार को अगले तीन महीने तक एक किलो दाल देने का प्रावधान किया गया है।

● **देश के कई हिस्सों से जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई की खबरें आ रही हैं। क्या सरकार ने इसके लिए कुछ सख्त प्रावधान किये हैं?**

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ाई की जा रही है। कोविड-19 के बचाव में मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग बढ़ गया है। इसीलिए इसे आवश्यक वस्तुओं की सूची में डाल दिया गया है। इनके मूल्य भी निर्धारित किए गए हैं। इससे अधिक मूल्य पर बेचने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीन-प्लाई मास्क का मूल्य 10 रुपये और 200 मिलीग्राम सैनिटाइजर का मूल्य एक सौ रुपये रखा गया है। राज्यों को महंगाई रोकने के लिए सख्त रुख अपनाने को कहा गया है।

● **सरकारी एजेंसियों की गेहूं खरीद की क्या तैयारी है?**

गेहूं उत्पादक सभी राज्य इसके लिए तैयार हैं। पंजाब और हरियाणा में गेहूं की खरीद तीन चरणों में करने की योजना है। किसानों और खेतिहर मजदूरों को लॉकडाउन से मुक्त कर दिया गया है। राज्य अपने स्तर से खरीद के कई विकल्पों पर तैयारी कर रहे हैं।

लॉकडाउन के बाद एमएसएमई के समक्ष नई चुनौती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लॉकडाउन के बाद मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट को फिर से चालू करने की कवायद में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम कंपनियां यानी एमएसएमई जुट गई हैं। लेकिन उन्हें कोरोना के बाद की परिस्थिति में मैन्यूफैक्चरिंग शुरू करना आसान नहीं लग रहा है। उद्यमियों ने बताया कि उनके समक्ष कुशल श्रमिकों की खोज से लेकर उन्हें यूनिट तक लाने-ले जाने, उनकी रोजाना स्तर पर स्क्रीनिंग, यूनिट में साफ-सफाई जैसी कई चुनौतियां आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या नकदी की आने वाली है क्योंकि पिछले दो महीने से बगैर कारोबार के ही उन्हें कर्मचारियों को वेतन देना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें कर्ज चुकाने की अवधि में मोहलत दी गई है, कर्ज पर लगने वाले ब्याज में कोई छूट नहीं दी गई है।

इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ऑफ इंडिया के चेयरमैन राजीव चावला ने बताया कि लॉकडाउन खुलने पर बिल्कुल बदली हुई परिस्थिति में काम शुरू करना होगा। यूनिट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना सबसे जरूरी होगा।

आरबीआइ ने कहा, सारे सुधारों को चुनौती दे रही कोरोना महामारी

मोनेटरी रिपोर्ट ▸ महंगाई और विकास दर का अनुमान लगाने से केंद्रीय बैंक का अभी तक परहेज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने गुरुवार को जारी मोनेटरी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना महामारी पिछले कई महीनों से चलाए जा रहे सभी आर्थिक सुधारों को चुनौती देती दिख रही है। आर्बीआइ के मुताबिक कोरोना आने से पहले तक भारतीय इकोनोमी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जबरदस्त रबी की फसल हुई थी और खाद्य उत्पादों की कीमतो में तेजी का रुख था जिससे संकेत मिल रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी। आरबीआइ के दबाव में ब्याज दरों में कटौती का फायदा बैंक ग्राहकों को देने लगे थे। सितंबर, 2019 में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का फायदा कारपोरेट सेक्टर पर दिखने लगा था जिसकी वजह से जीएसटी का संग्रह भी बढ़ने लगा था। लेकिन कोरोना महामारी ने इन सारी संभावनाओं पर पानी फेर दिया है।

फाइल

हालात यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में जो कमी हुई है, उसका भी मौजूदा स्थितियों में फायदा नहीं उठाया जा सकता।

वैसे तो कोविड-19 वायरस के प्रसार के बाद दुनिया की तमाम शोध एजेंसियां और आर्थिक थिंक टैंक ने एक स्वर में यह एलान कर दिया है कि इस महामारी की वजह से दुनिया संभवतः अभी तक की सबसे बड़ी मंदी की जाल में फंस चुकी है। आरबीआइ ने यह बात इतनी स्पष्टता से तो नहीं कही है लेकिन उसने भी माना है कि संकट बहुत बड़ा है। यही वजह है कि उसने अभी भी चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर या महंगाई दर का कोई अनुमान नहीं लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह निश्चित तौर पर कहा है कि कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन भारत की आर्थिक गतिविधियों पर बहुत ही ज्यादा असर डालेगा। आरबीआइ का कहना है कि आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाएंगे, यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कोविड-19 के बाद हालात कितनी तेजी से सामान्य होते हैं। लॉकडाउन जैसी स्थिति लंबा खींचने का उल्टा असर भी ज्यादा रहेगा। जितनी तेजी से हम आर्थिक गतिविधयों को सामान्य करेंगे उतनी ही तेजी से हम आर्थिक विकास की रफ्तार भी बढ़ा सकेंगे। आरबीआइ ने कहा है कि कोविड-19 को दुनिया के सामने एक काली छाया की तरफ लटकी रहेगी। महंगाई के बारे में आरबीआइ ने कहा है कि वैसे तो इसके बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है लेकिन लॉकडाउन की वजह से आपूर्ति प्रभावित होती है तो कुछ जरूरी उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। आरबीआइ ने जून को समाप्त तिमाही में महंगाई की दर 4.8 फीसद, सितंबर में समाप्त तिमाही में 4.7 फीसद और दिसंबर तिमाही में 2.7 फीसद रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि आरबीआइ ने यह भी कहा है कि यह अनुमान कोविड-19 के प्रसार के पहले के हालात में लगाया गया है। अभी किसी भी तरह का अनुमान लगाना काफी चुनौतीपूर्ण है। वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर का भी कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। संभवतः यह पहला मौका है कि केंद्रीय बैंक ने विकास दर या महंगाई के लिए कोई अनुमान नहीं लगाये हैं। सरकार की तरफ से सबसे पहले विकास दर का अनुमान आरबीआइ ही लगाता है।

बाजारों में 11 वर्षों की सबसे बड़ी साप्ताहिक तेजी

मुंबई, प्रेट्र : शेयर बाजारों में गुरुवार की उछाल ने पूरे सप्ताह को एक दशक से भी ज्यादा अरसे का सबसे अच्छा सप्ताह बना दिया। निवेशकों को इस सप्ताहांत तक दूसरे इकोनॉमिक बूस्टर डोज की उम्मीदों के चलते सेंसेक्स 1,265.66 अंक चढ़ गया और इस वजह से बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण शेयरों की वैल्यू 3.98 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। शुक्रवार को गुड फ्राइडे के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेंगे।

गुरुवार को बीएसई का 30-शेयरों वाला सेंसेक्स 1,265.66 अंक यानी 4.23 फीसद तेजी के साथ 31,159.62 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50-शेयरों वाला निफ्टी भी 363.15 अंक यानी 4.15 फीसद की बढ़त लेकर 9,111.90 के स्तर पर रहा। बीएसई के मिडकैप इंडेक्स में करीब साढ़े तीन फीसद और स्मॉलैकप इंडेक्स में तीन फीसद से ज्यादा तेजी दर्ज की गई। सभी सेक्टरों के सूचकांक बढ़त पर बंद हुए। निफ्टी के ऑटो इंडेक्स ने सर्वाधिक करीब 10.5 फीसद छलांग लगाई। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में लगभग छह फीसद और प्राइवेट बैंकों के इंडेक्स में करीब पांच फीसद तेजी दर्ज की गई। मेटल, फार्मा और मीडिया इंडेक्स ने भी 5 फीसद तक की बढ़त ली। बीएसई पर मदरसन सुमि के शेयर में 17.54 फीसद उछाल आया और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर ने 16.74 फीसद छलांग लगाई। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के शेयर में 13.34 फीसद और सिटी यूनियन बैंक के शेयर में पांच फीसद से ज्यादा उछाल आया। इसके अलावा मारुति सुजुकी, सिप्ला, टाइटन, टाटा मोटर्स, वेदांता, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयरों 14 फीसद तक तेजी दर्ज की गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में 3.5 फीसद गिरावट आई। डॉ. रेड्डीज, टेक महिंद्रा के शेयर भी गिरकर बंद हुए।

उछाल के कारण

बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजार जोरदार तेजी रही। इसका असर भारत समेत दुनियाभर के शेयर बाजारों पर नजर आया। यूरोप के बाजारों में बढ़त पर ट्रेडिंग शुरू हुई।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने यह भी कहा है वे कोरोना संकट के बाद अर्थव्यवस्था को तेजी से दोबारा खड़ी करना चाहते हैं।

मार्च में भारतीय बाजार से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक निकालने के बाद विदेशी निवेशक अप्रैल में खरीदारी करते दिखे हैं।

बाजार का रुझान मजबूत

निवेशकों को अगले इस सप्ताहांत तक दूसरे बूस्टर डोज की पूरी उम्मीद

विदेशी निवेशकों ने बीते दो सत्रों में किया 2,600 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश

निफ्टी 50 इंडेक्स के 43 शेयरों में तेजी दर्ज की गई और सात शेयरों में गिरावट

सेंसेक्स के 26 शेयर बढत पर बंद हुए, केवल चार शेयरों गिरावट दर्ज की गई

बीएसई पर 1,863 शेयरों में तेजी रही, 535 शेयरों की ट्रेडिंग में गिरावट

17 कंपनियों के शेयर अपने 52 हफ्तों के उच्च स्तर पर बंद हुए

38 कंपनियों के शेयर अपने 52 हफ्तों के सबसे निचले स्तर तक टूटे

इस हफ्ते सेंसेक्स 13 प्रतिशत चढ़ा

इस हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 13 प्रतिशत तेजी दर्ज की गई। ऑटोमोबाइल इंडेक्स ने 23 प्रतिशत से ज्यादा बढ़त ली और फार्मा इंडेक्स लगभग 20 प्रतिशत चढ़ा है। इस हफ्ते बैंक निफ्टी 15 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा और बीएसई के मिडकैप इंडेक्स में लगभग 11 प्रतिशत तेजी दर्ज की गई।

सदी की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी की ओर दुनिया : आइएमएफ

वाशिंगटन, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आइएमएफ को अंदेशा है कि इस वर्ष ग्लोबल इकोनॉमी पिछली एक सदी की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी के कुचक्र में पफंसने की ओर जाती दिख रही है। आइएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने गुरुवार को कहा कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष 170 से ज्यादा देशों की प्रति व्यक्ति आय में नकारात्मक वृद्धि होने की आशंका है। उनके मुताबिक कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष की ग्लोबल आर्थिक मंदी वर्ष 1929 की महामंदी के बाद सबसे खतरनाक हो सकती है।

आइएमएफ और वर्ल्ड बैंक की अगले सप्ताह महत्वपूर्ण बैठक से पहले 'संकट से मुकाबला : ग्लोबल इकोनॉमी की प्राथमिकताएं' विषय पर बोलते हुए जॉर्जिवा ने कहा कि इस वक्त दुनिया अपनी सबसे गंभीर चुनौती से जूझ रही है। कोविड-19 ने सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं पर जैसा वज्रपात किया है, वैसा हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उनके मुताबिक इस वायरस के चलते दसों हजार लोगों की जान जा चुकी है और इससे बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित है। गौरतलब है कि वर्ष 1929 की महामंदी 10 वर्षों तक रही थी।

भारत की विकास दर 4.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : एक तरफ जब वैश्विक एजेंसियां दुनियाभर की इकोनॉमी पर कोरोना को लेकर बड़ी चोट की बात कह रही हैं, संयुक्त राष्ट्र को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में भी भारतीय की अर्थव्यवस्था 4.8 प्रतिशत की दर से विकास करेगी। संस्था ने बीते वित्त वर्ष के लिए भारत के पांच प्रतिशत की दर से विकास करने का अनुमान लगाया था।

उपज बेचने को मंडी कानून में संशोधन करें राज्य : नरेंद्र तोमर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्र ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉकडाउन के चलते किसानों को राहत देने के लिए राज्यों को आगे आने को कहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों से चर्चा करते हुए वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मंडी कानून में संशोधन करने और मंडी टैक्स को फिलहाल स्थगित करने का अनुरोध किया है। उपज की खरीद को सहज बनाने के लिए मंडी के बाहर भी खरीद बिक्री की छूट दी जाए।

तोमर ने बताया कि आगामी खरीफ सीजन का तैयारी सम्मेलन निर्धारित 16 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ही होगा। इस दौरान खरीफ सीजन की फसलों की तैयारियों की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

केंद्र ने राज्यों से अपने मंडी कानून में उचित संशोधन करने को कहा है, ताकि किसानों को मंडी के बाहर कहीं भी अपनी उपज बेचने में सहूलियत हो। केंद्र ने अपनी ओर से हरसंभव मदद मुहैया कराने के प्रावधान किए हैं। इस दौरान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की संचालित मंडियों में लागू कानून में बदलाव करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से मौजूदा परिस्थितियों में मंडी टैक्स को स्थगित करने का भी आग्रह किया।

राज्यों के अनुरोध पर कृषि संबंधी कार्यों को 90 दिनों में पूरा कर लेने की समय-सीमा तय कर दी गई है। तोमर ने कृषि मंत्रियों से बातचीत में कोरोना वायरस संकट के दौर में खेती-किसानी के लिए हरसंभव राहत पहुंचाने पर जोर दिया।

कृषि मंत्री ने कहा कि सभी राज्य अपने स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर केंद्र के साथ लगातार समन्वय बनाने की कोशिश करें, ताकि कृषि उपज की बिक्री व अन्य गतिविधियों का संचालन करने में मदद मिल सके। केंद्रीय कंट्रोल रूम अपना कार्य सुचारु रुप से करने लगा है। अंतरराज्यीय परिवहन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया गया।

कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने लॉकडाउन से किसानों के लिए दी गई छूट व राज्यों को भेजे दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। केंद्र की छूट का उद्देश्य है कि कृषि उपज को मंडियों में लाने की जरूरत नहीं पड़े और वे परेशान न हो। वेयरहाउस से ही कृषि उपज की बिक्री सुविधाजनक तरीके से की जा सकती है। तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि लॉकडाउन के प्रारंभिक दौर में सब्जी मंडियों में सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा गया था।

दलहन-तिलहन की सरकारी खरीद को हर हाल में 30 अप्रैल तक पूरा कर लेने को कहा गया है। लेकिन राज्यों के अनुरोध पर अब इसकी समय सीमा 90 दिन कर दी गई है। तोमर ने कहा कि कोई किसान स्वयं सहायता समूह के माध्यम से होम डिलीवरी कर उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहते है तो इसकी छूट उन्हें दी जानी चाहिए। राज्यों को अपने मंडी कानून में इसके लिए संशोधन करने की जरूरत है। उन्होंने राज्यों से इस दौरान मंडी टैक्स में छूट देने का आग्रह किया है।

एफसीआई की खरीद–बिक्री प्रक्रिया हुई सरल

जागरण ब्यूरो नई दिल्ली

कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान खुले बाजार में खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति के लिए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम से अनाज खरीदने की शर्तों को सहज और सरल बना दिया है। टेंडर प्रक्रिया समाप्त कर सरकार ने अब गेहूं का भाव 21 रुपये और चावल का भाव 22 रुपये प्रति किलो निर्धारित कर दिया है।

यह फैसला गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले तीन मंत्रियों के समूह में लिया गया। मंत्री समूह में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन और उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्री राम विलास पासवान शामिल थे।

इस फैसले के बाद भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से कोई भी संस्था अथवा बड़ा उपभोक्ता गेहूं या चावल की मनमाफिक मात्रा में खरीद कर सकता है। यह फैसला लेने का उद्देश्य यह है की टेंडर प्रक्रिया के पालन और अन्य कई शर्तों के चलते अनाज की सप्लाई में विलंब होता था। प्रक्रिया को सरल बनाने से अब देश के किसी भी हिस्से में अनाज की सप्लाई करने में सहूलियत होगी। ढुलाई का दायित्व रेलवे से पूरा कराया जा सकता है।

लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न की बढ़ी मांग को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह जानकारी केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने जागरण से बातचीत ने दी। उन्होंने कहा कि देश में अनाज की कोई कमी नहीं है।

लॉकडाउन में विश्वसनीय सूचना का माध्यम बना एफएम रेडियो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

82 फीसद लोग एफएम रेडियो पर निर्भर, रोजाना 2.36 घंटे सुन रहे

- छह मेट्रो शहरों में की गई रिसर्च से सामने आई जानकारी

रेडियो हमेशा से ही लोगों का दोस्त रहा है। चाहे समय अच्छा हो या बुरा। कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान भी एफएम रेडियो लोगों का भरोसेमंद हमसफर साबित हो रहा है। यही वजह है कि 6 मेट्रो शहरों के 82 फीसद लोग विश्वसनीय सूचना के लिए एफएम रेडियो से जुड़े हुए हैं। यह जानकारी एजेड रिसर्च पीपीएल के हाल में किए गए अध्ययन में किया गया। यह अध्ययन एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स फॉर इंडिया (एआरओआई) की तरफ से करवाया गया था। अध्ययन 18 साल से ऊपर आयु के 3300 लोगों पर किया गया।

रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक सूचना पाने के माध्यम में रेडियो की विश्वसनीयता दूसरे नंबर पर पाई गई। सूचना पाने के लिए विश्वसनीय माध्यम में इंटरनेट पहले नंबर पर रहा। भारत में रेडियो के श्रोताओं की संख्या 5.1 करोड़ है। टेलीविजन देखने वालों की संख्या 5.6 करोड़ है तो सोशल मीडिया से 5.7 करोड़ लोग जुड़े हैं। रिसर्च में यह भी खुलासा हुआ कि घरों पर रेडियो सुनने वालों की संख्या में 22 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन के दौरान लोग प्रतिदिन 2.36 घंटे रेडियो सुन रहे हैं। यह अवधि पहले के मुकाबले 23 फीसद अधिक है। लोगों के बीच सूचना के लिए रेडियो की बढ़ती लोकप्रियता एवं विश्वसनीयता पर एआरओआई की अध्यक्ष अनुराधा प्रसाद ने कहा कि दर्शकों के लिहाज से हम टीवी की बराबरी करने वाले हैं। रेडियो सुनने के समय में 23 फीसद की बढ़ोतरी उत्साहजनक है।

रेडियो सिटी के सीईओ असित कुकियन ने कहा कि हाल की रिसर्च से पता चलता है कि रेडियो में स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों ही मुद्दों पर जागरूकता फैलाने की ताकत है। लाकडाउन के समय एफएम रेडियो ने फिर से यह साबित कर दिया है। रेडियो आसान माध्यम है और इस कारण इसकी पहुंच काफी अधिक लोगों के बीच हैं।

बिग एफएम के सीईओ अब्राहम थॉमस ने कहा कि रिसर्च की रिपोर्ट हमारी उम्मीद के अनुरूप है। रेडियो पर लोगों के बढ़ते विश्वास के साथ घरों में और मोबाइल पर रेडियो सुनने की बढ़ती आदत की वजह से लोगों के बीच रेडियो की पहुंच बढ़ी है। लॉकडाउन के दौरान रेडियो में प्रसारित होने वाले कंटेंट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। एचटी मीडिया लिमिटेड और नेक्स्ट मीडिया वर्क्स के रेडियो एंड इंटरटेनमेंट के सीईओ एच जैन के मुताबिकमहामारी फैलने के बाद इंटरटेनमेंट के माध्यम की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।

रामायण–महाभारत के सहारे दूरदर्शन आसमान पर

मुंबई, प्रेट्र : दूरदर्शन ने अपने उस सुनहरे दौर में वापसी कर ली है जब वही घर-घर में देखा जाने वाला टेलीविजन चैनल हुआ करता था। ब्राडकास्ट आडिएंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) ने गुरुवार को जो रिपोर्ट जारी की उसके मुताबिक दूरदर्शन रामायण और महाभारत जैसे बेहद लोकप्रिय सीरियलों के कारण पिछले हफ्ते दर्शकों की संख्या के लिहाज से सबसे आगे रहा। बार्क की यह रिपोर्ट तीन अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के लिए है। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह और शाम के बैंड में दूरदर्शन की व्यूअरशिप में 40000 फीसद तक की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि इसके बावजूद हुई है कि कई निजी ब्राडकास्टरों ने भी अपनी दर्शक संख्या में बढ़ोतरी दर्ज कराई है।

दूरदर्शन में हाल के दिनों में रामायण और महाभारत के साथ शक्तिमान और बुनियाद सरीखे सीरियलों की भी वापसी हुई है। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित 21 दिनों के लाकडाउन के दौरान रामायण और महाभारत सरीखे सीरियल लोगों को घरों में सीमित रहने में सहायता प्रदान की है। मोदी ने पिछले रविवार को नौ बजे नौ मिनट के लिए लाइटें बंद करने का आहान किया था। इसके चलते इस टाइम स्लाट में 2015 के बाद से सबसे कम व्यूअरशिप दर्ज की गई। बार्क के मुताबिक ओवरआल टीवी व्यूअरशिप में पिछले सप्ताह के मुकाबले चार प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह पहले के मुकाबले 43 प्रतिशत ज्यादा है।

वर्क फ्रॉम होम के चलते इंटरनेट स्पीड पर पड़ रहा भारी असर

- फिक्स्ड ब्रॉडबैंड और मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत मार्च में दो–दो पायदान खिसका

नई दिल्ली, एजेंसियां : कोरोना संकट से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते कारोबारी जगत का बड़ा हिस्सा अपने-अपने घरों से ऑफिस के काम निपटा रहा है। इसके चलते पिछले कुछ समय के दौरान इंटरनेट स्पीड पर बड़ा असर पड़ा है।

ग्लोबल इंटरनेट स्पीड का रिकॉर्ड रखने वाली कंपनी ओक्ला ने इस वर्ष मार्च के लिए जो स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स किया है, उसके मुताबिक फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके साथ ही औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड भी 1.68 एमबीपीएस घट गई है। ओक्ला के मुताबिक पिछले महीने की फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड के लिहाज से भारत दो पायदान खिसककर 71वें स्थान पर चला गया है। वहीं, मोबाइल ब्रॉडबैंड के मामले में भी भारत दो पायदान पिछड़कर 130वें स्थान पर चला गया है।

इस बारे में ओक्ला के सीईओ डग सटल्स ने कहा कि भारत में इस वर्ष फरवरी से ही इंटरनेट स्पीड में कमी दिख रही है। इस वर्ष जनवरी में औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड 41.48 एमबीपीएस थी, जो फरवरी में 39.65 एमबीपीएस और मार्च में 35.98 एमबीपीएस रह गई। सटल्स के मुताबिक जहां तक औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड का सवाल है, तो यह फरवरी के 11.83 एमबीपीएस से घटकर मार्च में 10.15 एमबीपीएस रह गई। ओक्ला सीईओ का कहना था कि लॉकडाउन के चलते भारत में पेशेवरों का बड़ा वर्ग इस वक्त घर से काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में इंटरनेट स्पीड में कमी आना लाजिमी है।